# वार्षिक रिपोर्ट

## 1999-2000

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली - 110016

# वार्षिक रिपोर्ट
# 1999-2000

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली- 110016

300 प्रतियां

© राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, 2001

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के लिए कुलसचिव, नीपा द्वारा प्रकाशित तथा प्रदीप आर्ट प्रेस, 36 अधचीनी, श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली-110017 में लेजर टाइप सेट होकर, तारा आर्ट प्रेस प्रा० लि० बी–4, हंस भवन, बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 में नीपा के प्रकाशन एकक द्वारा मुद्रित।

# विषय सूची

**अध्याय**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | विहंगावलोकन | 1 |
| 2. | प्रशिक्षण | 9 |
| 3. | अनुसंधान और प्रकाशन | 21 |
| 4. | पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र और अकादमिक समर्थन प्रणाली | 53 |
| 5. | संगठन, प्रशासन और वित्त | 59 |

**अनुलग्नक**

| | | |
|---|---|---|
| I. | प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/संगोष्ठी | 64 |
| II. | संकाय का अकादमिक योगदान | 70 |

**परिशिष्ट**

| | | |
|---|---|---|
| I. | नीपा परिषद के सदस्य | 98 |
| II. | नीपा कार्यकारी समिति के सदस्य | 102 |
| III. | वित्त समिति के सदस्य | 104 |
| IV. | योजना और कार्यक्रम समिति के सदस्य | 105 |
| V. | संकाय तथा प्रशासनिक स्टाफ | 107 |
| VI. | वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट | 109 |

# मिशन और उद्देश्य

- शैक्षिक योजना और प्रशासन में उत्कृष्टता का ऐसा राष्ट्रीय केंद्र विकसित करना जो योजना और प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाए और इसके लिए अध्ययन, नए विचारों और तकनीकों के सृजन का रास्ता अपनाए तथा कार्यनीतिक समूहों के साथ विचार–विमर्श कर और प्रशिक्षण के माध्यम से इनका प्रचार–प्रसार करे;
- केंद्र, राज्यों और संघ राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ शिक्षाधिकारियों के लिए सेवा–पूर्व और सेवाकालीन अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, बैठकों संगोष्ठियों तथा परिचय–सत्रों का आयोजन करना;
- महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र से संबद्ध प्रशासकों के लिए अनुस्थापन और प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना;
- संस्थान के समान कार्यों से संबद्ध संस्थाओं का नेटवर्क विकसित करना और ऐसी समर्थनकारी तथा साहयोगिक भूमिका अदा करना जिससे राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और प्रादेशिक क्षेत्रों का क्रमिक विकास हो सके;
- केंद्र और राज्य सरकारों में शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी नीति–निर्माण से जुड़े विधिकर्ताओं समेत राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तियों के लिए अनुस्थापन अभिविन्यास कार्यक्रम, संगोष्ठी और सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करना;
- शैक्षिक योजना और प्रशासन के विभिन्न पक्षों पर शोधकार्य करना उन्हें सहायता और प्रोत्साहन देना और उनका समन्वय करना, इनमें भारत के विभिन्न राज्यों और अन्य देशों में प्रयुक्त योजनाकारी तकनीकों और प्रशासनिक कार्यप्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन भी शामिल हैं;
- शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्मिकों, संस्थानों और एजेंसियों का अकादमिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन करना;
- राज्य सरकारों और शिक्षा संस्थाओं के अनुरोध पर सलाहाकारी सेवाएं प्रदान करना;
- शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार कार्य से संबंधित विचारों और सूचनाओं के लिए वितरण–केंद्र के रूप में कार्य करना;
- इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आलेखों, पत्रिकाओं और पुस्तकों की तैयारी, मुद्रण और प्रकाशन और विशेष रूप से शैक्षिक योजना और प्रशासन पर पत्रिका का प्रकाशन करना;
- इन उद्देश्यों की अधिकाधिक पूर्ति के लिए भारत और विदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय प्रबंध और प्रशासन के क्षेत्र से जुड़े संस्थानों के साथ सहयोग करना;
- अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति और अकादमिक प्रोत्साहनवृत्ति प्रदान करना;
- शैक्षिक योजना और प्रशासन से जुड़े विख्यात शिक्षाविदों को मानद अध्येतावृत्ति प्रदान करना; और
- अन्य देशों और विशेष रूप से एशियाई देशों के अनुरोध पर शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना तथा ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन में उनका सहयोग करना।

# अध्याय 1

## विहंगावलोकन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) पिछले साढ़े तीन दशकों से शिक्षा की योजना और प्रशासन के क्षेत्र में एक शीर्षस्थ संस्थान के रूप में कार्य करता आ रहा है। 1962 में अपनी स्थापना के बाद, पहले दस वर्षों में यह, यूनेस्को और भारत सरकार के बीच एक समझौते के आधार पर, एशिया प्रशांत क्षेत्र में शैक्षिक योजनाकर्मियों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए यूनेस्को के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में काम करता रहा। पहली अप्रैल 1965 को इसका नाम बदलकर एशियाई शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान कर दिया गया। यूनेस्को से समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद और कोठारी आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने यूनेस्को केंद्र की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इस तरह 1970 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में शैक्षिक योजनाकर्मियों और प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय स्टॉफ कालेज की स्थापना हुई। शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करना और इस क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ अनुभव और विशेषज्ञता का आदान–प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। 1979 में संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) कर दिया गया।

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थान ने अपने अकादमिक कार्यक्रमों को चार विषयवार एककों में बाँटा है : (1) योजना, (2) प्रशासन; (3) वित्त, और (4) नीति। शैक्षिक स्तर के दो एकक हैं: (1) विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक, तथा (2) उच्च शिक्षा एकक। साथ में क्षेत्रीय स्तर के दो एकक भी हैं : (1) प्रादेशिक प्रणाली एकक, और (2) अंतर्राष्ट्रीय एकक। वर्ष 1995 में स्थापित संक्रियात्मक अनुसंधान और प्रणाली प्रबंधन एकक, प्रणाली प्रबंधन के विभिन्न मुद्दों से संबंधित कार्य से संबद्ध है। पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र, प्रकाशन एकक, हिंदी कक्ष, इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रसंस्करण एकक, रिप्रोग्राफी और मानचित्रण कक्ष के अलावा सामान्य प्रशासन और वित्त अनुभाग भी अकादमिक कार्यों में सहायता करते हैं। वर्ष 1999-2000 में संस्थान की प्रमुख गतिविधियां प्रस्तुत रिपोर्ट में दी गई हैं।

संस्थान की अकादमिक गतिविधियां तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटी गई हैं : (1) क्षमता के विकास के लिए प्रशिक्षण; (2) ज्ञान का सृजन और व्यवहार अर्थात अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान; और (3) ज्ञान का प्रसार, परामर्शकारी सेवा, व्यावसायिक सहायता और प्रकाशन।

## प्रशिक्षण

**कार्यक्रम के प्रमुख क्षेत्र :** प्रशिक्षण के क्षेत्र में खास जोर शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण सेवाओं की नेटवर्किंग पर और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्षेत्र, राज्य, स्थान और संस्था के स्तर पर प्रशिक्षण की क्षमताओं का विकास करना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों पर जोर दिया जाता है, जैसे – सभी के लिए शिक्षा, व्यष्टिस्तरीय योजना, जिला स्तर पर योजना, संस्था स्तर पर योजना और मूल्यांकन, अनौपचारिक और वयस्क शिक्षा, जिला शिक्षा–प्रशिक्षण संस्थानों की योजना और प्रबंधन, आदिवासी शिक्षा, विकेंद्रीकृत प्रशासन, लैंगिक प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा, कंप्यूटरों का अनुप्रयोग, और (i) अकादमिक स्टाफ कालेजों, (ii) स्वायत्त महाविद्यालयों की योजना और विकास, (iii) उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता और प्रासंगिकता लाने के लिए योजना।

**विस्तार :** संस्थान ने इस साल 41 कार्यक्रमों का आयोजन किया। इनमें भारत में विभिन्न भागों से 1303 और दुनिया के 36 देशों तथा 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से 89 भागीदारों को भाग लेने का अवसर मिला।

**प्रशिक्षण सामग्री :** क्षेत्र, राज्य और राष्ट्र के स्तर पर क्षमता के विकास के लिए संस्थान ने शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में स्वशिक्षा माड्यूल, आलेख और सांख्यिकीय आंकड़ों की रिपोर्टें तैयार की। संकाय ने हरेक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विभिन्न स्रोतों के आधार पर, कार्यक्रमों के विषयों पर पठन सामग्री तैयार की जो भागीदारों को उपलब्ध कराई गई।

**प्रशिक्षण की पद्धति :** प्रशिक्षण के सभी कार्यक्रमों का स्वरूप अंतःशास्त्रीय है। कार्यक्रमों में व्यावहारिक और सामूहिक कार्य, केस अध्ययन और संगोष्ठियां शामिल हैं। कंप्यूटरों, फिल्मों, वीडियो और ओवरहेड प्रोजेक्टर जैसी सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके प्रशिक्षण में प्रस्तुतियों को समृद्ध बनाया जाता है। आवश्यकता के अनुसार भागीदारों को क्षेत्रों के दौरों पर ले जाया जाता है।

**मूल्यांकन :** प्रशिक्षण के हर कार्यक्रम में मूल्यांकन भी शामिल होता है। 6 माह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा जैसे लंबी अवधि वाले कार्यक्रमों में मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है। इन कार्यक्रमों के भागीदारों को डिप्लोमा के लिए पाठ्यचर्यात्मक कार्यों के अलावा लघुप्रबंध लिखने होते हैं।

## अनुसंधान

अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान संस्थान के महत्वपूर्ण कार्यकलाप हैं। कोई भी नया कार्यक्रम आरंभ करने से पहले प्रायोगिक या गहन अध्ययन किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान अक्सर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल विषयों पर कराए जाते हैं। अनुसंधान कार्यों में उन पक्षों पर जोर दिया जाता है जो शैक्षिक योजना, प्रशासन और नीति से संबंधित हों। शैक्षिक योजना और प्रशासन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान के इच्छुक विद्वानों को शोध परियोजनाओं के लिए धन देकर भी संस्थान अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है।

इस साल 20 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी हुईं। 15 परियोजनाएं जारी थीं। तीन नई परियोजना अध्ययनों की मंजूरी दी गई।

## परामर्शकारी और व्यावसायिक सहयोग

संस्थान के संकाय सदस्यों ने राष्ट्र, राज्य और संस्था के स्तर के संगठनों को तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी परामर्श और वृत्तिक सहयोग प्रदान किया। मिसाल के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्यों के शिक्षा विभागों, राज्य उच्च शिक्षा परिषदों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, राज्य शैक्षिक प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थानों को तथा यूनेस्को, विश्व बैंक और सी आई डी ए जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को परामर्शकारी और वृत्तिक सहयोग दिया गया।

## सूचनाओं का प्रसार

**प्रकाशन :** संस्थान नियमित रूप से शोध अध्ययनों और दो पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है। *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन* अंग्रेजी पत्रिका और *परिप्रेक्ष्य* हिंदी पत्रिका है। एक अर्धवार्षिक एनट्रिप (एशियन नेटवर्क आफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन एजुकेशनल प्लानिंग) न्यूज़ लेटर का प्रकाशन भी किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष में संस्थान ने 'बेस्ट प्रैक्टिसेज इन हायर एजुकेशन' पर शृंखला निकालनी आरम्भ की और अकादमिक रिनव्यल लिंकिंग एजुकेशन एण्ड एम्पलायमेंट शृंखला का पहला अंक निकाला। समीक्षाधीन वर्ष में पांच पुस्तकें, एक रिपोर्ट, लर्निंग द ट्रेज़र विदिन प्रकाशित की गई। हिंदी और अंग्रेजी जर्नल के तीन–तीन अंक तथा एनट्रीप न्यूज़ लेटर के दो अंक प्रकाशित किये गये। इसके अतिरिक्त कई मिमियोग्राफ और अनुसंधान आलेख भी प्रकशित किये गये।

## अकादमिक और सहायक एकक

संस्थान के अकादमिक कार्यक्रम नौ अकादमिक एककों द्वारा चलाए जाते हैं। इन अकादमिक और सहायक एककों का संक्षिप्त वितरण नीचे प्रस्तुत है :

### अकादमिक एकक

**शैक्षिक योजना एकक :** आज हम केंद्रीकृत की जगह विकेंद्रीकृत योजनाओं पर जोर दे रहे हैं। योजना एकक में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श का केंद्र भी बदला है। फिलहाल, हमारा मुख्य प्रयास है संस्था, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर योजना के आगतों, प्रक्रियाओं और

उत्पादों का एकीकरण करना। अर्थ व्यवस्था का उदारीकरण आरंभ होने के बाद अब परंपरागत अर्थों में व्यापक योजना की जगह कार्यनीतिक, सांकेतिक योजना पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा के अलावा सामाजिक सुरक्षातंत्र, योजना के सिद्धांत और व्यवहार के एक नए क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है। यह एकक अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श के कार्यक्रम चलाता है।

**शैक्षिक प्रशासन एकक :** यह एकक अपने विभिन्न प्रशिक्षण, अनुसंधान और अन्य कार्यक्रमों के द्वारा संस्था और उससे ऊपर के स्तर के प्रशासकों की क्षमताएं विकसित करने के प्रयास करता है। देश भर में आज 80,000 से अधिक विद्यालय हैं, इसलिए यह एकक और अधिक संख्या में विद्यालयों तक पहुंचने के लिए नेटवर्किंग के द्वारा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देता आया है। यह विशेष प्रकार की संस्थाओं, जैसे– रेलवे विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, आश्रम विद्यालयों आदि की जरूरतें भी पूरी करता है। शैक्षिक प्रशासन की व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए यह एकक शैक्षिक प्रशासकों में आवश्यक प्रबंध–कौशल के विकास के प्रयास करता है ताकि वे शैक्षिक विकास की नई मांगों और चुनौतियों का सामना कर सकें।

**शैक्षिक वित्त एकक :** नई आर्थिक स्थितियों का शिक्षा के बजटों पर भारी दबाव पड़ रहा है। शिक्षा व्यवस्था के लिए संसाधन संबंधी आवश्यकताएं तेजी से बढ़ रही हैं, जबकि उनकी उपलब्धता सीमित है और इस तरह दोनों के बीच का अंतर बढ़ रहा है। जरूरत ऐसे कारगर तरीके निकालने की है कि संसाधनों का आवंटन, सरकारी और गैर–सरकारी संसाधनों की लामबंदी और उनका अच्छा उपयोग किया जा सके। इस तरह शैक्षिक वित्त का कारगर प्रबंध आज अत्यधिक महत्व का विषय है।

यह एकक इसी के अनुसार अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श तथा राज्यों के शिक्षा विभागों और विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारियों की क्षमताओं के विकास के लिए प्रयासरत है। यह उन्हें शैक्षिक वित्त संबंधी नवीनतम विकासक्रमों और प्रवृत्तियों का परिचय देता है और संसाधनों के आवंटन, लामबंदी और उपयोग समेत वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विधियों और तकनीकों की जानकारी भी देता है।

**शैक्षिक नीति एकक :** यह एकक शैक्षिक नीतियों का निर्धारण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर देता है। यह शैक्षिक नीति के पेचीदा मुद्दों पर अनुसंधान और विचारविमर्श की पहल करता है। यह राष्ट्रीय नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन करता है। शिक्षा में समता और उसकी मांग के सृजन से जुड़े प्रश्नों पर उसका खास जोर होता है।

इस वर्ष इस एकक की गतिविधियां मुख्यतः दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा की योजना और प्रबंध, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास, विकेंद्रित योजना और समुदाय की भागीदारी पर केंद्रित रही हैं।

**विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक :** जिला शिक्षा अधिकारियों, वयस्क और अनौपचारिक

शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय अधिकारियों तथा विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रशासन से जुड़े अन्य अधिकारियों की क्षमता विकास इस एकक का केंद्र बिन्दु रहा है। यह विद्यालयों और अनौपचारिक शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मुद्दों को उठाता है तथा उनके समाधान की वैकल्पिक कार्यनीतियां विकसित करने के प्रयास करता है। यह प्रमुख अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उनकी व्यावसायिक योग्यता/कौशल बढ़ाने के प्रयास करता है। यह एकक अनुसंधान परियोजनाएं चलाकर विद्यालय व्यवस्था की कारगर योजना और प्रबंध के बारे में उनके ज्ञान वृद्धि के प्रयास करता है। यह एकक विद्यालय शिक्षा के प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्रों और योजनाओं पर जोर देता है।

यह एकक अनुसंधान कार्य भी करता है तथा गुणवत्ता सुधार के लिए यह विद्यालय शिक्षा की योजना और प्रबंध संबंधी परामर्श भी प्रदान करता है।

**उच्च शिक्षा एकक :** उच्च शिक्षा के विकास की भविष्यमुखी योजना और प्रबंध के लिए यह एकक एक मंच प्रदान करता है। इसके लिए यह परामर्श, अनुसंधान और प्रशिक्षण की गतिविधियां चलाता है और जिन क्षेत्रों में आवश्यक हो, उनमें संस्था, राज्य और केंद्र स्तर के नीतिनिर्माताओं, योजनाकारों, प्रशासकों और सहायक कार्मिकों को एक मंच पर लाता है। गुणवत्ता, समता, उत्कृष्टता, प्रासंगिकता, स्वायत्तता, जबावदेही, और प्रत्यायन को बढ़ावा देने पर इस एकक का खास जोर रहा है। यह उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंध संबंधी प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श के द्वारा मूल्यांकन, आत्म विकास और संस्थागत विकास तथा स्टाफ के विकास पर जोर देता है। 'प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण' के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करके तथा साथ ही महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों, अकादमिक स्टाफ कालेजों के निदेशकों और उच्च शिक्षा निदेशकों की क्षमता विकास के कार्यक्रम चलाकर योजना और प्रबंध की क्षमताएं बढ़ाना इस एकक के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य है। यह केंद्र, राज्य, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर के अकादमिक और गैर–अकादमिक संकायों की क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रम भी चलाता है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा उनका अनुस्थापन करता है, नीतियों, कार्यक्रमों और कार्रवाई योजनाओं से संबंधित नवीनतम विकासक्रमों से उन्हें परिचित कराता है और भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं की योजना और प्रबंध की आधुनिक तकनीकों से उन्हें परिपूर्ण करता है।

इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, यह एकक सभी स्तरों पर कार्यरत योजनाकर्मियों और प्रशासकों की क्षमताएं विकसित करने के अलावा अनुसंधान और परामर्श के कार्य भी करता है।

**प्रादेशिक प्रणाली एकक :** इस एकक के प्रमुख केन्द्र बिन्दु इस प्रकार हैं : सभी के लिए शिक्षा के संदर्भ में विकेंद्रित और व्यष्टिस्तरीय योजना, संस्थागत योजना और मूल्यांकन, शैक्षिक कार्यक्रमों की निगरानी और उनका मूल्यांकन तथा प्रादेशिक स्तरों पर शिक्षा के सूचकों का विकास। 'सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा की निगरानी के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण', दूसरा 'अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण' और 'विद्यालय-मानचित्रण' इस एकक के प्रमुख राष्ट्रस्तरीय अध्ययन रहे हैं। इसमें केंद्र द्वारा प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा योजनाओं के संदर्भ में देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों के मूल्यांकन अनुसंधान को आधार बनाकर देश में

अनौपचारिक शिक्षा के मूल्यांकन पर एक विस्तृत रिपोर्ट का प्रकाशन भी किया गया है। इस एकक ने राज्य सरकारों के सहयोग से जिला शिक्षा–प्रशिक्षण संस्थानों में अनेक क्षेत्र–आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है।

**अंतर्राष्ट्रीय एकक :** विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान के द्वारा खासकर विकासशील देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझदारी की भावना को बढ़ावा देना अंतर्राष्ट्रीय एकक का प्रमुख उद्देश्य है। इस मकसद से यह एकक मानव संसाधन विकास के अहम विषयों और मुद्दों पर संगोष्ठियों और बैठकों का आयोजन करता है। विकासशील देशों के शैक्षिक योजनाकर्मियों और प्रशासकों के लिए दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना इसका प्रमुख कार्यकलाप है। इस कार्यक्रम में एक ओर शिक्षा की संरचनाओं और प्रक्रियाओं, व्यष्टिस्तरीय, मध्यस्तरीय और समष्टिस्तरीय योजनाओं के देशीकरण पर और दूसरी तरफ शैक्षिक पर्यवेक्षण, प्रशासन, प्रबंध और नेतृत्व पर जोर दिया जाता है। यह एकक विभिन्न देशों के आग्रह पर पहले से निरूपित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक शिक्षाशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और परामर्श की सेवाएं भी प्रदान करता है।

**संक्रियात्मक अनुसंधान और प्रणाली प्रबंधन एकक :** इस एकक का गठन नीपा समीक्षा समिति की सिफारिश पर अक्टूबर 1995 में किया गया। यह एकक प्रणाली स्तर पर प्रबंध के अनेक मुद्दों को उठाता है। इनमें क्रियागत (लाजिस्टिक) प्रबंध, सूचना प्रणालियां, नियंत्रण की प्रणालियां, कंप्यूटर के व्यवहार, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, परियोजनाओं का निरूपण, निगरानी और क्रियान्वयन, निर्णय सहायता प्रणालियां आदि शामिल हैं। यह एकक विशेष रूप से राज्य/जिला स्तर के उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर के उपयोग की क्षमताओं के विकास पर तथा सूचना प्रणालियों के विकास और क्रियान्वयन के संबंध में पेशेवर स्टाफ के प्रशिक्षण पर जोर देता है। यह एकक इन दिनों जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली के निरूपण और क्रियान्वयन में तकनीकी और वृत्तिक सहयोग प्रदान कर रहा है। यह अनुसंधान परियोजनाओं, प्रायोगिक परियोजनाओं, क्षेत्र–आधारित अध्ययनों, प्रमुख अध्ययनों और क्रियात्मक अनुसंधान में भी संलग्न है।

**अकादमिक सहायता एकक**

**पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र :** पुस्तकालय शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी नवीनतम और अधुनातन सामग्रियों का संग्रह करता है और उनके उपयोग की सुविधाएं प्रदान करता है। सूचनाओं का प्रसार प्रलेखन सूचना केंद्र द्वारा किया जाता है। पुस्तकालय के पास कोई 52620 पुस्तकें हैं और वह 380 पत्रिकाएं भी मंगाता है। यहां पुस्तकों और लेखों की एक कंप्यूटरीकृत सूची भी है। पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र ने जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के पुस्तकालयों की योजना और प्रबंध पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

पुस्तकालय, डेलनेट के सदस्य के रूप में दिल्ली के 65 पुस्तकालयों से फोन द्वारा जुड़ा हुआ है। संकाय को इलेक्ट्रॉनिक मेल की सेवा भी प्रदान की जाती है जिससे वे देश–विदेश से अपनी डाक मंगा और भेज सकते हैं।

माननीय डॉ. मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
सर्व शिक्षा अभियान पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए

सर्व शिक्षा अभियान पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागी

श्री एम.के.काव, शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
और निदेशक, नीपा अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर

डॉ. कर्ण सिंह, सुविख्यात शिक्षाविद् और सांसद , राज्य सभा अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा-2000
के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए

**प्रकाशन एकक** : अनुसंधान के परिणामों का प्रचार=प्रसार स्वयं अनुसंधान जितना महत्वपूर्ण होता है। कार्यपत्रों और सामयिक आलेखों के जरिये भी अनुसंधान का प्रसार किया जाता है। प्रसार का एक और साधन विनिबंध और अनुलेखित पांडुलिपियां हैं। यह एकक कार्यपत्रों, सामयिक आलेखों, जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (अंग्रेजी) और 'परिप्रेक्ष्य' (हिंदी), एनट्रिप न्यूजलेटर, शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी पुस्तकों और अनुसंधान की रिपोर्टों का प्रकाशन भी करता है।

**कंप्यूटर केंद्र** : कंप्यूटर केंद्र में पी.II मशीनें हैं। आंकड़ा विश्लेषण और शब्द प्रक्रियन के लिए विभिन्न प्रकार के साफ्टवेयर पैकेज हैं। संस्थान में अधिकांश कंप्यूटर मुख्य कंप्यूटर लौ से सबद्ध हैं। यह केद्र विभिन्न अकादमिक एककों की शोध गतिविधियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों मैं समर्थनकारी सेवाएं प्रदान करता है। अन्य समर्थनकारी एककों को रोजमर्रा का कार्य करने हैं के लिए कंप्यूटर की सुविधाएं प्रदान की जाती है। कंप्यूटर केंद्र में ई–मेल और इंटरनेट की सुविधा भी है। इसके अलावा यह केंद्र संस्थान के विभिन्न प्रकाशनों की लेजर टाइप सेटिंग भी करता है।

**हिंदी कक्ष** : यह कक्ष प्रशिक्षण सामग्रियों के हिंदी अनुवाद के साथ–साथ राष्ट्रीय राजभाषा नीति के अनुसार प्रशासन और संकाय को राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में सहयोग देता है।

**मानचित्रण कक्ष** : यह कक्ष आंकड़ों की सचित्र प्रस्तुति, प्रशिक्षण, प्रकाशन और प्रदर्शन के लिए मानचित्रों और चार्टों आदि की सुविधाएं प्रदान करता है।

**रिप्रोग्राफी कक्ष** : संस्थान की अकादमिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए यह कक्ष प्रशिक्षण सामग्रियों, शोधपत्रों और अनुलेखित सामग्रियों की प्रतियां तैयार करने में सहायता देता है।

## प्रशासन और वित्त

**प्रशासन** : प्रशासनिक व्यवस्था में सामान्य, अकादमिक और कार्मिक प्रशासन आते हैं। 31 मार्च 2000 तक संस्थान की कुल स्वीकृत स्टाफ सदस्य संख्या 181 थी। इसमें अकादमिक और प्रशासनिक, दोनों प्रकार के कार्मिक आते हैं। इनके अलावा विभिन्न परियोजनाओं में उनकी अपनी–अपनी अवधियों तक के लिए नियुक्त 39 परियोजनाकर्मी भी थे।

**वित्त** : इस साल संस्थान को कुल 478.00 लाख रुपये का अनुदान मिला (गैर–योजना मद में 178.00 लाख रु. और योजना मद में 300.00 लाख रु.)। साल के आरंभ में संस्थान के पास योजना और गैर–योजना, दोनों मदों में 32.96 लाख रुपये शेष थे। साल के दौरान कार्यालय और छात्रावास से 65.00 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। योजना और गैर–योजना मदों में इस साल का व्यय 496.93 लाख रुपये था।

दूसरे संगठनों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों/अध्ययनों की मद में इस साल के दौरान संस्थान के पास 89.17 लाख रुपये थे और 305.51 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्ति हुई। प्रायोजित कार्यक्रमों/अध्ययनों पर साल में कुल 223.34 लाख रुपये खर्च किए गए।

**परिसर की सुविधाएं :** संस्थान के पास एक चार–मंजिला कार्यालय, सात मंजिलों में सुसज्जित व स्नानाघरयुक्त 60 कमरों वाला एक छात्रावास और एक आवास–क्षेत्र है। इस आवास क्षेत्र में टाइप I के 16, टाइप II से V तक के 8-8 क्वार्टर और एक निदेशक आवास हैं। छात्रावास को वर्ष के दौरान 20.19 लाख रुपये की प्राप्ति हुई।

# अध्याय 2

## प्रशिक्षण

प्रशिक्षण, संस्थान के मुख्य कार्यकलापों में से एक है। यह शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में संलग्न वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रशासकों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और ऐसे ही दूसरे कार्यक्रम आयोजित करता है। संस्थान दूसरे देशों के प्रमुख शिक्षाकर्मियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

### दृष्टिकोण और मुख्य बल

प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की रूपरेखा क्षेत्र के मए विकासक्रमों से उत्पन्न आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाती है। कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते समय भागीदारों और निर्णयकर्ताओं द्वारा पहचानी गई प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं पर भी विचार किया जाता है। कार्यक्रमों का आयोजन करते समय पिछले भागीदारों द्वारा दिए गए सुझावों को भी ध्यान में रखा जाता है। कार्यक्रमों के ब्यौरों पर विचारविमर्श के लिए कार्यबल गठित किए जाते हैं।

इसके अलावा, संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची बनाते समय प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाता है, मसलन जिला स्तर पर योजना, आदिवासी क्षेत्रों में संस्थाओं और अल्पसंख्यक प्रबंधवाली संस्थाओं की योजना और प्रबंध, शैक्षिक योजना और प्रबंध में कंप्यूटरों की भूमिका आदि। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वाले जिलों में कार्यरत शिक्षाकर्मियों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए मए।

संस्थान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से विकासशील देशों के शिक्षाकार्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी केंद्रीय भूमिका निभाता आ रहा है।

संस्थान समकालीन आवश्यकता के अनुसार धीरे–धीरे अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर तथा राज्य और क्षेत्र स्तर की संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के शिक्षाशास्त्र विभागों से नेटवर्किंग पर जोर दे रहा है।

**प्रशिक्षण सामग्री**

नीपा का संकाय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान पर आधारित सामग्रियों की तैयारी में सक्रिय रहा । कार्यक्रमों के दौरान यह सामग्री भागीदारों के लिए बुनियादी लेखों का काम करती हैं। इन सामग्रियों के साथ संबंधित विषयों पर प्रकाशित साहित्य भी दिया जाता है।

**मूल्यांकन**

प्रशिक्षण के हर कार्यक्रम का औपचारिक मूल्यांकन किया जाता है। इसका पहला चरण हर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में आता है जब एक संरचनाबद्ध प्रपत्र पर हर भागीदार से कार्यक्रम का मूल्यांकन करने को कहा जाता है। लंबी अवधि के कार्यक्रमों में इस मूल्यांकन से पहले एक–दो मध्यावधि मूल्यांकन किए जाते हैं।

**भागीदारी**

वर्ष 1999-2000 में संस्थान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 41 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों और डिप्लोमा कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में कुल 1303 व्यक्तियों ने भाग लिया। इनमें से 1214 भागीदार राष्ट्रीय और 89 भागीदार अंतर्राष्ट्रीय थे। वर्ष 1999-2000 में आयोजित कार्यक्रमों की सूची अनुलग्नक–I में दी गई है।

**राष्ट्रीय स्तर** : समीक्षाधीन वर्ष में संस्थान ने 37 डिप्लोमा कार्यक्रमों/अभिविन्यास व प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों/सम्मेलनों आदि का आयोजन किया। इनमें 1077 भागीदार विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों के शिक्षा विभागों से तथा 137 केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों से जुड़े हुए थे। राज्यवार भागीदारी की सूची तालिका–2 में दी गई है।

इस वर्ष आयोजित कार्यक्रम दो प्रकार के थे : (अ) डिप्लोमा कार्यक्रम और (ब) शैक्षिक योजना और प्रशासन पर सामान्य या विषयवार कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर संक्षिप्त अवधि के विषय केंद्रित कार्यक्रम। संस्थान द्वारा आयोजित श्रेणीवार कार्यक्रम तालिका–1 में दिए गए हैं।

तालिका 1

**1999-2000 में संस्थान द्वारा आयोजित श्रेणीवार कार्यक्रम**

| कार्यक्रमों की श्रेणी | कार्यक्रमों की संख्या | अवधि (दिन) | भागीदारों की संख्या |
|---|---|---|---|
| **डिप्लोमा कार्यक्रम** | | | |
| (अ) राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम * | 2 | 186 | 43 |
| (ब) अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम * | 2 | 181 | 63 |
| **शैक्षिक योजना और प्रशासन पर विषयवार कार्यक्रम** | | | |
| विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए योजना और प्रबंध में प्रशिक्षण | 3 | 15 | 65 |
| उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंध | 4 | 28 | 150 |
| वित्त–योजना और प्रबंधन | 2 | 12 | 40 |
| अल्पसंख्यक समुदाय प्रबंधित संस्थानों की योजना और प्रबंधन | 1 | 12 | 16 |
| सामुदायिक भागीदारी | 1 | 3 | 66 |
| आदिवासी शिक्षा की योजना और प्रबंधन | 1 | 5 | 25 |
| प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण | 1 | 5 | 19 |
| शैक्षिक योजना की परिमाणात्मक तकनीकें | 3 | 28 | 68 |
| विद्यालय मानचित्रण और व्यष्टियोजना | 1 | 5 | 24 |
| जिला शिक्षा–प्रशिक्षण संस्थानों की योजना और प्रबंध | 5 | 22 | 92 |
| साक्षरता कार्यक्रम | 2 | 5 | 42 |
| शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन | 2 | 4 | 335 |
| पुस्तकालय की योजना और प्रबंधन * | 3 | 17 | 72 |
| बंगलादेश के उच्चस्तरीय शिक्षाविदों और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रवीक्षा अधिकारियों के लिए अध्ययन दौरा | 2 | 16 | 37 |
| **अन्य कार्यक्रम** | 6 | 14 | 146 |
| **योग** | **41** | **558** | **1303** |

* *इस सूची में पहले से जारी तीन कार्यक्रम (एक राष्ट्रीय, एक अन्तर्राष्ट्रीय डिप्लोमा और गुजरात राज्य के पुस्तकालयों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम) शामिल हैं।*

संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में देश के लगभग सभी राज्यों और (दमन और दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी को छोड़कर सभी संघीय क्षेत्रों) ने भाग लिया। राज्यवार भागीदारी तालिका–2 में दिखाई गई है।

## तालिका 2
## राज्यवार भागीदारी

| क्रम संख्या | राज्य/संघीय क्षेत्र | भागीदारों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | आंध्रप्रदेश* | 81 |
| 2 | अरुणाचलप्रदेश* | 3 |
| 3 | असम* | 35 |
| 4 | बिहार* | 48 |
| 5 | गोवा | 30 |
| 6 | गुजरात | 67 |
| 7 | हरियाणा | 36 |
| 8 | हिमाचलप्रदेश | 93 |
| 9 | जम्मू–कश्मीर* | 14 |
| 10 | कर्नाटक | 105 |
| 11 | केरल | 34 |
| 12 | मध्यप्रदेश* | 37 |
| 13 | महाराष्ट्र | 46 |
| 14 | मणिपुर | 5 |
| 15 | मेघालय | 6 |
| 16 | मिजोराम | 6 |
| 17 | नागालैंड | 10 |
| 18 | उड़ीसा* | 34 |
| 19 | पंजाब | 12 |
| 20 | राजस्थान* | 35 |
| 21 | सिक्किम | 10 |
| 22 | तमिलनाडु | 50 |
| 23 | त्रिपुरा | 1 |
| 24 | उत्तरप्रदेश* | 68 |
| 25 | पश्चिम बंगाल* | 50 |
| 26 | अंडमान–निकोबार द्वीप समूह | 129 |
| 27 | चंडीगढ़ | 10 |
| 28 | दादरा व नागर हवेली | 1 |
| 29 | दमन और दीव | – |
| 30 | दिल्ली | 121 |
| 31 | लक्षद्वीप | – |
| 32 | पांडिचेरी | – |
| 33 | भारत सरकार व अन्य संगठन | 137 |
| | **योग** | **1214** |

लगभग 33.36 प्रतिशत भागीदार शैक्षिक रूप से पिछड़े दस राज्यों से आए : आंध्रप्रदेश (81), अरुणाचलप्रदेश (3), असम (35), बिहार (48), जम्मू–कश्मीर (14), मध्यप्रदेश (37), उड़ीसा (34), राजस्थान (35), उत्तरप्रदेश (68) और पश्चिम बंगाल (50)।

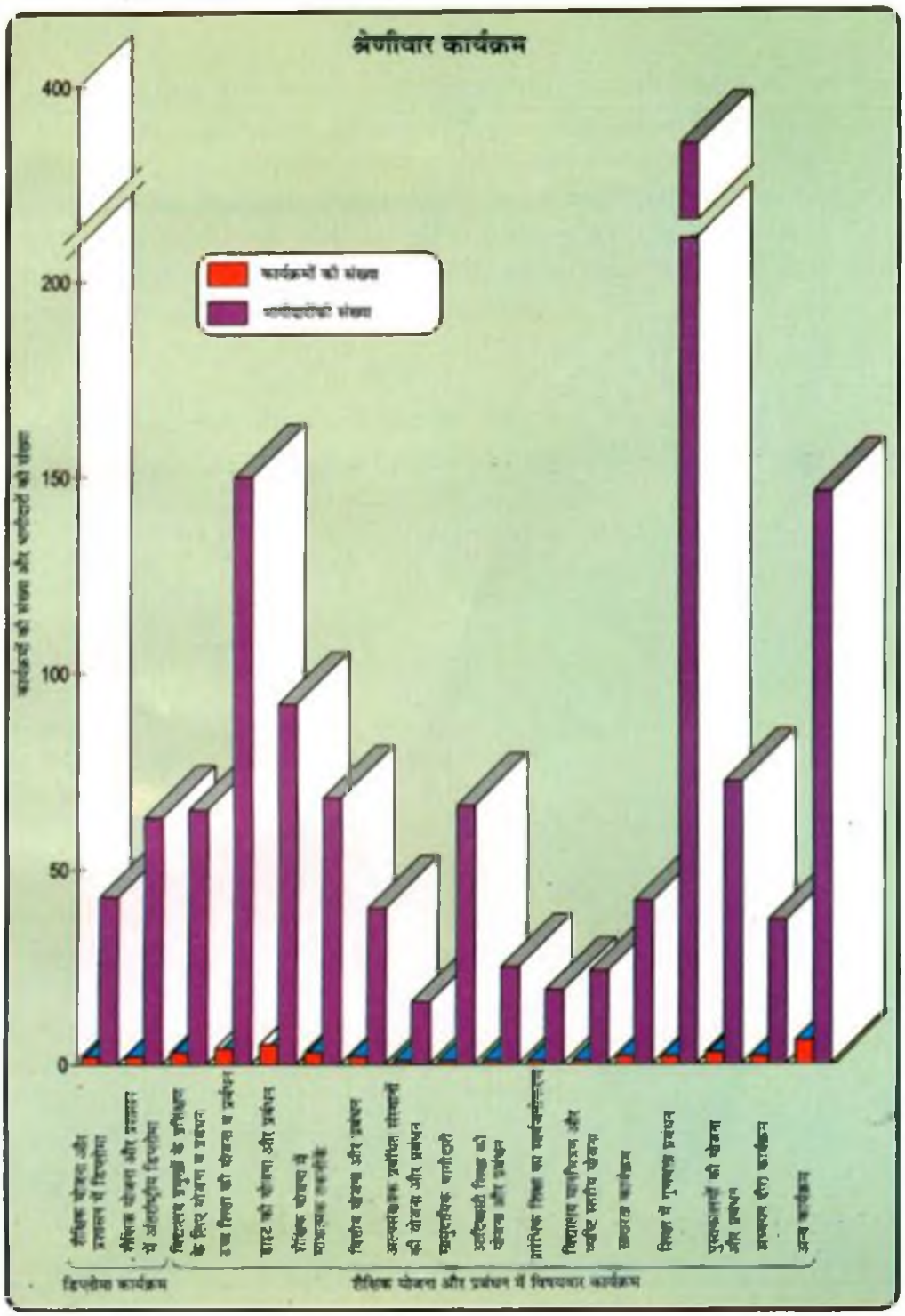

श्रेणीवार कार्यक्रम
कार्यक्रमों की संख्या
400
200
150
100
50
0
डिप्लोमा कार्यक्रम
शैक्षिक योजना और प्रबंधन में विषयवार कार्यक्रम

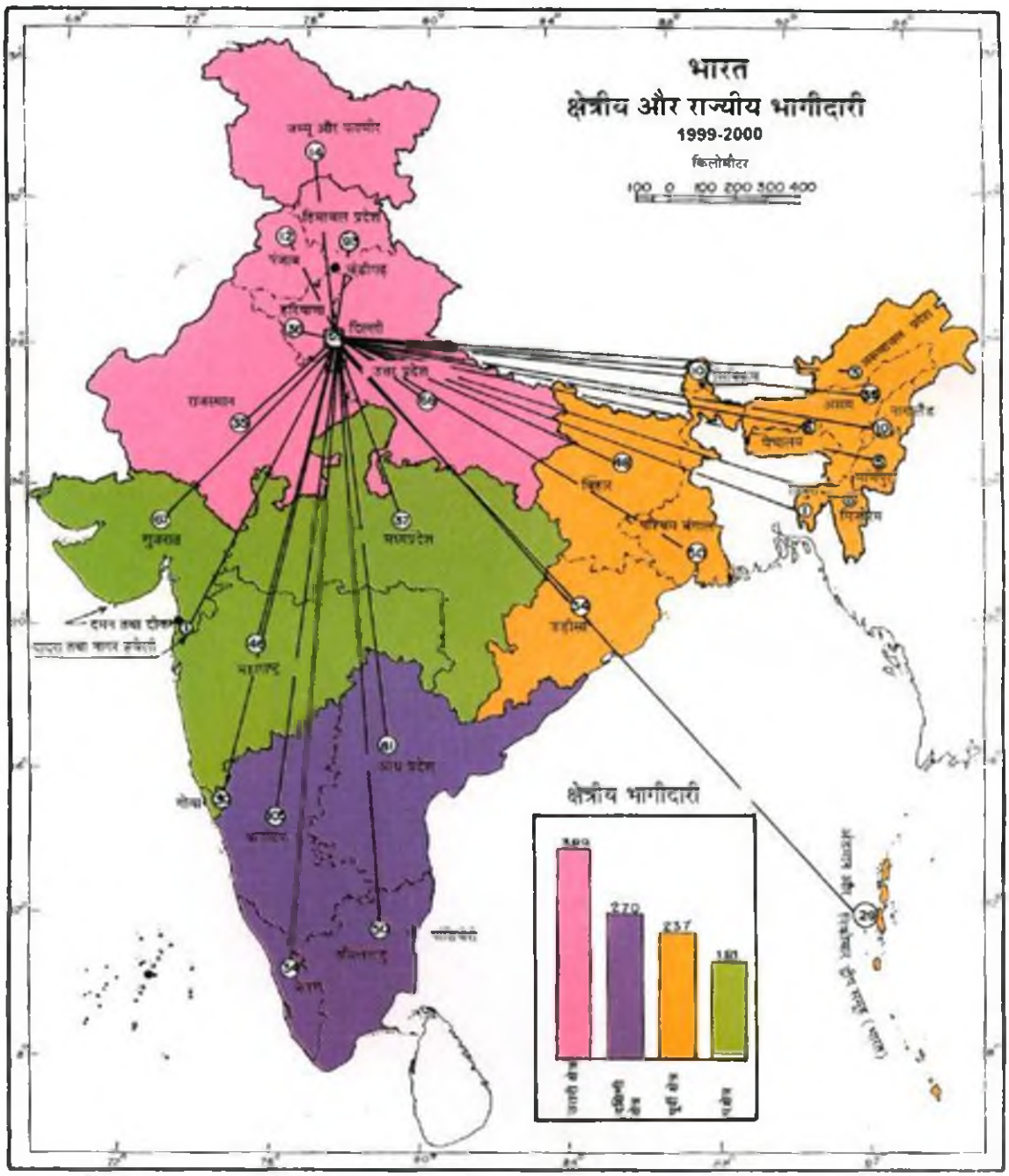

भारत
क्षेत्रीय और राज्यीय भागीदारी
1999-2000
किलोमीटर
दिल्ली
राजस्थान
गुजरात
मध्यप्रदेश
उत्तर प्रदेश
बिहार
महाराष्ट्र
क्षेत्रीय भागीदारी
270
237

**भागीदारी का प्रकार और स्तर** : विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारों का स्तरों के आधार पर एक मिला–जुला समूह था। इनमें राज्यों, संघ क्षेत्रों, शिक्षा निदेशालयों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम राज्यों के और मंडलीय तथा जिला स्तर के कार्मिक, और विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों जैसे संस्था–प्रमुख शामिल थे। इसी तरह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालयों के प्राचार्यों और विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ प्रशासकों ने भी भाग लिया। प्रकार और स्तर के अनुसार भागीदारों के ब्यौरे तालिका–3 में देखे जा सकते हैं :

तालिका 3

**1999-2000 में आयोजित अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों आदि में स्तरवार भागीदारी**

| स्तर | भागीदारों की संख्या |
|---|---|
| विद्यालयों के प्रधानाध्यापक | 98 |
| जिला शिक्षा अधिकारी | 19 |
| जि शि प्र संस्थानों/राज्य शै अ प्र परिषद के कार्मिक | 431 |
| वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासक | 151 |
| महाविद्यालयों के प्राचार्य | 105 |
| विश्वविद्यालयों के प्रशासक/वरिष्ठ अकादमिक सदस्य | 213 |
| अन्य | 197 |
| **योग** | **1214** |

इस वर्ष संस्थान ने 2 डिप्लोमा कार्यक्रम (जिनमें एक अभी चल रहा था) आयोजित किये। बंगलादेश के उच्चस्तरीय शिक्षाविदों के प्रतिनिधि मंडल ने संस्थान का दौरा किया। श्रीलंका और चीन के प्रतिनिधियों के लिए तीन अध्ययन दौरे आयोजित किए गए। संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में विभिन्न देशों के कुछ अधिकारियों ने भी भाग लिया। 89 व्यक्तियों की देशवार भागीदारी तालिका 4 में दिखाई गई है :

तालिका 4

**1999-2000 में आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में देशवार भागीदारी**

| देश का नाम | भागीदारों की संख्या |
|---|---|
| आस्ट्रेलिया उच्चायुक्त | 2 |
| बंगलादेश | 10 |
| भूटान | 7 |
| ब्रिटेन | 2 |
| बोत्सवाना | 2 |
| कंबोडिया | 1 |
| कोमरोस द्वीप | 1 |
| क्यूबा | 1 |
| डोमिनिका | 1 |
| इरीट्रिया | 8 |
| गुयाना | 2 |
| इंडोनेशिया | 1 |
| इराक | 1 |
| जमैका | 2 |
| जापान | 1 |
| कज़ाकिस्तान | 1 |
| किरजिस्तान | 1 |
| लाओ गणराज्य | 1 |
| मलेशिया | 2 |
| मालदीव | 2 |
| मारीशस | 6 |
| मोलदोवा | 1 |
| मंगोलिया | 2 |
| मोरक्को | 1 |
| नेपाल | 1 |
| नीदरलैंड | 1 |
| नाइजर | 2 |
| ओमान | 1 |
| दक्षिण अफ्रीका | 1 |
| सुडान | 1 |
| सीरिया | 3 |
| थाइलैंड | 2 |
| तंजानिया | 1 |
| उजबेकिस्तान | 1 |
| वियतनाम गणराज्य | 6 |
| ज़ाम्बिया गणराज्य | 4 |
| **अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं** | |
| यूरोपियन कमीशन | 2 |
| यूनेस्को | 2 |
| विश्व बैंक | 1 |
| यू.एस.ई.एफ.आई. | 1 |
| **योग** | **89** |

## क्षेत्रवार और विषयवार कार्यक्रम

संस्थान ने चार डिप्लोमा कार्यक्रमों (2 राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय जिनमें दोनों में से एक–एक पिछले वर्ष से चल रहे थे), 37 प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रमों (एक पहले से जारी था), 8 कार्यशालाओं, 3 संगोष्ठियों, 5 बैठकों और 2 दौरा कार्यक्रमों (इनमें एक पिछले वर्ष से चल रहा था) का आयोजन किया।

**शैक्षिक योजना और प्रशासन में राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम (डेपा)** : वर्ष 1999-2000 में संस्थान ने 19वें डिप्लोमा कार्यक्रम का दूसरा और तीसरा चरण पूरा किया। इस कार्यक्रम का

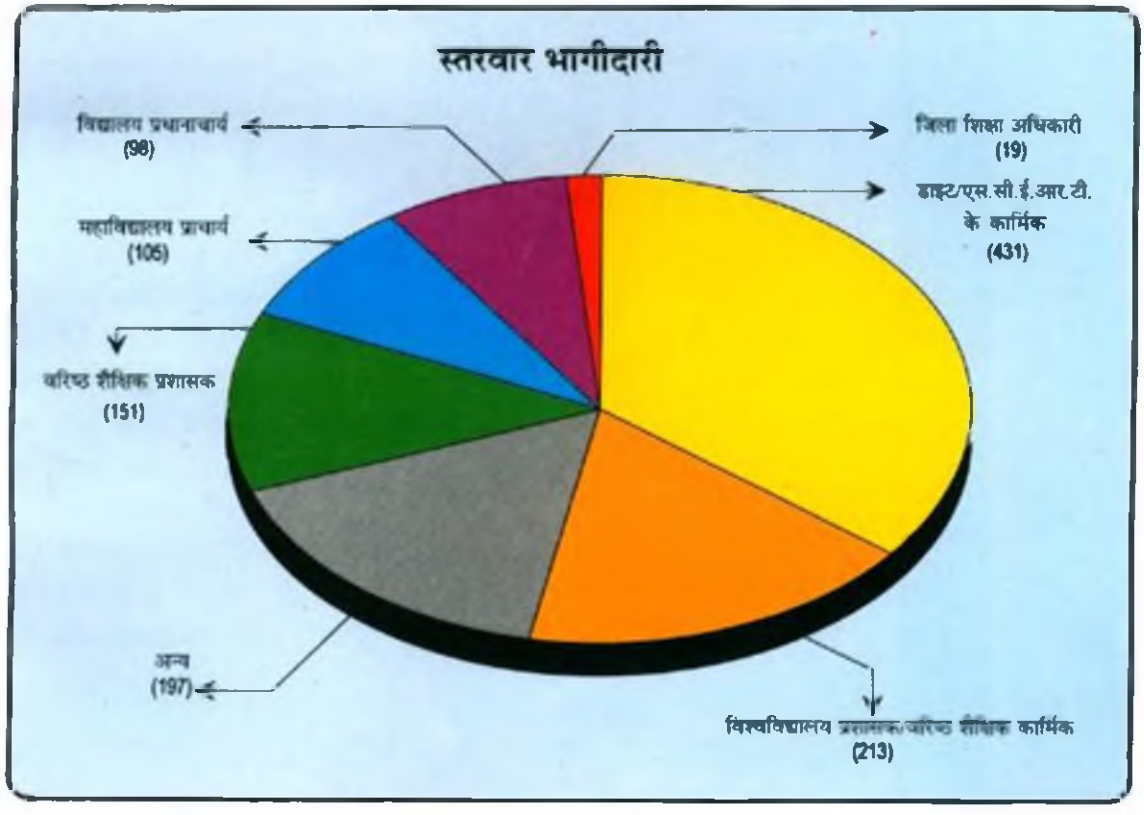
स्तरवार भागीदारी
विद्यालय प्रधानाचार्य
(98)
महाविद्यालय प्राचार्य
(106)
वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासक
(151)
अन्य
(197)
जिला शिक्षा अधिकारी
(19)
डाइट/एस.सी.ई.आर.टी.
के कार्मिक
(431)
विश्वविद्यालय प्रशासक/वरिष्ठ शैक्षिक कार्मिक
(213)

## अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी :1999-2000

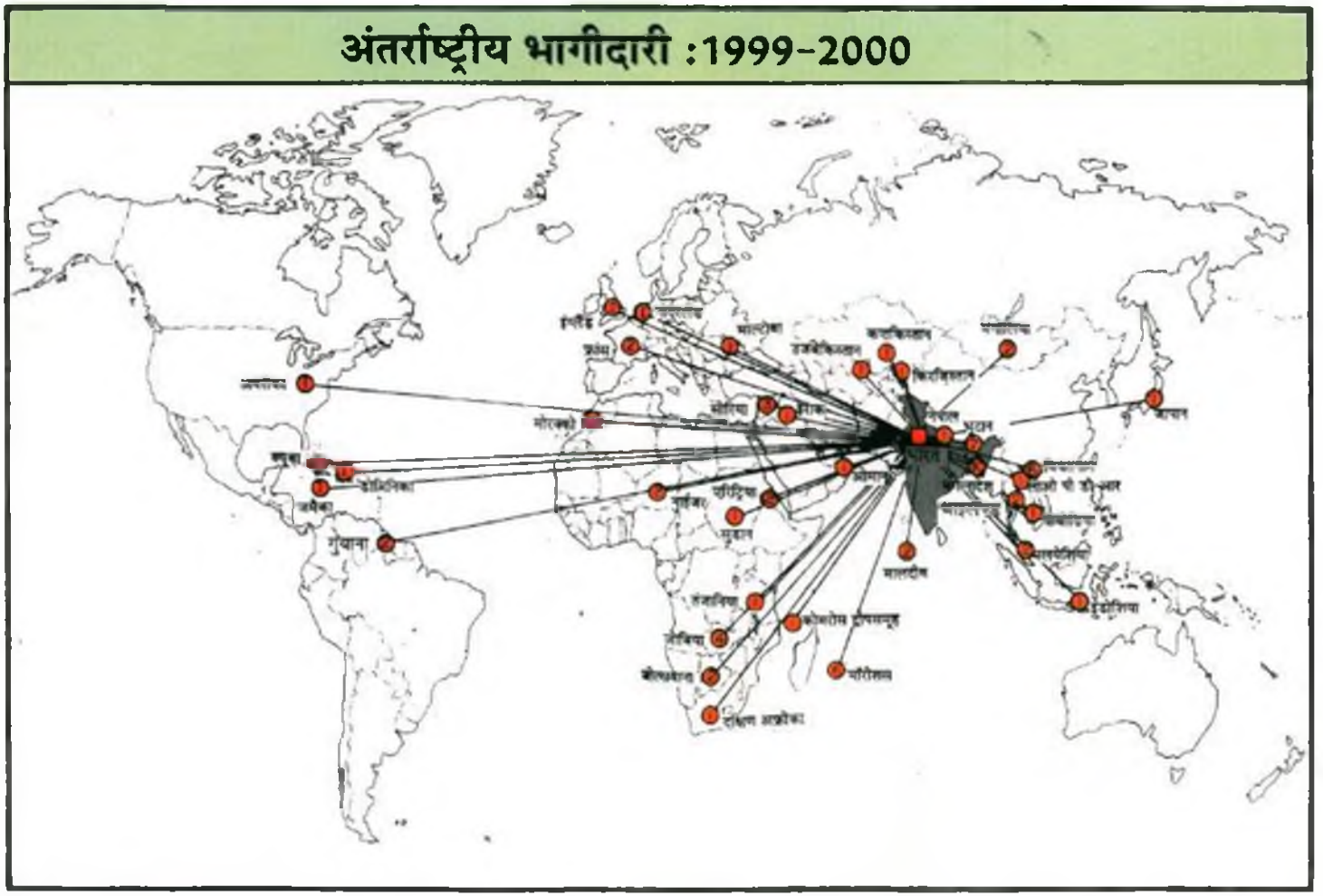

प्रथम चरण नवम्बर 1998 में शुरू हुआ था। जनवरी 1998 और अप्रैल, 1999 में क्रमशः दूसरे और तीसरे चरणों का समापन हुआ। 20वां डिप्लोमा कार्यक्रम का पहला चरण 1 नंवबर 1999 को प्रारंभ हुआ। इसका पहला और दूसरा चरण क्रमशः जनवरी और अप्रैल 2000 में पूरा हुआ। इन दोनों कार्यक्रमों में 43 अधिकारी शामिल हुए।

20वां डिप्लोमा कार्यक्रम व्याख्यान -- परिचर्चा, परिसंवाद, समेकित केस अध्ययन विधि, अभिप्रेरणात्मक भूमिका निर्वहन कार्याभ्यास बास्केट विधि और निर्धारित विषयों पर सामूहिक परिचर्चा पर आधारित थे। इसके अलावा व्यावहारिक कार्याभ्यास, पुस्तकालय आधारित कार्य और कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थानों के अध्ययन दौरों के लिए भी पर्याप्त समय दिया गया। प्रत्येक प्रतिभागी को कार्यभार निर्वहन का प्रशिक्षण भी दिया गया जिसके अंतर्गत प्रतिभागी को अपने कार्य क्षेत्र में 3 माह का परियोजना अध्ययन कार्य करना था। परियोजना अध्ययन कार्य का पर्यवेक्षण भी किया गया। अपनी परियोजना रिपोर्ट का सारांश 15 फुलस्केप पेंज में प्रस्तुत करना था।

पाठ्यचर्या के एक भाग के रूप में नीपा ने भागीदारों के लिए 3–10 जनवरी 1999 के दौरान कर्नाटक राज्य अध्ययन दौरा आयोजित किया। अध्ययन दौरे के दौरान राज्य की गतिविधियों से अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भागीदारों को तीन समूहों में विभाजित किया गया। प्रत्येक समूह ने राज्य के दो जिलों का दौरा किया। अध्ययन दौरे वाले जिले थे–मैसूर और मांड्या, बेलारी और रायचूर तथा कालार और बैंगलौर ग्रामीण क्षेंत्र। राज्य के इन क्षेत्र कीं कुछ प्रमुख नवाचारी गतिविधियों में नाल्ली काली, कला जत्था चिनार मेला और व्यष्टिस्तरीय योजना सहित प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में सामुदायिक भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। प्रत्येक समूह को अपने संबंधित जिले के दौरे के दौरान इन गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिला। भागीदारों ने ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, सी आर सी/ बी आर सी के अधिकारियों, बैंगलौर देहात, मैसूर, मांड्या ओर रायचूर के डाइट संकायों तथा विद्यार्थियों के साथ बैठकें भी कीं।

अठारहवें और उन्नीसवें डिप्लोमा कार्यक्रम में राज्यवार भागीदारी का विवरण तालिका–5 में प्रस्तुत है :

तालिका 5

19वें और 20वें डिप्लोमा कार्यक्रमों में राज्यवार भागीदारी

| राज्य | 19वां डिप्लोमा | 20वां डिप्लोमा | योग |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 1 | - | 1 |
| असम | 1 | 2 | 3 |
| गोवा | - | 1 | 1 |
| गुजरात | 5 | 5 | 10 |
| जम्मू–कश्मीर | 4 | 3 | 7 |
| कर्नाटक | 2 | 5 | 7 |
| केरल | 1 | 1 | 2 |
| महाराष्ट्र | 1 | 2 | 3 |
| मणिपुर | 1 | - | 1 |
| उड़ीसा | 1 | - | 1 |
| सिक्किम | - | 1 | 1 |
| त्रिपुरा | 1 | - | 1 |
| उत्तरप्रदेश | - | 3 | 3 |
| अंडमान–निकोबार द्वीप समुह | 1 | - | 1 |
| दिल्ली | - | 1 | 1 |
| **योग** | **19** | **24** | **43** |

**शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आई-डेपा)** : नीपा में 1985 से ही हर वर्ष विकासशील देशों के शिक्षाकर्मियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में एक छः माह का अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 15वां आई–डेपा कार्यक्रम फरवरी 1999 में शुरू होकर जुलाई 1999 में पूरा हुआ। 16वां आई–डेपा कार्यक्रम फरवरी 2000 में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के पहले और दूसरे चरण क्रमशः अप्रैल और जुलाई 2000 में पूरे हुए।

तालिका 6

15वें और 16वें अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रमों में देशवार भागीदारी

| देश का नाम | 15वां डिप्लोमा | 16वां डिप्लोमा | योग |
|---|---|---|---|
| भूटान | 3 | 2 | 5 |
| कंबोडिया | - | 1 | 1 |
| कोमरोस द्वीप समूह | - | 1 | 1 |

क्रमशः

| देश का नाम | 15वां डिप्लोमा | 16वां डिप्लोमा | योग |
|---|---|---|---|
| क्यूबा | 1 | - | 1 |
| डोमिनिका राष्ट्रमंडल | - | 1 | 1 |
| इरीट्रिया | 4 | 4 | 8 |
| गुयाना | 1 | 1 | 2 |
| इंडोनेशिया | 1 | - | 1 |
| इराक | 1 | - | 1 |
| जमैका | 1 | 1 | 2 |
| जापान | 1 | - | 1 |
| कज़ाकिस्तान | 1 | - | 1 |
| किरगिस्तान | - | 1 | 1 |
| लाओ गजराज्य | - | 1 | 1 |
| मलेशिया | 2 | - | 2 |
| मालदीव | - | 2 | 2 |
| मारीशस | 3 | 3 | 6 |
| मोलदोवा | 1 | - | 1 |
| मंगोलिया | 1 | 1 | 2 |
| मोरक्को | - | 1 | 1 |
| नाइजर | - | 2 | 2 |
| ओमन | - | 1 | 1 |
| दक्षिण अफ्रीका | 1 | - | 1 |
| सुडान | - | 1 | 1 |
| सीरिया | 3 | - | 3 |
| थाइलैंड | 2 | - | 2 |
| तंजानिया | - | 1 | 1 |
| उजबेकिस्तान | - | 1 | 1 |
| वियतनाम गणराज्य | 3 | 3 | 6 |
| जांबिया गणराज्य | 1 | 3 | 4 |
| **योग** | **31** | **32** | **63** |

पाठ्यक्रम की संरचना के दो प्रमुख घटक थे : (अ) पहला चरण जो नीपा में तीन माह के गहन पाठ्यचर्यात्मक कार्य पर आधारित था, और (ब) भागीदार के अपने प्रयास से उसी के देश में तीन माह की क्षेत्र अनुसंधान परियोजना। कार्यक्रम के पद्धतिशास्त्र में सिद्धांत और व्यवहार के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें मोटे तौर पर व्याख्यान और

विचार–विमर्श, अनुकरण और व्यावहारिक कार्य, भूमिका निर्वाह, केसों पर बहस, प्रबंध कार्याभ्यास, खोजी सम्मेलन, प्रदर्शन और सामूहिक विचार विमर्श शामिल होते हैं। इसके अलावा भागीदारों को प्रोत्साहन देने के लिए पैनल विचार–विमर्श और भागीदारों की संगोष्ठियां इस पाठ्यक्रम की पद्धति की प्रमुख विशेषताएं हैं। कार्यक्रम में व्यष्टिगत स्तर पर अकादमिक कार्यों, शैक्षिक/सांस्कृतिक क्षेत्र–भ्रमण, शैक्षिक संबद्धताओं और समृद्धकारी व्यख्यानों पर भी जोर दिया जाता है। पूरे कार्यक्रम में अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अलावा, व्यष्टिगत स्तर पर क्षेत्रीय शैक्षिक संबद्धताएं आई–डेपा के भागीदारों के कार्यों का एक प्रमुख घटक है। इन संबद्धताओं में कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की उच्च स्तरीय संस्थाओं के दौरे और उनसे संबद्धता शामिल थे। ऐसे हर दौरे के बाद पहले से मनोनीत एक भागीदार/क्षेत्र सलाहकार ने एक संस्था विशेष के शैक्षिक भ्रमण पर एक रिपोर्ट पेश की। 30 देशों के कुल 63 अधिकारियों ने इन दोनों आई–डेपा कार्यक्रमों में भाग लिया। 15वें और 16वें अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम में देशवार भागीदारी तालिका 6 में दिखाई गई है।

**विद्यालय-प्रमुखों के प्रशिक्षण की योजना और प्रबंधन**

विद्यालय प्रमुखों के लिए संसाधन की योजना और प्रबंध पर एक अभिविन्यास कार्यक्रम और 2 कार्यशाला आयोजित किए गए। इनमें 65 विद्यालय प्रमुखों ने भाग लिया।

**उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंधन**

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान ने दो संगोष्ठियां आयोजित की। इनके विषय थे : 'उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आकलन : मानदंड और संकेतक। इसके अलावा महाविद्यालय के प्राचार्यों के लिए महाविद्यालय की' योजना और प्रबंधन पर दो अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय प्रशासकों और महाविद्यालय प्राचार्यों सहित कुल 150 भागीदार शामिल हुए।

**जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की योजना और प्रबंधन**

नीपा ने डाइट के प्राचार्यों और संकाय सदस्यों के लिए योजना और प्रबंधन पर 2 अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक कार्यशाला और डाइट के राज्यवार मूल्यांकन हेतु आंकड़ा विश्लेषण कीं रूपरेखा की तैयारी के लिए दो बैठकें आयोजित कीं। इन कार्यक्रमों में डाइट प्राचार्यों तथा संकाय सदस्यों और राज्यस्तरीय अधिकारियों सहित कुल 92 भागीदार सम्मिलित हुए।

**शैक्षिक योजना में मात्रात्मक तकनीक**

शैक्षिक योजना में मात्रात्मक तकनीक के क्षेत्र में संस्थान ने दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इनके विषय थे : "शैक्षिक योजना में मात्रात्मक तकनीक का प्रयोग और शिक्षा की उन्नत मात्रात्मक कार्यविधियों और शिक्षा की योजना में संकेतकों का प्रयोग"। इन कार्यक्रमों में राज्यों से कुल 68 अधिकारी शामिल हुए।

**वित्तीय प्रबंधन**

वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में दो अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें विभिन्न विश्वविद्यालयों और राज्य स्तरीय अधिकारियों सहित कुल 40 भागीदार शामिल हुए।

**अल्पसंख्यक समुदाय प्रबंधित संस्थानों की योजना और प्रबंधन**

संस्थान ने अल्पसंख्यक समुदाय प्रबंधित संस्थानों की शैक्षिक योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में देश के संबंधित संस्था–प्रमुखों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें 16 संस्था–प्रमुखों ने हिस्सा लिया।

**सामुदायिक भागीदारी**

संस्थान में 'सामुदायिक भागीदारी और प्राथमिक शिक्षा का सबलीकरण' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय सरकारों और विभिन्न राज्यों के अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 6 अधिकारियों सहित कुल 66 अधिकारियों ने भाग लिया।

**आदिवासी शिक्षा की योजना और प्रबंधन**

आंध्र प्रदेश आदिवासी कल्याण आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसायटी और नीपा के संयुक्त तत्वावधान में ए पी टी डब्ल्यू आर ई आई एस के प्राचार्यों के लिए सांस्थानिक योजना और प्रबंधन पर हैदराबाद में एक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 25 प्राचार्य शामिल हुए।

**प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण**

नीपा ने एजावल में पूर्वोत्तर राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में पूर्वोत्तर राज्यों के 19 अधिकारियों ने भाग लिया।

**विद्यालय मानचित्रण और व्यष्टि स्तरीय योजना**

संस्थान ने विद्यालय मानचित्रण ओर व्यष्टि स्तरीय योजना के क्षेत्र में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राज्य स्तर के 24 अधिकारी सम्मिलित हुए।

**साक्षरता कार्यक्रम**

इस वर्ष प्रौढ़ शिक्षा के राज्य स्तरीय संसाधन केंद्रों के मूल्यांकन पर एक बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा साक्षरता आकलन कार्यनीति और प्रक्रिया पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इन दोनो कार्यक्रमों में केंद्रीय सरकार और राज्यों के कुल 42 अधिकारी शामिल हुए।

**शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन**

नीपा ने शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन पर एस सी ई आर टी कार्मिकों के लिए एक कार्यशाला और केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्राचार्यों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया।

इन कार्यक्रमों में कुल 335 भागीदार सम्मिलित हुए।

**पुस्तकालयों की योजना और प्रबंधन**

नीपा ने डाइट पुस्तकालयों की योजना और प्रबंधन पर गुजरात में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया और एक–एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के महाविधालय पुस्तकालयों के लिए आयोजित किया। इन तीनों कार्यक्रमों में कुल 72 पुस्तकालयाध्यक्षों ने भाग लिया।

**अध्ययन दौरा कार्यक्रम**

समीक्षाधीन वर्ष में बंगला देश के 10 उच्च स्तरीय शिक्षाविदों का एक प्रतिनिधि मंडल और भारतीय सांख्यिकी सेवा के 27 परिवीक्षा अधिकारियों ने संस्थान का दौरा किया।

**अन्य कार्यक्रम**

संस्थान ने अन्य क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। ये कार्यक्रम थे : तृतीयक शिक्षा क्षेत्र में मानवाधिकार पर विचारोत्तेजक कार्यक्रम, हिमाचल प्रदेश मे विद्यालय सुधार योजना पर कार्यशाला, *डाइस* डाटा परियोजना और अनुश्रवण की सामान्य वैधता पर राष्ट्रीय कार्यशाला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर परिचर्चा बैठक और भूटानी शैक्षिक कार्मिकों के लिए कार्यालय प्रबंधन में अभिविन्यास कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में 2 विदेशी भागीदारों (भूटान) सहित विभिन्न केन्द्रीय और राज्य स्तरीय संगठनों से कुल 146 भागीदार शामिल हुए।

# अध्याय 3

## अनुसंधान और प्रकाशन

### अनुसंधान

नीपा शैक्षिक योजना और प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को आयोजित करने, सहायता देने, प्रोत्साहन देने और उसका समन्वय करने संबधी कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न है। इस अनुसंधान की प्रकृति बहुशास्त्रीय होती है और इसमें शैक्षिक योजना और प्रशासन के सिद्धांतों, नीतियों, प्रासंगिक विधियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं पर विशेष बल दिया जाता है।

नीपा की ओर से संकाय की शोध परियोजनाओं के लिए धन देकर दूसरे संगठनों की शोध परियोजनाएं लेकर तथा पहचानशुदा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों में शोध के लिए विशेषज्ञों और संस्थाओं को वित्तीय सहायता देकर अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाता है।

नीपा द्वारा आयोजित और सहायताप्राप्त अनुसंधान में सैद्धांतिक और अनुभवाश्रित मुद्दों का समन्वय होता है। संस्थान के शोधकार्यों, नीतियों और योजनाओं के निरूपण के लिए निरंतर ठोस अनुभवाश्रित और वैश्लेषिक आधार तैयार करने के प्रयास किए जाते हैं। प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भी महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान की जाती है।

समीक्षाधीन अवधि में 20 शोध अध्ययन पूरे हुए जबकि 15 अध्ययन जारी थे।

### पूरे किए गए अध्ययन

**1. कुछ उत्कृष्ट अध्यापकों का कार्यविवरण और शिक्षा के विकास में उनका योगदान**

यह अध्ययन नीपा सहायता योजना के अंतर्गत प्रो. जे. मोहंती, पूर्व प्राचार्य, राधानाथ, आई ए एस ई, कटक ने किया। इसके लिए रु. 90,000 की धनराशि स्वीकृत की गई थी। अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य थे :

(i) विभिन्न स्रोतों से उत्कृष्ट अध्यापकों का बायो–डाटा और अन्य संबंधित सूचनाएं एकत्र करना,

(ii) विद्यालयों में कार्यरत लगभग 50 उत्कृष्ट अध्यापकों का चयन करना,

(iii) विभिन्न उपकरणों से एकत्र आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्या करना,

(iv) चयनित सफल अध्यापकों का जीवनवृत्त संबंधी विवरण तैयार करना और समाज के प्रति उनकी अभिप्रेरणा और योगदान पर प्रकाश डालना, और

(v) अध्यापकों के उत्कृष्ट विकास को बढ़ावा देने के लिए मागदर्शिका/सुझाव का विकास करना।

इस अध्ययन में निम्नांकित सुझाव दिए गए हैं :

(क) आमतौर पर आज समाज में उत्कृष्ट अध्यापक एक अपवाद स्वरूप हैं और वे सतत नवाचारी हैं। अतः सरकार द्वारा उनका पूर्ण सहयोग अपेक्षित है और उनके प्रमुख कार्यकलापों को निरंतर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए;

(ख) चूंकि अधिकांश उत्कृष्ट अध्यापक सृजनशील और स्वाभिमानी स्वभाव के हैं, इसलिए समाज के हित में उनके आत्माभिमान को यथोचित महत्व दिया जाए;

(ग) अधिकांश उत्कृष्ट अध्यापक स्वतंत्र विचारधारा के हैं, इसलिए उन्हें उचित अधिकार और स्वायत्तता मिलनी चाहिए;

(घ) वे दृढ़ अनुशासनप्रिय हैं। उनकी अनुशासन व्यवस्था में किसी प्रकार का वांछित हस्तक्षेप न किया जाए;

(च) वे दृढ़ प्रतिज्ञ और अटल अनुरागी होते हैं, इसलिए किसी प्रकार का प्रलोभन और अंकुश आवश्यक नहीं होगा;

(छ) उत्कृष्ट अध्यापक अच्छे अकादमिशियन हैं, उनको अच्छा वेतन, अवकाश और पुस्तकालय सुविधाओं सहित पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाए;

(ज) उनमें से अधिकांश पाठ्यचर्यात्मक और सह पाठ्यचर्यात्मक, दोनों गतिविधियों में अभिरुचि रखते हैं, इसलिए उन्हें समुचित रूप से भौतिक सुविधाएं और अपेक्षित नेतृत्व प्रदान किया जाए;

(झ) अधिकांश उत्कृष्ट अध्यापक लेखक/कलाकार, समाज सुधारक हैं, उचित सामाजिक हित में उनके सृजनात्मक कार्यकलापों को उचित श्रेय तथा सहयोग मिलना चाहिए;

(ट) विशेष प्रतिभाओं – अभिनय, वाक् शैली और आशुकाव्य आदि से सम्पन्न उत्कृष्ट अध्यापकों को अपनी विलक्षण प्रतिभाओं का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए;

(ठ) इन उत्कृष्ट अध्यापकों में अच्छी खासी संख्या उन अध्यापकों की है जो सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के उन्मूलन में विशेष रूप से सक्रिय हैं। उन्हें असामाजिक तत्वों

से सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है जो ऐसे जघन्य अपराध और भेदभाव के संरक्षक हैं;

(ड) यद्यपि उत्कृष्ट अध्यापकों में किसी प्रकार के पुरस्कार या सम्मान की महत्वाकांक्षा नहीं है, फिर भी सरकार/समाज द्वारा उनकी पहचान की जाए और उनको अपेक्षित मान्यता प्रदान की जाए;

(ढ़) आज के भौतिकवादी युग में ऐसे उत्कृष्ट अध्यापकों और उनके योगदानों को भूल जाने की संभावना है। अतः उनके जीवनवृत्त और कार्यकलापों से संबंधित सामग्री तैयार करने की आवश्यकता है ताकि वे समाज और विशेषकर अध्यापकों के लिए निरंतर प्रेरणास्रोत बन सकें;

(त) यद्यपि उत्कृष्ट अध्यापक कभी भी नाम, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के आकांक्षी नहीं होते हैं। उनकी पहचान की जानी चाहिए और सामाजिक हित में उनको अपेक्षित सम्मान दिया जाना चाहिए;

(थ) सफल लोकतंत्र में शिक्षा के जनतांत्रीकरण के द्वारा अध्यापक की नेतृत्वकारी गुणवत्ता को निरंतर उन्नत बनाने की आवश्यकता है;

(द) आधुनिक जनसंचार माध्यम द्वारा इन उत्कृष्ट अध्यापकों की नवाचारी, सृजनात्मक और प्रेरणादायी गतिविधियों का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए। इससे सामाजिक कल्याणकारी गतिविधियों के व्यापक कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी;

## 2. दिल्ली में विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान : समीक्षा और विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन डा. (श्रीमती) रश्मि दीवान, सह–अध्येता ने किया। इसके लिए रु. 20,000 की धनराशि स्वीकृत थी। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे :

(क) दिल्ली में विद्यालयी शिक्षा से संबंधित अध्ययनों को एकत्र करके उनकी समीक्षा करना,

(ख) एकत्रित सभी अध्ययनों के सारांश तैयार करना,

(ग) एकत्रित अध्ययनों में विद्यालयी शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों, समस्याओं, आयामों आदि पर विश्लेषणात्मक समीक्षा आलेख तैयार करना।

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नाकित निष्कर्ष है :

दिल्ली के विद्यालयों पर शोध अध्येताओं द्वारा किए गए अध्ययनों का विश्लेषण और समीक्षा उनके परिणाम की दृष्टि से बहुत ही व्यापक है। ये अध्ययन मुख्यतः पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकें और विशेषकर विज्ञानधारा के विभिन्न विषयों की शिक्षण विधियों पर केंद्रित हैं। उन अध्ययनों की अच्छी खासी संख्या है जो परीक्षण और परीक्षाओं तथा संप्राप्तियों पर हैं। उनमें नई प्रभावकारी परीक्षाविधियों और प्रणालियों द्वारा सहसंबंध स्थापित किए गए हैं। विद्यालय और विद्यार्थी कार्यनिष्पादन के उत्तरोत्तर विकास में सहायक दूसरे पक्षों पर अध्ययन के प्रयास

द्वारा विद्यालय गुणवत्ता में सुधार के लिए शोध किया जा सकता है।

शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत वीडियो, कंप्यूटर साफ्टवेयर, टी घी कार्यक्रमों और कुछ विषयों के शिक्षण में अभिप्रेरणात्मक तर्कपूर्ण उपागमों पर शोध अध्ययनों में चर्चा की गई है। शोध अध्ययन सहपाठी से अनुक्रियात्मक अधिगम की प्रभाविकता, सुनियोजित अधिगम, विषय विशेष में आत्मनियंत्रित अनुदेशन विधि से संबंधित हैं मगर इनमें कोई नई बात नहीं है। अतः कक्षा में वास्तविक शिक्षण अधिगम की स्थितियों और सामान्य अनुदेशात्मक विधियों पर और अधिक सार्थक शोध अध्ययनों की आवश्यकता है। उपलब्ध संसाधनों के दायरे में शिक्षण को प्रभावकारी बनाने की विधियों से संबंधित अध्ययनों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षण और संप्राप्तिस्तर वाले अच्छे विद्यालयों के केस अध्ययन तैयार करने की आवश्यकता है। विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों, शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और अध्यापकों से संबंधित मुद्दो पर सीमित संख्या में शोध अध्ययन हुए। अध्यापकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बहुत सार्थक अध्ययन हैं। समीक्षाधीन प्रत्येक अध्ययन विशिष्ट, महत्वपूर्ण और संवेदनशील समस्या से संबंधित हैं मगर अधिकांश अध्ययनों की और अधिक उच्चस्तरीय कार्मिकों पर केंद्रित कर व्यापक अध्ययन की जरूरत है ताकि अपेक्षाकृत सही तस्वीर सामने आ सके. और सूक्ष्म विवेचन के साथ अपेक्षित सुझाव प्रकाश में आएं।

विद्यालयी शिक्षा के लिए वित्त व्यवस्था और उपयोग से संबंधित अध्ययन बहुत सीमित हैं। विद्यालयों के प्रकार, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, विद्यालय की श्रेणी, लक्ष्य वर्ग' अध्यापकों की कार्यदशाएं, सामुदायिक सहयोग के स्वरूप और अन्य संबंधित पक्षों के अनुसार अधिक वित्त व्यवस्था वाले प्राथमिक क्षेत्रों के शैक्षिक कार्मिकों को जागृत करने वाले शोध अध्ययनों की आवश्यकता है।

### 3. सुलभता और धारणक्षमता : डी पी ई पी का प्रभाव

यह अध्ययन डा. वाई पी अग्रवाल, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, संक्रियात्मक अनुसंधान प्रणाली प्रबंधन एकक ने किया। इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य डी घी ई पी के विशेष संदर्भ में प्राथमिक कक्षाओं में सुलभता और धारणक्षमता के विविध आयामों की समीक्षा करना है। इस अध्ययन के अंतर्गत विशेष रूप से विश्लेषण के लिए निम्नांकित मुद्दों की पहचान की गई :

(क) डी पी ई पी और गैर–डी पी ई पी जिलों के बीच नामांकन की प्रवृत्तियों की तुलना करना,

(ख) निम्नांकित तथ्यों के अनुसार डी पी ई पी–जिलों का कार्यविवरण तैयार करना;

  (अ) कक्षा, लिंग, अ. ज. और अ. ज. जा. के अनुसार नामांकन में वृद्धि,

  (ब) प्रत्येक कक्षा के लिए लिंगवार पुनरावर्ती दर,

  (स) नामांकन दरों में लिंग और जाति के अनुसार अंतर,

(ग) सामान्यतया प्राथमिक शिक्षा और विशेषकर डी पी ई पी की नीति, योजना और

अनुश्रवण के लिए कार्यनिष्पादन के संकेतकों में हाल की प्रवृत्तियों के प्रभाव और निहितार्थों की समीक्षा करना।

इस अध्ययन में डी पी ई पी–I के सभी 42 जिलों को शामिल किया गया। डी पी ई पी और गैर–डी पी ई पी जिलों के नामांकन संकेतकों के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए आधार वर्ष 1993–94 तथा समाप्ति वर्ष 1996–97 माना गया था। यद्यपि यह परियोजना अध्ययन अधिकारिक रूप से 1994 के अंत में शुरू किया गया था, परंतु 1993–94 के दौरान चुनिंदा जिलों में शिक्षार्थी संप्राप्ति आधार निर्धारण सहित पूर्व परियोजना गतिविधियां आरंभ कर दी गई थीं।

डी पी ई पी जिलों में वर्ष 1995–96 और 1996–97 के नामांकन का लिंग, सामाजिक और क्षेत्रीय वर्गीकरण के अनुसार विस्तृत विश्लेषण किया गया। डी पी ई पी परियोजना आरंभ होने के बाद कुछ जिलों का पुनर्गठन किया गया। कार्यक्रम आगतों और परियोजना के अनुश्रवण के लिए जिलों के पूर्ववत सीमांकन को ही आधार माना गया है। इसलिए ई एम आई एस आंकड़ा कालक्रम से तुलनीय है।

## 4. प्राथमिक विद्यालय की आधारभूत संरचना और सुविधाओं पर प्रादेशिक आंकड़ा आधार

प्रस्तुत अध्ययन डा. वाई पी अग्रवाल, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, सं. अ. प्र. प्र. एकक ने किया। यह यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित था तथा इसकी लागत 2000 अमरीकी डॉलर थी।

इस अध्ययन के निम्नांकित उद्देश्य थे :

किसी शैक्षिक ढांचे में पठन–पाठन का परिवेश विद्यालय प्रबंधन का एक प्रभावकारी और महत्वपूर्ण पक्ष है। इसका अधिगम के परिणाम से गहरा संबंध है। राज्य में साक्षरता का निम्न स्तर उस राज्य में तेजी से बढ़ती आबादी की मूलभूत शैक्षिक जरूरत को पूरा करने में शिक्षा प्रणाली की अपर्याप्तता को प्रतिबिंबित करता है। राज्य में औसत ग्रामीण महिला साक्षरता दरों में ग्रामीण–नगरीय असमानताएं अत्यंत सोचनीय थीं। (नगरीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर 50.4 और ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 19 प्रतिशत) प्राथमिक शिक्षा में सुलभता और भागीदारी की दृष्टि से इस प्रकार की असमानताएं व्याप्त हैं। समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में विशेषकर प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों के मामलों में ये समस्याएं अत्यंत ही चिंताजनक है।

इन वर्गों में प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी सर्वाधिक हैं। देश की कुल आबादी का 22 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति की आबदी का है। देश के लगभग आधे जिलों में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 10 प्रतिशत से भी कम है। यद्यपि इन सांख्यिकीय तथ्यों से साक्षरता की गुणवत्ता और संपूर्ण शैक्षिक संप्राप्ति के स्तर के बारे में जानकारी नहीं मिलती है फिर भी यह जाहिर है कि राज्य सार्वजनिक साक्षरता के लक्ष्यों और सबके लिए शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की यात्रा में अभी काफी पीछे है।

विविध स्रोतों से प्राप्त उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा से पता चलता है कि आम तौर पर विद्यालय परिवेश से संबंधित सूचना में परिमाण और गुणवत्ता, दोनों ही दृष्टियों से कमी है। भारत में राज्य

और केंद्र सरकार की नियमित शैक्षिक सांख्यिकी में विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता, विद्यालयी आधारभूत ढांचों के प्रकार और स्वरूप एवं आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता में आए क्रमशः परिवर्तन से संबंधित आंकड़ा शामिल नहीं होता है। यहां तक कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए अलग–अलग आकड़ा प्राप्त करना भी बहुत कठिन कार्य है।

## 5. प्राथमिक विद्यालय की धारणक्षमता और कार्यनिष्पादन में संगीत और खेलकूद का प्रभाव : उडांग का प्रयोग

नीपा ने प्राथमिक विद्यालय की धारणक्षमता और कार्य निष्पादन में "संगीत और खेलकूद का प्रभाव : उडांग का प्रयोग" विषय पर अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की। यह अध्ययन प्रो. एम. मुखोपाध्याय, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, शैक्षिक प्रशासन एकक, नीपा ने किया। अध्ययन की लागत रु. 20,000 थी।

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित थे :

(क) वर्ष 1993 और 1996 के बीच उपस्थिति के रूझान का अध्ययन करना,

(ख) वर्ष 1993 और 1996 के बीच विद्यालयत्याग की प्रवृत्ति में अगर कोई परिवर्तन है तो उसका अध्ययन करना;

(ग) कार्यनिष्पादन के स्तर का अध्ययन करना;

(घ) संगीत, खेलकूद संबंधी गतिविधियों पर अध्यापकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना;

(च) इस नवाचारी हस्तक्षेप/प्रयोग की इकाई लागत का अध्ययन करना।

इस अध्ययन के निम्नांकित निष्कर्ष हैं :

परियोजना अध्ययन पूरा होने और जुलाई 1998 में आई ई आर एस डी द्वारा इसकी पहली रिपोर्ट प्रकाशित होने के बीच संयोगवश अनेक विकास हुए हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, एस सी ई आर टी कोलकाता ने पिछले दो वर्षों के दौरान महती दिलचस्पी के साथ इस परियोजना का अनुकरण किया। एस सी ई आर टी ने परियोजना विवरण और संक्षिप्त रिपोर्ट की 55000 प्रतियां मुद्रित की और राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों और जिला परिषदों में उनका वितरण किया। आई ई आर एस डी और एस सी ई आर टी ने संयुक्त रूप से राज्य स्तरीय प्रमुख संगठनों और जिला परिषदों की शिक्षा समितियों के अध्यक्षों के साथ एक प्रचार–प्रसार कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्य के शिक्षा मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर केंद्र सरकार के शिक्षा सचिव मुख्य अतिथि थे। इलेक्ट्रानिक जन संचार माध्यमों और समाचार पत्रों ने इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार किया। इसके कुछ सार्थक और साकारात्मक प्रभाव और विकास निम्नांकित हैं :

(क) निजी तौर पर कई विद्यालयों और अध्यापकों ने मुद्रित पुस्तक से संगीत और खेलकूद

संबंधी कार्यकलाप अपनाना शुरू कर दिया है।

(ख) राज्य योजना बोर्ड के सदस्यों ने आरंभ में प्रखंड स्तर पर और तदुपरांत जिला स्तर पर परियोजना के विस्तार की संभावना का पता लगाने के लिए परियोजना निदेशक और अन्वेषक से भेंट की।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने विद्यालयों को अभिरुचिपूर्ण और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से उडांग माडल अपनाने/अनुकूलन के लिए पश्चिम बंगाल की प्राथमिक शिक्षा परिषद को 150 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की।

(घ) राज्य में डी पी ई पी के योजना कक्ष ने इस प्रयोग पर ध्यान दिया है और विद्यालय आकर्षण को बढ़ाने के लिए इस कार्यविधि के प्रयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यालय त्याग की समस्या ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको दूर नहीं किया जा सके। इसे दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में कई प्रावधान हैं। इसके लिए स्थान विशिष्ट गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन की आवश्यकता है।

**6. सांस्थानिक विकास और सांस्थानिक स्तर पर संसाधन योजना का निदानात्मक अध्ययन : मैसूर जिला के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर प्रायोगिक परियोजना :**

यह अध्ययन डा. (श्रीमती) वाई जोसेफिन, सह–अध्येता, नीपा ने किया। इस अध्ययन के निम्नांकित उद्देश्य थे :

(क) संस्थानों की समस्याओं की पहचान करना।

(ख) कालक्रम में संस्थानों के विकास का अध्ययन करना और उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना।

(ग) विद्यालय विकास के लिए भौतिक और गैर–मौद्रिक संसाधनों में सुधार के परिणाम का अध्ययन करना।

(घ) संस्थानों के गुणात्मक और मात्रात्मक विकास के संवर्धन के लिए मौद्रिक संसाधनों में सुधार का अध्ययन करना, और

(च) योजनाओं का प्रतिपादन करना और विकास के लिए कार्यक्रमों का सुझाव देना।

इस अध्ययन से पता चला कि निजी संस्थानों की तुलना में राजकीय संस्थानों में अपव्यय अधिक था। चूंकि निजी विद्यालय अधिक शुल्क लेते हैं, इसलिए अभिभावक विद्यालय से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के प्रयास करतें हैं। निजी विद्यालयों के बेहतर कार्य निष्पादन के महत्वपूर्ण पक्ष उनके साकारात्मक दायित्वबोध और जवाबदेही हैं। निजी विद्यालयों के बीच बढ़ती प्रतियोगिताओं के चलते अपेक्षित न्यूनतम सुविधाओं के लिए अपर्याप्त धनराशि के अभाव में भी वे अपने बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए पूरे दायित्व के साथ प्रयासरत रहे। कोई भी चमत्कार की आकांक्षा नहीं कर सकता है। यद्यपि संसाधन की प्रचुरता सांस्थानिक क्षमता और

गुणवत्ता की गारंटी नहीं है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि बेहतर कार्य निष्पादन में गैर–मौद्रिक संसाधन और उनकी समुचित योजना का अपना महत्व है।

राजकीय विद्यालयों के निम्न कार्यनिष्पादन का मुख्य कारण आधारभूत सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था में मानव संसाधन के विकास पर समुचित निवेश का अभाव है।

यह अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि गैर–मौद्रिक संसाधनों (भौतिक सुविधाओं) का कार्य निष्पादन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। इससे इस गलतफहमी को दूर किया जा सकता है कि सुविधाओं के लिए प्रचुर मात्रा में आवश्यक धनराशि (गैर–मौद्रिक भौतिक सुविधाओं) के बिना विद्यालय अपना कार्य निष्पादन बेहतर नहीं कर सकते। इसे प्रभावकारी प्रबंधन और न्यूनतम प्रभावी सुविधाओं तथा मानव संसाधनों से संभव बनाया जा सकता है।

### 7. जिला शिक्षा सूचना प्रणाली-चरण I

यह अध्ययन यूनिसेफ द्वारा प्रयोजित है। इसे डॉ. वाई पी अग्रवाल, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, सं. अ. प्र. प्र. एकक ने किया।

सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों के शिक्षा विभाग विद्यालयी सांख्यिकी से संबंधित आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण और प्रसारण कार्य से संबद्ध हैं। आमतौर पर आंकड़ा विद्यालयों से एकत्र किया जाता हैं। इसमें विद्यालय संबंधी सभी विवरण–विद्यालय की विशिष्टताएं, अध्यापक, भवन, साज सज्जा, सुविधाएं, नामांकन, कक्षा, लिंग और जाति के अनुसार विद्यार्थियों का विवरण है। हाल के वर्षों में आंकडा संग्रह, आंकड़ा प्रवाह और विश्लेषण की कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आंकड़ा के संबंध में इसकी वैधानिकता, पूर्णता, परिणामों की उपलब्धता में विलंब और अपेक्षित आंकड़ा की कमी संबंधी समस्याएं बताई जाती हैं। आंकड़ा संग्रह अपने आप में एक अंतिम प्रक्रिया नहीं है। यह आंकड़ा संग्रह कार्य पद्धति की प्रभाविता और दक्षता में सुधार का अनवरत प्रयास है।

डी आई एस ई–98 एक कंप्यूटर आधारित साफ्टवेयर है। शैक्षिक विकास के आवश्यक और व्यापक अनुश्रवण के लिए विभिन्न शैक्षिक सोपानों के स्तरों पर मुख्य कार्यनिष्पादनों के संकेतकों पर अत्यावश्यक सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से इस साफ्टवेयर में शैक्षिक आंकड़ा आधार का विकास किया गया हैं।

डी आई एस ई की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं :

(क) प्रक्रिया के आरंभ, आंकड़ा प्रविष्टि और अन्य दूसरे संचालन प्रक्रियाओं के दौरान स्वचालित विकल्प/बटन तथा अनुपलब्ध प्रयुक्त सुविधाएं हैं।

(ख) विद्यालय के लिए कोड एक बार में ही निर्धारित किया जा सकता है। विद्यालय कोड जनसंख्या कोड़ से अलग है और शैक्षिक जिला/पंजिकाओं पर आधारित है। इसमें विद्यालयों/गांवों/पंजिकाओं/स्कूलों को शामिल करने और हटाने का प्रावधान दिया गया है।

(ग) इसके द्वारा आंकड़ा संग्रह प्रपत्र में निर्धारित चरों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों/वर्गों के लिए विद्यालय स्तरीय आंकड़ा आधार तैयार किया जा सकता है।

(घ) प्रयोक्ता निर्धारित उपयोगी चरों के द्वारा जिला स्तर पर प्रयोक्ता विशिष्ट आंकड़ा प्रविष्टि के लिए सुविधाएं हैं।

(च) वार्षिक रूप से संदर्भ तिथि, 30 सितबर को आंकड़ा आधार को अद्यतन बनाया जाता है। कंप्यूटर द्वारा निर्मित विद्यालय कोड नहीं बदलता है। इससे विद्यालय स्तर पर देश कालिक विश्लेषण संभव हो जाता है।

(छ) इससे संस्था, संकुल संसाधन केंद्र, प्रखंड/तालुका/मंडल/एम सी, जिला और राज्य स्तर पर मुख्य शैक्षिक संकेतकों का सारांश तैयार किया जा सकता है। तुलनात्मक विश्लेषण से कार्य निष्पादन के मुख्य संकेतकों के अनुसार जिलों/ब्लाकों/संकुलों का वर्गीकरण किया जा सकता है।

(ज) राज्य स्तरीय ई एम आई एस द्वारा निरंतर और समान रूप से आंकड़ा प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए इसमें अनेक महत्वपूर्ण और उपयुक्त आंकड़ों को शामिल किया जा सकता है। जब जिला से राज्य स्तर पर आंकड़ा स्थानांतरित हो जाता है तो राज्य और जिला को प्रदर्शित करने के लिए एक कोड निर्मित हो जाएगा। साफ्टवेयर में 1991 की जनसंख्या के कोडों के आधार पर कोडीकरण की प्रणाली मौजूद है। 1991 के बाद नवगठित जिलों के लिए प्रयोक्ता कोड बना सकते हैं।

(झ) सतत आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए अलग से डी आई एस ई--98 के साथ एक आंकड़ा प्रविष्टि माड्यूल है। विभिन्न मशीनों के आंकड़ों को समस्त आंकड़ा आधार में एकीकृत किया जा सकता है।

## 8. जिला पेडेरू के 11 मंडलों में प्राथमिक शिक्षा कोर्ष चयन कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन

नीपा ने जिला पेडेरू विशाखापट्टनम के 11 मंडलों में प्राथमिक शिक्षा कार्यान्वयन कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन पर परियोजना अध्ययन के रूप यूनिसेफ, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय से संविदा के अंतर्गत अध्ययन किया। यह परियोजना अध्ययन डॉ. (सुश्री) के सुजाता, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय एकक, नीपा ने किया। इसकी अनुमानित लागत रु. 5,31,200/– थी।

अध्ययनों के प्रमुख उद्देश्य थे :

(क) प्रत्येक हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम की योजना और प्रशासन की प्रक्रिया का प्रलेख तैयार करना,

(ख) लक्ष्य की प्राप्ति में हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमों की प्रभाविता का अध्ययन करना,

(ग) हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमों की कमजोरियों और प्रभाविता की पहचान करना,

(घ) अत्यावश्यक समर्थन/संवर्धन/मजबूतीकरण के लिए सुझाव देना,

(च) कार्यक्रमों के भावी दिशा–निर्देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करना।

अध्ययन के निम्नांकित निष्कर्ष हैं :

यह कहा जा सकता है कि समुदाय लड़के और लड़कियों, दोनों के लिए शिक्षा के महत्व से पूर्णतः अवगत हैं। वे शिक्षा को अपनी नई पीढ़ी के बेहतर जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं और अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाना चाहते हैं। अधिकांश माता–पिता गुणवत्ता सुधार के कार्यान्वित नवीनतम कार्यक्रम के विभिन्न गतिविधियों और विद्यालयों के परिवर्तित कार्यकलापों को जानते थे। इस बदलाव के प्रति उनका सहयोग और स्वीकृति विद्यालयी तैयारी और विद्यालय में बच्चों की अभिरुचि संबंधी गतिविधियों तक सीमित थी। यद्यपि माता–पिता अधिगम साक्षरता और कौशलों के प्रति अधिक जिज्ञासु थे। शिक्षा व्यवस्था के प्रति उनका समर्थन बच्चों की प्रभावी पठन–पाठन संबंधी कार्यकलापों पर निर्भर करता है। सामुदायिक सदस्यों ने आनंददायी पठन–पाठन विधि के बारे में प्रबंधन और प्रभाव संबंधी कुछ मुद्दे उठाए। उनकी एकमात्र जिज्ञासा अपने आर्थिक सुधार को लेकर थी क्योंकि उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि शिक्षा के द्वारा उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। विद्यालय की सौंदर्यीकरण योजना में समुदाय की जागरुकता और समर्थन केवल कुछ ही मंडलों में देखा गया और वह भी केवल पहला प्रयास ही था। ग्राम शिक्षा समितियों ने विद्यालय और शिक्षा के प्रति अभिभावकों को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अध्यापकों का प्रशिक्षण आवश्यक है। परन्तु प्रशिक्षण कार्य के कारण अध्यापकों की अनुपस्थिति पर समुदाय को आपत्ति थी। समुदाय ने माना कि अगर अवकाश के दौरान अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाए तो अनुपस्थिति की समस्या को दूर किया जा सकता है। समुदाय के अधिकांश सदस्य एम आर पी प्रणाली से अवगत थे। उन्होनें बैठकों में शामिल होकर अध्यापकों का समर्थन किया। दोपहर का भोजन कार्यक्रम एक सफल और उपयोगी प्रयास माना गया है। आनंददायी अधिगम कार्यक्रम में समुदाय की रुचि बनाए रखने के लिए आई टी डी ए द्वारा निम्नांकित कदम उठाने की आवश्यकता है :

(क) विद्यालय के विकास संबंधी विविध गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता को बनाए रखने के उद्देश्य से विद्यालय सौंदर्यीकरण जैसे कार्यक्रमों को नियमित रूप से जारी रखा जाए।

(ख) ग्राम शिक्षा समिति और मां समिति को नियमित रूप से कार्यक्रम में अभिमुख किया जाए ताकि इन समितियों के सदस्य समुदाय को लामबंद कर अभिप्रेरित कर सकें।

(ग) एम आर पी समुदाय के निरंतर संपर्क में रहें और संमुदाय से संवाद स्थापित करते रहें और संपूर्ण आई टी डी ए में आनंददायी अधिगम कार्यक्रम की समस्त प्रगति के बारें में उन्हें सूचित करते रहें।

(घ) अध्यापक बच्चों की संप्राप्ति स्तर के बारें में उनके माता–पिता को बताएं। इससे बच्चों को घर से मदद मिलेगी।

(च) अध्यापक की अनुपस्थिति में किसी स्वयंसेवक या किसी वरिष्ठ व्यक्ति को विद्यालय खोलने और विद्यार्थियों को कार्ड बांटने का दायित्व सौंपा जाए। इससे नियमित रूप से विद्यालय चलाने और बच्चों की अभिरुचि को निरंतर बनाए रखने में मदद मिलेगी।

(छ) केवल अभिनय संगीत, कहानियां और पठन कार्यकलापों के माध्यम से लम्बे समय तक समुदाय की रुचि को बनाए नहीं रखा जा सकता है क्योंकि अंततः बाद की कक्षाओं में बच्चों की संप्राप्ति स्तर उनके लेखन कौशल पर निर्भर होता है। अतः बच्चों में लेखन क्षमता के विकास की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

## 9. प्राथमिक शिक्षा नवीकरण परियोजना के अंतर्गत शिक्षार्थी संप्राप्ति का अध्ययन (दिल्ली)

यह अध्ययन यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित और वित्तीय सहायता प्राप्त था। डॉ. वाई पी अग्रवाल, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, सं. अ. प्र. प्र. एकक ने यह अध्ययन किया। अध्ययन की कुल लागत रू. 5,30,000/– थी।

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य थे :

(क) कक्षा I और कक्षा IV के विद्यार्थियों की भाषा और गणित की दक्षताओं के आधार पर सम्प्राप्ति स्तरों को मापना,

(ख) विद्यालय प्रबंधन के प्रकार, विद्यार्थियों के लिंग और जाति के अनुसार सम्प्राप्ति स्तरों के बीच के अंतरों की समीक्षा करना,

(ग) विद्यालयों की विशेषताओं और विद्यार्थियों के कार्य विवरणों की समीक्षा करना, और

(घ) विद्यार्थी संप्राप्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना।

इस अध्ययन में निम्नांकित प्रमुख शिफारिशें की गईं और आशा व्यक्त की जाती है कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर इसका साकारात्मक प्रभाव होगा।

(क) निम्नांकित चार आवश्यक अवयवों की सम्मिलित करते हुए पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है :

- वास्तविक सख्त शैक्षिक मानक का निर्धारण
- इन मानकों के आधार पर विद्यार्थी संप्राप्ति स्तर के मापन के लिए तकनीकों का विकास करना। इससे अनुदेशी रणनीति और संसाधन वितरण में मौलिक परिवर्तन भी होंगे। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को संश्लिष्ट समय सीमा और सीमामुक्त आकलन के लिए पर्याप्त रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। इस दिशा में पहल के लिए अध्यापकों को पर्याप्त प्रशिक्षण और समर्थन, दोनों जरूरी हैं।
- प्रत्याशित संप्राप्ति स्तर प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, और

– निदानात्मक अध्यापन, विशेष अनुदेशी सामग्री और अन्य दूसरे उपायों के द्वारा चुनौतीपूर्ण मानकों को पूरा करने के लिए विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को अपेक्षित अवसर प्रदान करना।

(ख) पाठ्यचर्या विकास से संबंधित उन सम्मेलनों, संगोष्ठियों और संबंधित परियोजनाओं, जहां मौजूदा कार्यव्यवहारों और सुधारों पर चर्चाएं की जाती हैं, अध्यापकों को सहभागिता के अवसर प्रदान करना। इनमें अध्यापक मूल्यांकन और अपेक्षित प्रशिक्षण आकलन भी सम्मिलित होने चाहिए ताकि गुणवत्ता सुधार की उपयुक्त कार्यनीतियां लागू की जा सकें।

(ग) विद्यालय प्रबंधन के कार्यव्यवहारों का विश्लेषण भी आवश्यक है। राजकीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को विषय विशेषज्ञता के अलावा शैक्षिक प्रशासन में भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। अनेक विद्यालय प्रबंधन का आदर्श प्रस्तुत करते हैं जबकि अन्य विद्यालयों में प्रबंधन संबंधी कई प्रकार की समस्याएं मौजूद हैं। विद्यालय प्रबंधन संबंधी मुद्दों को उजागर करने के लिए कुछ केस अध्ययन भी किए जा सकते हैं।

(घ) सुविधाओं की उपयोगिता की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालने के लिए संमुचित अध्ययन की आवश्यकता हैं। यद्यपि ऐसा लगता है कि पर्याप्त संख्या में कक्षाओं के लिए कमरे हैं। मगर कुछ क्षेत्र ऐसे है जहां भीड़–भाड़ वाली कक्षाएं होती हैं।

## 10. भारत में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में अ-सरकारी संगठनों की भूमिका और योगदान

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य थे :

(क) भारत में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न प्रकार के अ–सरकारी संगठनों की वर्तमान अवस्थिति और भूमिका की समीक्षा करना;

(ख) देश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में अ–सरकारी संगठनों के संपूर्ण योगदान का आकलन करना;

(ग) बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कुछ चुनिंदा अ–सरकारी संगठनों की कार्यनीतियों और अपनाई गई प्रक्रियाओं का सघन अध्ययन करना।

मौजूदा अ–सरकारी संगठनों (अ.स.सं.) के बीच अनेक भिन्नताओं के बावजूद उनमें कुछ समानताएं हैं। अ.स.सं. सीधे जनता तक लाभकारी कार्यक्रम पहुंचाते हैं। वे पिछड़े और दूरवर्ती क्षेत्रों में आधारभूत स्तर पर काम करते हैं, इसलिए उनकी पहुंच बहुत व्यापक है और वे यर्थाथ के बहुत निकट होते हैं और समुदाय की जरूरतों को बखूबी जानतें हैं। लक्ष्यवर्ग से उनका सीधा संपर्क होता है और उनकी कार्यविधि बहुत प्रभावशाली होती है, इसलिए वे कार्ययोजना को और अधिक स्थानीय बनाने में समर्थ हैं। वे जनता के साथ आत्मीय संबंध रखते हैं और उनमें आत्मविश्वास पैदा करते हैं।

वे अपने कार्यकलापों की विशेषता और स्वभाविकता से जन भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और

समुदायों के बीच जागरुकता पैदा करते है। वे प्रारंभिक शिक्षा के समर्थन में विभिन्न लोगों की सहभागिता हासिल करते हैं। वे स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार के द्वारा शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण का विकास कर सकते हैं। वे समुदायों को लामबंद करते हैं और एक ऐसी संस्कृति के निमार्ण में जनसहभागिता का समर्थन करते हैं जिनमें जनता अपने अधिकारों और प्राथमिकताओं की स्वयं मांग उठाती है। वे अपने कार्य के स्वरूप और आकार के बल पर जन विश्वास हासिल करके उनसे गहरा संबंध रखते हैं। बेहतर शिक्षा के लिए सामुदायिक संसाधनों, ज्ञान और कौशलों के उपयोग के लिए जनता को अभिप्रेरित करना उनके लिए आसान कार्य है। अ–सरकारी संगठनों को गांवों के बारे में गहरी जानकारी है। वे गांवो की शैक्षिक समस्याओं और गरीबी के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं।

अ–सरकारी संगठन सार्थक शिक्षा के विकास में सरकार की मदद कर सकते हैं। वे सरकार और समुदाय के बीच संबंध स्थापित करने में सहायक हो सकते हैं। समस्या का विस्तार इतना व्यापक है कि इससे केवल अपने क्षेत्रों में सक्रिय अ–सरकारी संगठनों के सहयोग से ही निपटा जा सकता है। सरकारी तंत्र इतने बड़े देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वे सरकारी आधार का विस्तार करने में मददगार सिद्ध हो सकते हैं।

## 11. प्रखंड संसाधन केंद्रों और संकुल संसाधन केंद्रों की गतिविधियां और संसाधन उपयोग का विश्लेषण : मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का केस अध्ययन

यह अध्ययन डॉ. (श्रीमती) वाई. जोसेफिन, सह–अध्येता ने किया। इसके लिए वित्तीय सहायता डी पी ई पी ब्यूरो ने दी। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे :

(क) बैतूल जिले में प्रखंड संसाधन केंद्रों के साथ डाइट तथा संकुल संसाधन केंद्रों की सहभागिता प्रक्रिया की समीक्षा करना;

(ख) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भौतिक लक्ष्य और संप्राप्तियों का लागत के अनुसार मापन करना और उपयोगिता के स्वरूप का अध्ययन करना;

(ग) उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां डी. पी. ई. पी निधि का अपव्यय हुआ है;

(घ) अंतिम लाभार्थियों पर अध्यापक प्रशिक्षण के प्रभाव का अध्ययन करना;

अंतिम अध्याय में शोधकर्त्ती ने यह निष्कर्ष निकाला है कि शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को उठाने में अध्यापक प्रशिक्षण की प्रभावकारी भूमिका होती है। बेहतर कौशल और दक्षता से परिपूर्ण एक अच्छा अध्यापक भावी पीढ़ियों में सफल और उदीयमान नागरिक बनाकर अपनी सफलता का परिचय दे सकता है। प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अध्यापकों की गुणवत्ता में सुधार की परम आवश्यकता है। मध्य प्रदेश ने इस प्रयोजना से केंद्र प्रायोजित डी पी ई पी योजना को कार्यान्वित किया। इस दिशा में राज्य के प्रयास अग्रणी और प्रेरणादायी थे। प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का संपूर्ण दायित्व मुख्यतः डाइट पर था। इसके लिए अनेक कार्यनीतियां बनाई गईं, जैसे – डी आर पी समूह का निर्माण, प्रमुख प्रशिक्षण इलेक्ट्रानिक पठन–पाठन सामग्रियों का विकास। यद्यपि इन गतिविधियों के लिए

आवंटित धनराशि का कम उपयोग किया गया। संभवतः उपयुक्त कार्यनीतियों के उपयोग करने की क्षमता की कमी या कोई अन्य कमियां इसके कारण हो सकती हैं। स्थानीय संसाधन संस्थाओं की इस विशेष समस्या को समझने के लिए प्रस्तुत अध्ययन किया गया है और बैतूल जिला के संसाधन संस्थानों के व्यावहारिक कार्यकलापों और संसाधन उपयोग के स्वरूप और प्रवृत्ति की समीक्षा की गई है। यह एक ऐसा जिला है जिसमें प्रखंड संसाधन केंद्रों और संकुल संसाधन केंद्रों के लिए आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया है। इसमें धनराशि के उपयोग में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है।

**12. आदिवासी क्षेत्रों में समुदाय की सहभागिता : आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम में मांबाडी (सामुदायिक विद्यालयों) का अध्ययन**

यह अध्ययन डॉ. (सुश्री) के. सुजाता, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय एकक ने किया। इसके मुख्य उद्देश्य थे;

(क) समुदाय द्वारा विद्यालयों की योजना और प्रबंधन प्रक्रिया का अध्ययन करना;

(ख) विद्यालय संचालन में समुदाय की भागीदारी और लामबंदी की प्रक्रिया की समीक्षा करना;

(ग) विद्यालय–समुदाय संबंधों और ग्राम समितियों की भूमिका तथा स्वरूप की समीक्षा करना, और

(घ) इन विद्यालयों के स्थायित्व और प्रसार की संभावनाओं का अध्ययन करना।

इन विद्यालयों के विविध पक्षों और संपूर्ण प्रक्रिया के विश्लेषण के बाद यह कहा जा सकता है कि मांबाडी की अवधारणा प्रादेशिक और क्षेत्र विशिष्ट है। इसका आरंभ वंचित और दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था परंतु इसकी पूर्व प्रकृति और उद्देश्य कायम नही रहे। अब इसका उपयोग कम लागत की शिक्षा सुविधाओं के रूप में किया जाने लगा तथा उन क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय खोले गए जहां औपचारिक विद्यालय खोले जा सकते हैं। समान परिवेश और संदर्भ के अंतर्गत मांबाडी के आदर्श का अनुकरण करते समय अध्यापक दक्षता, विकेंद्रित प्रशासन, परियोजना माडल के केंद्रबिंदु और सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। इसका संयोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि समुदाय और प्रशासन के संयुक्त दृष्टिकोण के अनुसार मानदंडों, नियमों, नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन हो।

**13. जनसाधारण के गुणवत्ता विद्यालय के रूप में नवयुग विद्यालय**

यह अध्ययन डॉ. (श्रीमती) सुदेश मुखोपाध्याय, अध्येता, विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक ने किया। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे :

(क) परिवर्तन के कारकों को केंद्र में रखकर नवयुग विद्यालयों की मूलभूत योजना में आए परिवर्तनों की पहचान करना;

(ख) क्या नवयुग विद्यालय अभी भी जनसाधरण के लिए गुणवत्ता पूर्ण विद्यालय हैं, इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करना;

(ग) नवयुग विद्यालयों की मौजूदा स्थितियों का अध्ययन करना;

(घ) गुणवत्तापूर्ण विद्यालय के रूप में नवयुग विद्यालयों की विशेषताओं की आलोचनात्मक समीक्षा करना;

(च) नवयुग विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण विद्यालय बनाये रखने के लिए सुझाव देना

नवयुग शिक्षा सोसायटी की नीति का मूलभूत उद्देश्य माता–पिता की आय और स्थिति के कुछ निर्धारित प्रतिमानों के साथ दिल्ली के जनसमान्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यद्यपि प्रशासनिक प्रविधियां और नैसर्गिकता एक विकासशील और सुधारोन्मुख प्रक्रिया हो सकती है; फिर भी मिशन के उद्देश्य और साथ ही साथ उद्देश्य को मूर्त रूप देने की कार्यान्वनकारी प्रक्रिया पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करने की आवश्यकता है। यह सिफारिश की जाती है कि अपने अस्तित्व के 27 वर्षों बाद नवयुग विद्यालय शिक्षा सोसायटी माता–पिता, वर्तमान विद्यार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों, संकाय और स्टाफ, शिक्षाविदों, प्रशासकों और राजनीतिज्ञों को एक मंच पर लाए और नैसर्गिक प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2000 और उससे आगे के एन डी एम सी विद्यालयों के स्वरूप पर गंभीरता पूर्वक विचार करे। दिल्ली के नवोदय विद्यालय और प्रतिभा विद्यालय के बीच परस्पर अनुक्रिया के द्वारा भी कुछ सीख हासिल की जा सकती है। नवयुग विद्यालय शिक्षा सोसायटी के संदर्भ में नैसर्गिक प्रतिभा की अवधारणा के सम्मुख शैक्षिक उत्कृष्टता को व्यवहारिक रूप में निर्धारित करने की आवश्यकता है। इससे निश्चित रूप से संपूर्ण प्रणाली को नवजीवन प्राप्त होगा और एन डी एम सी के दूसरे विद्यालयों का स्तरोन्नयन करने में भी योगदान होगा।

## 14. भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति और समस्याएं

यह अध्ययन सुश्री जयश्री जलाली, सह अध्येता ने किया। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नालिखित थे:

(क) प्रारंभिक शिक्षा के विकास की स्थिति की समीक्षा करना;

(ख) महिला और बालिका साक्षरता की समस्याओं को समझना;

(ग) कम महिला साक्षरता वाले जिलों का विश्लेषण करना, और

(घ) हस्तक्षेपकारी कार्यनीतियों का विकास करना।

यह अध्ययन पूरा हो गया है और इसमें कार्रवाई के लिए निम्नांकित महत्वपूर्ण कार्यनीतियों की सिफारिश की गई है :

(क) विद्यालय संघटन के नेटवर्क के द्वारा प्राथमिक और अनौपचारिक विद्यालयों तथा शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा की अभिबिंदुता;

(ख) विद्यालय संघटन के द्वारा मिडिल और हाईस्कूलों की अभिबिंदुता;

(ग) आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण और विशेषकर बालिकाओं के लिए साक्षरता और प्रारंभिक शिक्षा अभियान में समुदाय की सह–भागिता सुनिश्चित करना और ग्राम शिक्षा समिति का उपयोग करना;

(घ) स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल पोषण और दूसरे विकास कार्यक्रमों के अपेक्षित समेकन के लिए व्यापक रूप से प्रशासनिक प्रखंडो का विकास करना ताकि शिक्षा में बेहतर सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अंतरविभागीय संसाधनों की साझेदारी के साथ प्रत्येक प्रखंड में आर्थिक सुविधाओं का निर्माण हो सके;

(च) व्यष्टि स्तरीय योजना तकनीकों के द्वारा शैक्षिक योजना के विकास के लिए स्थानीय योजना और प्रखंडों तथा गांवों की अलग स्वायत्तता पर बल;

(छ) राज्य विश्वविद्यालयों और स्वायत्त जिला परिषदों को अपनी भाषाएं और पाठ्यपुस्तकें विकसित करने की अनुमति देना जो उनके परिवेश के अधिक अनुकूल हो।

(ज) राज्यों और जिलों की विशेष समस्याओं पर कार्य करने के लिए कोर समूह का गठन करना और उन्हे एन सी ई आर टी/ नीपा तथा प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्यापक पशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों से संबद्ध करना।

## 15. भारत में अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

यह अध्ययन डॉ. (श्रीमती) नलिनी जुनेजा, अध्येता ने किया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अनिवार्य शिक्षा की नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था। यह अध्ययन निम्नांकित प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया :

(क) स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद अनिवार्य शिक्षा के कार्यान्वयन संबंधी दस्तावेजों की समीक्षा करना, और

(ख) वर्तमान में अनिवार्य शिक्षा के संबंध में शैक्षिक प्रशासकों की जानकारी और इसके प्रति उनकी मनोवृत्तियों का अध्ययन करना।

इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष थे :

(क) प्रकाशित दस्तावेजों से पता चलता है कि अनिवार्य शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 45 का निर्देश वस्तुतः 1950 के दशक में और 1960 के दशक के आरंभ में अनेक राज्यों में लागू किया गया;

(ख) 1960 के दशक के आरंभ में विद्यालयों में बच्चों को लाने के लिए अभिप्रेरणात्मक उपायों के प्रयोग के समर्थन के कारण अनिवार्यता पर विराम लगा दिया गया;

(ग) अनिवार्यता के प्रयोग पर इतना पूर्ण विराम लगा कि शैक्षिक प्रशासकों की मौजूदा पीढ़ी के 90 प्रतिशत प्रशासक उन कानूनों से अनभिज्ञ हैं जिनके द्वारा सरकार अपने राज्य के मौजूदा विद्यालयों में बच्चों को दाखिल कराने के लिए माता–पिता को विवश कर सकती है।

(घ) सभी बच्चों–लड़के/लड़कियों, अमीर/गरीब को बुनियादी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। आज इसके समर्थन में सभी शैक्षिक प्रशासक हैं। इनमें लगभग 40 प्रतिशत यह मानते हैं कि माता–पिता/अभिभावकों को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। वे ऐसे किसी कानून के पक्ष में भी नहीं हैं जिससे सरकार माता–पिता/अभिभावकों को बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए मजबूर कर सके।

(च) दिल्ली के नगर निगम विद्यालयों के प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक (ये गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दिहाड़ी पर कार्यरत हैं) दूसरे राज्यों और अन्य स्तरों पर कार्यरत शैक्षिक प्रशासकों की तुलना में अनिवार्य शिक्षा के कानूनी प्रावधानों के जोरदार समर्थक हैं।

### 16. अवस्नातक कार्यक्रमों का व्यावसायीकरण : एक प्रायोगिक अध्ययन

यह अध्ययन डॉ. (श्रीमती) सुधा राव, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, शैक्षिक नीति एकक ने किया। इसकी लागत रु. 37,500 थी।

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य थे :

(क) व्यावसायीकरण की योजना की परिकल्पनाओं, विश्वासों और इसके प्रति विचारों को प्रकाश में लाना;

(ख) उच्च शिक्षा के व्यावसायिक कार्यक्रमों की योजना, प्रबंधन और कार्यान्वयन से संबद्ध व्यक्तियों की आकांक्षाओं को समझना;

(ग) वास्तविक रूप में कार्यान्वित योजना और संरचना, कार्यकलापों तथा वित्त व्यवस्था आदि के अनुसार उपलब्ध कराए गए आगतों का अध्ययन करना;

(घ) दिल्ली के कालेजों में कार्यान्वित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित आंकड़ा और सूचना प्रकाश में लाना;

(च) सुधार के लिये सुझाव देने के उद्देश्य से वास्तविक कार्यान्वयन की कमजोरियों और प्रभावी शक्तियों की पहचान करना।

इस अध्ययन में निम्नांकित सुझाव दिए गए हैं :

(क) सभी कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा के दिनोंदिन की गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए एक सक्रिय और प्रभावकारी सलाहकार परिषद का गठन किया जाना चाहिए।

(ख) वि. अ. आ. को व्यावसायिक विषयों के लिए अलग विभाग बनाने और इसके लिए स्थाई अध्यापक नियुक्त करने पर विचार करना चाहिए।

(ग) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए कालेजों को समुचित आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

(घ) प्रत्येक सत्र के आरंभ में आकस्मिक मद में पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएं।

(च) पाठ्यक्रमों के लिए बोधात्मक पाठ्यपुस्तकें तैयार की जाएं और तत्काल प्रकाशित की जाएं।

(छ) मौजूदा जरुरतों को ध्यान में रखकर उपयुक्त पाठ्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित की जाए और उनमें संशोधन किया जाए।

(ज) सभी विश्वविद्यालयों के लिए रोजगार/ग्रीष्म कालीन प्रशिक्षण हेतु समान मार्गदर्शिकाएं हों। इनका सख्ती से पालन किया जाए।

(झ) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबद्ध संकाय के लिये नियमित रूप से अभिविन्यास और पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ;

(ट) अतिथि संकाय के लिए आकर्षक पारिश्रमिक का प्रावधान हो ;

(ठ) उद्योगों और सेवाक्षेत्रों के साथ प्रबल संबद्धता और सहयोग ;

(ड) क्षेत्रीय और कालेज स्तर पर आवश्यक रूप से उद्यमशीलता पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं;

(ढ) सहयोजकों और लाभार्थियों को आकर्षित करने के लिए व्यापक आधारयुक्त संचेतना कार्यक्रम आयोजित किया जाए। सफल व्यक्तियों की प्रेरणादायी कहानियां तैयार की जाए और टी वी तथा जनसंचार माध्यम के जरिए इनका प्रचार–प्रसार किया जाए।

(त) विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंतिम उपाधि पत्रों को बी. ए. (पास) व्यावसायिक नाम दिया जाए।

## 17. शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिये सघन क्षेत्र कार्यक्रम के प्रभाव के आकलन हेतु प्रतिदर्श सर्वेक्षण

उपरोक्त अध्ययन डा. सुश्री प्रमिला मेनन, अध्येता द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे :

i) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के सघन क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षण ढांचा और सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित योजना का आकलन करना,

ii) उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिये उपयोगिता के दृष्टिकोण से क्रियान्वित ढांचे का आकलन,

iii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के ढांचे और क्रियान्वयन के अंतर को ध्यान में रखते हुये योजना में परिवर्तन के लिये सुझाव देना।

अध्ययन से उभरने वाले सुझाव निम्न प्रकार से हैं :

i) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिये सघन क्षेत्र कार्यक्रम केवल अल्पसंख्यक

क्षेत्रों के लिये ही अनुप्रयोज्य है जिन्हे कल्याण मंत्रालय द्वारा चिन्हित किया गया है। तदनुसार राज्यों से अनुरोध किया गया कि वह केवल इन्हीं क्षेत्रो में आधारभूत सुविधाओं के सृजन और परिवर्धन के लिये प्रस्ताव भेजे। तथापि, कुछ ऐसे क्षेत्र भी चिन्हित हो गये जो कि अल्पसंख्यक घनत्व वाले क्षेत्र नही थे। नये विद्यालयों को खोलने के लिये आवश्यकता के निर्धारण हेतु विद्यालय मानचित्रण कार्य अनिवार्य रूप से किया जाये।

ii) यह राज्यों का प्रमुख दायित्व है कि वे योजना को लागू करें तथा शैक्षिक अल्पसंख्यकों के शिक्षा के स्तर में सुधार कर सके। जब तक राज्य सरकार इस दिशा में अपना सहयोग प्रदान नहीं करेगी तथा सरकारी नीति का क्रियान्वयन गंभीरता पूर्वक ठीक तरह से नही करेगी, तब तक, योजना का वांछित प्रभाव प्राप्त नही होगा।

iii) सभी राज्यों को एक ऐसी व्यवस्था का उत्सर्जन करना होगा जिसके माध्यम से वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप कार्य का सूत्रपात तथा प्रभावी अनुश्रवण व्यवस्था को सम्पोषित कर सकें।

iv) विशेषतौर से लक्ष्य समूह के बीच योजना के प्रति पर्याप्त जागरुकता के लिये राज्य सरकार को कदम उठाने चाहिये। इस प्रकार वे राज्य के प्रयासों से लाभ उठा सकेंगे।

v) योजना के अंतर्गत समयबद्ध ढंग से प्रस्तावों का क्रियान्वयन इसका विस्तार तथा संचालन क्षेत्रों का और अधिक सरलीकरण करेगा। इस प्रकार इससे लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होगी।

vi) भवन तथा भवन निर्माण के लिये वित्त का आवंटन वर्तमान उपयोगिता और भविष्य के लिये उन्नतिशील योजना का आकलन करने के बाद ही किया जाये। निर्माण कार्य का अनुकरण भी किया जाये।

## 18. साक्षरता कार्यक्रमों की योजना और संचालन : प्रखंड स्तर के अनुभवों के पाठ

उपरोक्त अध्ययन नीपा सहायता योजना के अंतर्गत रु. 87,600/– की लागत से प्रो. आर. भारद्वाज, अध्यक्ष, शैक्षिक अनुसंधान एंव विकास संस्थान, बेंगलौर का स्वीकृत किया गया था। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे :

i) आंदोलन को बल पहुंचाने वाले संस्थागत ढांचे और स्वयं आंदोलन की गति के आपसी संबंधों का अध्ययन करना।

ii) इसमें प्रशिक्षित व्यक्तियों के परवर्ती जीवन के परिदृश्य तैयार करना और इस तरह इस बात का आकलन करना कि क्या साक्षरता के लाभार्थी उसकी सहायता से अपना जीवन सुधार सकते हैं।

अध्ययन के कुछ सुझाव निम्न प्रकार से है :

i) उत्तर–साक्षरता स्वयंसेवकों के लिये अभिविन्यास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

ii) उत्तर–साक्षरता सामग्री को इस प्रकार पुनः रूपांकित करना कि यह भागीदार के व्यवसाय से संबधित हो। चूंकि प्रौढ़ शिक्षार्थी की अधिगम रुचि महत्वपूर्ण है, इसलिये अध्ययन सामग्री उसके परिवेश से संबंधित हो तथा उसके व्यवसाय से संबंधित हों।

iii) विकास कार्यकर्त्ताओं की मदद से क्षमता निर्माण और क्षमता वृद्धि के लिये कार्यक्रमों का आयोजन करना (विद्यालय स्तरीय कार्यकर्त्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, सफाई तथा स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता तथा आधारभूत स्तर पर अन्य कार्यकर्त्ता) यह क्षमता संप्रेषण क्षमता, उत्तरजीविता क्षमता, व्यावसायिक क्षमता, उद्यमी तथा प्रबंधन क्षमता इत्यादि हो सकती हैं।

iv) उनके बारे मे और उनके व्यवसाय के बारे में रुचि उत्पन्न करने के लिये और अधिक जानकारी हेतु सुस्पष्ट मुद्रण और निदर्शन के साथ विविध व्यावसायिक गतिविधियों के प्रसंग में सरल समाचार मदों के साथ कम लागत वाली सूचना पत्रिका विकसित की जाये।

v) अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिये उत्तर – साक्षरता केन्द्रों में एक आन्दोलन के रूप में पुस्तकालय सेवाओं का निर्माण करना।

vi) कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यक्तियों, समूहों तथा संस्थानों द्वारा अच्छे, गुणात्मक तथा सकारात्मक कार्य का अभिज्ञान एवं योजना का उत्सर्जन वांछनीय और आवश्यक है।

## 19. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों का समय प्रबंधन

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों के समय प्रबंधन पर अध्ययन की स्वीकृति डॉ. सिंथिया पाण्डियन, उपाचार्य, शिक्षा विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय को नीपा सहायता योजना के अंतर्गत शैक्षिक योजना और प्रशासन में अध्ययन के लिये दी गई। अध्ययन की लागत 64,680 रूपये थी।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं :

(i) प्राचार्यों के समय प्रबंधन के विभिन्न पक्ष

(ii) प्राचार्यों के समय प्रबंधन में अंतर, और

(iii) स्वग्रहीत समय नष्ट करने वाले और प्रतिदिन के कार्यकलापों और समय के साथ तालमेल बनाकर काम करने के प्राचार्यों के प्रतिमान की पहचान करना।

शिक्षा संसार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। विद्यालय की उत्कृष्टता बनाये रखने के लिये

प्राचार्यों को विकास के नये आयामों से परिचित रहना चाहिए। कार्य के दौरान वह निरंतर शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। उन्हें आलोचनात्मक और विचारशील सोच आत्मसात करनी पड़ती है। अगर कार्य का वर्णन स्पष्ट रूप से किया जाये तो समय को अधिक उर्वरता के लिये आवांटित किया जा सकता है। इसलिये यह आवश्यक है कि प्रचार्यों को लक्ष्य निर्धारण, प्राथमिकता निर्धारण, संप्रेषण रणनितियों के उत्सर्जन, जनसंपर्क रणनीतियों, मीडिया, विद्यालयों में जनता के दक्षता विश्वास को प्रोत्साहन, संघटनात्मक सिद्धांत, विद्यालय उत्सर्जन को बनाये रखना तथा उसके सुधार, विद्यालय संस्कृति को दिशा तथा परिवर्तित करना, शैक्षिक विवाद को समझना, राजनैतिक परिवेश को समझना, विद्यालय पुनर्गठनात्मक मॉडल, योजना के प्रकार और सिद्धान्त, प्रदत्त कार्यों, स्टाफ विकास, मापन तथा मूल्यांकन, संसाधन आबंटन, प्रेरणा, अंतर कार्मिक क्षमता, भूमिका तथा नेतृत्वकारी सिद्धान्त, कार्यात्मक क्षमता, प्रबंधन सूचना व्यवस्था, निर्णयकारी व्यवस्था, परस्पर–विरोधी प्रबंधन, समस्या निवारण, समस्या मूल्यांकन, भूमिका और नीतियों का स्पष्ट रूप से निर्धारण, कार्य–अभिविन्यास, नवाचार प्रवृत्ति, जोखिम लेना, विद्यालय के भविष्य के लिये लक्ष्य तथा दूर दृष्टि, आम उदासीनता तथा दबाव प्रबंधन से बचने के लिये रणनीति, वर्तमान में जीने के लिये दक्षता, शैक्षिक प्रशासन तथा परिवर्तित मॉडल के सरलीकरण हेतु अनिवार्य रूप से नियतकालिक पुनश्चर्या तथा अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये।

## 20. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों में व्यय प्रतिमान का विश्लेषण : डॉ. वाई. पी. अग्रवाल

### जारी/स्वीकृत अध्ययन

### 1. दूसरा अखिल-भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण परियोजना

यह परियोजना 19.84 लाख रुपये की राशि के साथ स्वीकृत की गई। नीपा के वरिष्ठ संकाय सदस्य डा. एम मुखोपाध्याय, डा. आर गोविन्द, डा. जे. बी जी तिलक, डा. वाई पी अग्रवाल, डा. एन वी वर्गीस और डा. के सुजाता विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षण के प्रभारी हैं।

यह सर्वेक्षण सभी राज्यों/संघीय क्षेत्रों और केंद्र में शैक्षिक प्रशासन का एक व्यापक अध्ययन है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं : (अ) विभिन्न स्तरों पर संरचनाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की दृष्टि से शैक्षिक प्रशासन की वर्तमान स्थिति को समझना, (ब) प्रयोगों, परिवर्तनों और प्रवर्तनों का अध्ययन करना, (स) शैक्षिक योजना और प्रशासन के प्रमुख मुद्दों और भावी दायित्वों की निशानदेही करना।

सर्वेक्षण में सचिवालय, निदेशालय और निरीक्षणालय स्तर पर शिक्षा विभागों के सांगठनिक ढाचों, उनकी भूमिका, कार्यों और गतिविधियों को, विभिन्न प्रबंधमंडलों तथा शिक्षा विभाग से दूसरे विभागों के तहत आने वाली संस्थाओं को समेटा गया है। इसका प्रमुख केंद्र बिन्दु विद्यालय शिक्षा का प्रशासन है।

संस्थान की ओर से विकास पब्लिशिंग हाउस दिल्ली द्वारा अरुणाचलप्रदेश, असम, बिहार, केरल,

पंजाब, मिजोरम, गोवा, हरियाणा, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान–निकोबार द्वीपसमूह, राजस्थान, त्रिपुरा, हिमाचलप्रदेश, और उत्तरप्रदेश के सर्वेक्षण की रिपोर्टें समूल्य प्रकाशित की जा चुकी हैं।

दिल्ली, उडीसा, केंद्र सरकार तथा मेघालय की रिपोर्टें प्रेस में हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महाराष्ट्र, दमन व दिव तथा पांडिचेरी की रिपोर्टें अंशतः संशोधित की गई हैं। गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, दादरा व नागर हवेली, जम्मु–कश्मीर, और आंध्रप्रदेश की रिपोर्टें तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं।

## 2. भारत में महिला अध्ययन केंद्रों की योजना और प्रबंधन

अध्ययन के उद्देश्य हैं : केंद्र, राज्य, विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तरों पर, भारत में महिला अध्ययन केंद्रों के विकास के लिए किए गए प्रयासों और की गई पहलकदमियों को समझना तथा महिलाओं के विकास के लिए महिला अध्ययन केंद्रों द्वारा की गई पहलकदमियों की जानकारी हासिल करना; वास्तविक शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार करके महिला विकास से जुड़े केंद्रों का मूलभूत, मान्य और वास्तविक कार्यान्वयन, महिला कार्यकत्ता समूहों, गैर–सरकारी संगठनों, प्रौढ़ शिक्षा विभागों और विस्तार विभागों द्वारा किए प्रयासों की पुनरावृत्ति और उनके दोहराव का विश्लेषण, नीति, योजना और प्रबंधन में अंतरालों का पता लगाना जिसके लिए महिला अध्ययन केंद्रों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है और अंत में उपर्युक्त के आधार पर महिला विकास के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिला अध्ययन केंद्रों के संसाधनों का कारगार उपयोग करने के लिए ऊपर सुझाई गई योजना और प्रबंधन कार्यनीतियां सुझाना।

साहित्य समीक्षा पूरी हो गई है। प्रश्नावलियां विकसित कर ली गई हैं और महिला अध्ययन केंद्रों, विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों तथा महिला विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों को दे दी गई हैं। महिला अध्ययन केंद्रों और शिक्षकों से आंकड़े एकत्र करने का काम पूरा कर लिया गया है। यह परियोजना आंकड़ा विश्लेषण और रिपोर्ट लिखने के चरण में है।

इस परियोजना का संचालन प्रो. के. सुधा. राव और डॉ. कौसर विजारत कर रही हैं।

## 3. जि. प्रा. शि. का. डी. पी. ई. पी. के अंतर्गत विविध गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये दिनांक 20.1.2000 से 19.1.2001 तक नीपा और मा. सं. वि. मंत्रालय, शिक्षा विभाग के बीच समझौता

पिछले समझौते को जारी रखते हुये नीपा ने उपरोक्त अवधि के लिये जि. प्रा. शि. योजना के अंतर्गत विविध अकादमिक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये शिक्षा विभाग के साथ उपरोक्त अवधि के लिये 41,80,000 रुपये की लागत के साथ नया समझौता किया। जि. प्रा. शि. कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किये जाने वाली गतिविधियां निम्न प्रकार से थी :

(i) प्रशिक्षण कार्यक्रम

- विद्यालय मानचित्र और सूक्ष्म योजना
- सीमेट और उसकी गतिविधियों पर बैठक
- शिक्षा की गुणवत्ता योजना के लिये परिमाणात्मक शैक्षिक अनुसंधान प्रणाली।

(ii) अनुसंधान अध्ययन :–

- पुस्तकालय/प्रलेखन केन्द्र तथा सूचना सेवाओं का आधुनिकीकरण
- प्रखण्ड संसाधन केंद्रों की भूमिका और कर्त्तव्यों का अध्ययन : वर्तमान स्थिति तथा भविष्य परिदृश्य
- विद्यालय सुधार के संकेतकों की पहचान और विकास
- शिक्षा की मांग पर जि. प्रा. शि. कार्यक्रम के हस्तक्षेप का प्रभाव : उड़ीसा में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का अध्ययन
- प्राथमिक विद्यालयों में बालिका नामांकन तथा अवधारण पर ई. सी. सी. ई. योजना का प्रभाव : दो राज्यों का तुल्नात्मक अध्ययन
- वी. ई. सी. के लिये प्रशिक्षण माड्यूल के सारांश के मूल्यांकन पर अध्ययन

## 4. आप्रेशन ब्लैकबोर्ड योजना का क्रियान्वयन और प्रभाव : राष्ट्रीय मूल्यांकन

मा. सं. वि. मंत्रालय, शिक्षा विभाग के अनुरोध पर नीपा ने आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना का क्रियान्वयन और प्रभाव पर राष्ट्रीय मूल्यांकन कार्यक्रम प्रारंभ किया। अध्ययन का कार्य डा. आर गोविन्द वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, अनौपचारिक शिक्षा एकक नीपा को सौंपा गया है। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं :

i) आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना के वृहद आयामों के संदर्भ में हुई प्रगति का आलोचनात्मक मूल्याकंन। यह मूल्याकंन राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 में वर्णित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों और उनके तदनन्तर में आठवी योजना में वर्णित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

ii) दो या तीन शिक्षक वाले विद्यालयों के गुणात्मक प्रभाव का अध्ययन तथा प्राथमिक विद्यालयों के कार्य में महिला अध्यापकों की नियुक्ति का अध्ययन। इसके अतिरिक्त विशिष्ट तौर पर नामांकन और धारण क्षमता के संदर्भ में योजना का समूल प्रभाव का अध्ययन करना।

iii) योजना के तीनों लक्ष्यों के अंतर्गत विशिष्ट लक्ष्यों की उपलब्धता स्तर का अध्ययन। यह तीनों लक्ष्य इस प्रकार से हैं : दो अध्यापक विद्यालय, दो अध्यापन कक्ष तथा न्यूनतम अध्यापन अधिगम उपकरण (टी. एल. ई.) तथा प्राथमिक विद्यालय व्यवस्था पर विभिन्न राज्यों में इनका प्रभाव।

iv) स्थानीय दशा को ध्यान में रखते हुये गुणवत्ता और अनुकूलता के संदर्भ में योजना के भाग के रूप में किये गये विद्यालय भवन निर्माण का परीक्षण।

v) टी. एल. ई. प्रशस्ति अध्यापकों द्वारा इस उदेश्य की पूर्त्ति के लिये टी. एल. ई. की उपलब्धता और उपयोग का अध्ययन। आप्रेशन ब्लैड बोर्ड सामग्री के उपयोग और अध्यापक प्रशिक्षण के बीच संबंधों पर विशेष बल दिया जायेगा।

vi) कार्यव्यवहार के क्रियान्वयन के मूल्यांकन हेतु राज्य स्तर पर स्वीकार्य वर्तमान पद्धति का परीक्षण योजना।

vii) ग्राम शिक्षा समिति/स्थानीय समुदाय तथा शिक्षकों द्वारा टी. एल. ई. सामग्री प्राप्त करने में रुचि तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टी. एल. ई. के प्रभाव का परीक्षण

viii) प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं और मांगो को ध्यान में रखतें हुये योजना के अंतर्गत अनुदान की उपयोगिता का मूल्यांकन

अनुसंधान की अनुमानित लागत 3,98,20,000/– रुपये है।

माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग, मा. सं. वि. मंत्रालय को उपरोक्त अध्ययन की रिपोर्ट का एक प्रारूप भेज दिया गया है।

**5. विद्यालय शिक्षा स्तर पर प्रोत्साहन की प्रभाविकता**

उपरोक्त अध्ययन डा. (सुश्री) के. सुजाता, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय एकक द्वारा किया जा रहा है।

इससे पहले यूनिसेफ ने पेडेरू, विशाखापट्टनम के 11 मंडलों में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के समवर्त्ती मूल्याकन के लिये 5,31,200 रुपये लागत का अध्ययन प्रायोजित किया था। इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य हैं :

(i) प्रत्येक हस्तक्षेप के लिये योजना और प्रशासन हेतु प्रयुक्त प्रक्रियाओं का प्रलेखन,

(ii) लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मध्यस्थता की प्रभाविकता का अध्ययन,

(iii) मध्यस्थता की ताकत और कमजोरियां,

(iv) सुदृढ़ीकरण/संशोधन/विवेचनात्मक समर्थन के लिये सुझाव प्रस्तुत करना।

(v) भविष्य में कार्यक्रम को दिशा प्रदान करना–विवेचनात्मक मुद्दों की पहचान करना। विद्यालय शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, समुदाय सदस्यों (वी.ई.सी. तथा मदर्स समिति), एम. आर. पी., विद्यालय परिसर हेडमास्टर, पी. आर. सी, पी. एम. सी. परियोजना अधिकारी तथा प्राधिकरणों से प्राप्त गुणात्मक और परिमाणात्मक आंकड़ा संग्रह पर मूल्यांकन अध्ययन आधारित हैं।

प्रस्तुत अध्ययन के व्यय की पूर्त्ति यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित अध्ययन की बचत से की जायेगी।

अध्ययन जारी है।

**6. नगरीय गरीबों की शिक्षा : दिल्ली की मलीन बस्तियों का एक केस अध्ययन**

उपरोक्त अध्ययन 49,800 रुपये की लागत से डा. बी. के. पांडा, सह अध्येता के लिये स्वीकृत किया गया। अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नालिखित हैं :

i) मलीन बस्तियों में विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों तथा विभिन्न प्रोत्साहनों इत्यादि के संदर्भ में विविध शैक्षिक सुविधाओं का अध्ययन करना;

ii) मलीन बस्ती के निवासियों द्वारा प्राप्त शिक्षा के स्तर तथा ज्ञान को समझना तथा उनके बच्चों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के संदर्भ में उनकी आशाएं और दष्टि्कोण को समझना;

iii) मलीन बस्तियों के निवासियों के सामाजिक–आर्थिक तथा शैक्षिक अवरोधकों को समझना

यह अध्ययन प्रगति पर है।

**7. उच्च शिक्षा में मानवाधिकार : चुनौतियां और अवसर**

इस अध्ययन के उद्देश्य हैं : उच्च शिक्षा क्षेत्र की अवस्थिति, व्यवस्थाएं और पद्धतियों पर विचार–विमर्श करना, उच्च शिक्षा क्षेत्र में अवसरों और भावी चुनौतियों को ध्यान में रखकर मानवाधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों का पता लगाना, कॉलेज प्रशासन और शिक्षकों के अनुभव एकत्र और वर्गीकृत करना, तथा उपर्युक्त के आधार पर रिपोर्ट बनाना तथा नीति निर्माताओं, योजनाकर्मियों और विभिन्न स्तरों पर प्रशासकों को आगत उपलब्ध कराना।

यह अध्ययन प्रो. के सुधा राव और सुश्री आरती छत्रपति कर रही है।

**8. दिल्ली में पाली में चलने वाले विद्यालयों की कार्यप्रणाली : समस्या तथा भविष्य**

उपरोक्त अध्ययन डा. रश्मि दीवान, सह अध्येता द्वारा किया जा रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत 49,600 रुपये है। अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:

i) स्थाननिर्धारण, आधारभूत तथा भौतिक सुविधाएं, संसाधनों का उपयोग तथा लामबन्दी, अध्यापक संख्या, छात्र संख्या, समय सारणी, कक्षा–आकार, पाठ्यचर्या और सहचर्यात्मक गतिविधियों का आयोजन, नामांकन, विद्यालय त्याग तथा क्षमता धारण इत्यादि को ध्यान में रखते हुये विद्यालयों की कार्यप्रणाली की प्रभाविकता का अध्ययन करना,

ii) ऊपर वर्णित आयामों के अतिरिक्त उपलब्धियों, मूल्यांकन प्रक्रिया, परीक्षा परिणाम इत्यादि को ध्यान में रखते हुये एकल पाली और दोहरी पाली विद्यालयों का तुलनात्मक अध्ययन करना

यह अध्ययन जारी है।

**9. भारत में विश्वविद्यालय वित्त व्यवस्था : एक कार्यविवरण**

47,500/–.रुपये की अनुमानित लागत से यह अध्ययन डा. जे.'बी. जी. तिलक, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, शैक्षिक वित्त एकक द्वारा किया जा रहा है। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं :

i) विश्वविद्यालय वित्त व्यवस्था में परिवर्तित ढांचे का विश्लेषण करना – विश्वविद्यालय के लिये आय के विभिन्न स्रोतों और उनकी हिस्सेदारी पर बल,

ii) विश्वविद्यालय व्यय के ढांचे का अध्ययन करना विभिन्न मदों पर व्यय

यह अध्ययन जारी है।

**10) डी. पी ई. पी. के अंतर्गत जिला तथा उप जिला प्रबंधन संरचनाएं**

'डी. पी. ई. पी. के अंतर्गत जिला तथा उपजिला प्रबंधन संरचनाएं' शीर्षक से एक अनुसंधान अध्ययन प्रारंभ किया गया है। इस अध्ययन के चार उद्देश्य हैं :

i) डी.पी.ई.पी. के अनुसार जिला तथा उप–जिला प्रबंधन संरचनाओं की भूमिका और कार्य का अध्ययन करना,

ii) भूमिका और कार्य के संदर्भ में डी. पी. ओ., बी. आर. सी. और सी. आर. सी. की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन और अध्ययन करना,

iii) अन्य अकादमिक तथा प्रशासनिक संस्थानों के साथ जिला तथा उप–जिला प्रबंधन संरचनाओं का क्षैतिज तथा अनुलम्ब संबंध,

iv) भविष्य में उपजिला संरचनाओं, जैसे – बी. आर. सी. तथा सी. आर. सी. की भूमिका तथा क्षमता निर्माण की कार्यप्रणाली के लिये सुझाव देना।

यह अध्ययन प्रारांभिक चरण में है तथा दस्तावेज/सामग्री इत्यादि के अध्ययन हेतु पुस्तकालय कार्य जारी है। यह अध्ययन गहन क्षेत्र कार्य पर आधारित होगा। इस कार्य के लिये बिहार (शैक्षिक रूप से पिछड़ा राज्य) तथा केरल (शैक्षिक रूप से अग्रणी राज्य) से एक–एक जिले को चुना गया है। डा. एस. एम. आई. ए. जैदी इसके परियोजना निदेशक हैं।

**11. परिवार द्वारा शिक्षा की मांग पर डी. पी. ई. पी. के हस्तक्षेप का प्रभाव : उड़ीसा में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का अध्ययन**

उद्देश्य

– डी. पी. ई. पी. और गैर डी. पी. ई. पी. जिलो में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की शिक्षा की मांग के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन, तथा

– डी. पी. ई. पी. के द्वारा विशेषतौर पर प्राथमिक शिक्षा के लिये गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की शिक्षा की मांग के स्तर में बढ़ोत्तरी में योगदान (अगर कोई है तो) की पहचान करना

शुरुआत के रूप में, एक संकल्पना पत्र प्रस्तुतिकरण और चर्चा के लिये तैयार किया जा रहा है।

**12. विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन**

उपरोक्त अध्ययन डा. एम. मुखोपाध्याय वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, शैक्षिक प्रशासन एकक द्वारा किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत 99,700/– रुपये है। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं :

i) शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (टी.क्यू.एम) पैकेज का विकास–जिसका प्रयोग डाइट जैसे चुनिंदा संस्थानों में किया जा सके।

ii) डाइट के प्राचार्यों को टी. क्यू. एम. क्रियान्वयन के लिये प्रशिक्षण देना,

iii) सांस्थानिक मूल्यांकन तथा क्रियान्वयन योजना का विकास करना,

iv) संगठनात्मक विकास में टी. क्यू. एम. के हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना,

अध्ययन प्रगति पर है।

**13. जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) की तकनीकी तथा ढांचात्मक क्षमता का मूल्यांकन - एक राष्ट्रीय मूल्यांकन अध्ययन**

32,45,000/– रुपये की अनुमानित लागत से नीपा यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित उपरोक्त अध्ययन कर रहा है। यह अध्ययन डॉ. आर. गोविंद, वरिष्ठ अध्येता तथा डा. (सुश्री) नीलम सूद, अध्येता द्वारा किया जा रहा है। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं :

i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 में निर्धारित मूल लक्ष्यों और इसके तदनन्तर योजना के क्रियान्वयन के लिये ज़ारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों सापेक्ष देश में डाइट की योजना के क्रियान्वयन में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक प्रगति का आकलन

ii) मूल कार्य विवरण और प्रारंभिक शिक्षा में तेजी से हो रहे परिवर्तनो के संदर्भ में डाइट के प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन, डाइट की वर्तमान भूमिका और कार्यकलापों, प्रशिक्षण तथा अन्य गतिविधियों द्वारा तकनीकी समर्थन की पर्याप्तता और गुणवत्ता, व्यवस्था के अंदर ही अन्य संस्थानों से संबंध तथा योजना के अंतर्गत उपलब्ध ठोस समान तथा अन्य आगतों पर केन्द्रित होगा।

iii) डाइट की क्षमता को मजबूती देने के लिये तत्कालिक तथा दीर्घकालिक कार्यकलापों के लिये सुझाव, जिला स्तरीय नोडल तकनीकी संसाधन समर्थन संस्थान के रूप में

विवेचनात्मक कार्यकलापों को निभाने के लिये समर्थ करना तथा विशेषतः प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये योगदान देना।

iv) देश में प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा पर वृहद सूचना आधार का विकास, इसके अतिरिक्त डाइट की निर्देशिका तैयार करना जिसमें स्थान, ढांचा–आधार, अकादमिक सामर्थ्य, विशेषज्ञता का क्षेत्र इत्यादि की सूचनाएं उपलब्ध हों।

अध्ययन जारी है।

**14. शिक्षा के लिये जिला सूचना प्रणाली-चरण-II**

उपरोक्त अध्ययन चरण–I के क्रम में यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित किया गया है। डा. वाई. पी. अग्रवाल, वरिष्ठ अध्येता इसके परियोजना निदेशक हैं। चरण–II कार्यक्रम में निम्नांकित गतिविधियां की जानी हैं :

i) डी. आई. एस. ई. आंकड़ा के संचालन के लिये राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर माड्यूलों का विकास,

ii) डी. आई. एस. ई. 2.0 के क्रियान्वयन में डी. पी. ई. पी. जिलों/राज्यों को प्रशिक्षण प्रदान करना। नये जिलों/राज्यों के क्षमता विकास पर विशेष बल दिया जायेगा (डी. पी. ई. पी.–II),

iii) साफ्टवेयर के संचालन में राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करना जिसके अंतर्गत समस्याओं के निराकरण हेतु राज्यों का दौरे भी सम्मिलित हैं।

iv) राज्यों को आवश्यक अध्यापन डाटाबेस प्रबंधन साफ्टवेयर के संबंध में उनसे चर्चा। इस चर्चा के आधार पर आवश्यक कदम उठायें जायेगें,

v) डाइस 2.0 की प्रभाविकता और कार्यदक्षता में सुधार के लिए क्रियान्वयन स्तर पर आने वाली तकनीकी तथा अन्य बाधाओं को दूर करना। (1997)

vi) नामांकन प्रक्षेपण, कोहोर्ट विश्लेषण तथा प्रवृत्ति मूल्यांकन जैसे प्रमुख अनुप्रयोगों के लिये साफ्टवेयर का विकास। यह साफ्टवेयर परिदृश्य निर्माण, दीर्घकालिक परियोजना तथा वार्षिक कार्य योजना की तैयारी से जुड़े जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के व्यावसायिकों के लिये लाभकारी सिद्ध होगा।

vii) वर्ष के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली डी. पी. ई. पी. गतिविधियों की योजना और अनुश्रवण हेतु डी. आई. एस. ई. और अन्य आंकड़ा के प्रयोगों के लिये राज्य स्तरीय सिस्टम एनलिस्ट तथा वरिष्ठ प्रशासकों को प्रशिक्षण।

उपरोक्त अध्ययन जारी है।

## 15. सबके लिये शिक्षा-2000

उपरोक्त अध्ययन यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित है तथा डा. आर. गोविंद, वरिष्ठ अध्येता और अध्ययक्ष, अनौपचारिक शिक्षा एकक द्वारा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सम्मिलित तथा केब द्वारा पृष्ठांकित उद्देश्य, लक्ष्य, तथा रणनीतियों को पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में क्रमशः सम्मिलित किया जाता रहा है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रयास किये गये। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत बाह्य निधि और साक्षरता अभियानों के समर्थन से आठवीं पंचवर्षीय योजना में बड़ी परियोजनाएं भी प्रारंभ की गई। ये परियोजनाएं नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में भी जारी हैं। इस प्रकार सबके लिए शिक्षा के लक्ष्यों को राष्ट्रीय योजना ढांचे में सम्मिलित किया गया है जो कि राज्य स्तर पर सभी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

यह अध्ययन दो भागों में विभाजित है। भाग–I में तीन प्रमुख अध्ययनों की तैयारी की गई है :

i) मूलभूत 18 – ई. एफ. ए. संकेतक

ii) शिक्षार्थी संप्राप्ति की अवस्थिति की समीक्षा

iii) शिक्षार्थी की दशाओं की अवस्थिति की समीक्षा

इन दस्तावेजों को मई, 1999 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया। इस कार्यशाला में राज्य शिक्षा सचिवों, शिक्षा विशेषज्ञों तथा संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, विश्व बैंक तथा बाह्य धनदाताओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय कार्यशाला की समाप्ति के तुरन्त बाद इन दस्तावेजों पर नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई देशों की उपक्षेत्रीय बैठकों में चर्चा की गई। दिनांक 12–13 अक्तूबर 1999 के दौरान काठमाण्डु में आयोजित दक्षिण और पश्चिम एशिया के लिये आयोजित द्वितीय उप–क्षेत्रीय कार्यशाला में सबके लिए शिक्षा : आकलन 2000 का प्रारंभिक प्रारुप प्रस्तुत किया गया। नवंबर 1999 में राष्ट्रीय आकलन समूह की काठमाण्डु में कार्यशाला के दौरान प्राप्त पुनर्निवेशन और टिप्पणियों के आधार पर संशोधित प्रारूप पर चर्चा की गई।

अध्ययन के भाग–II में 21 विषयगत समीक्षाओं और 4 केस अध्ययन है :

1) बुनियादी शिक्षा में अ–सरकारी संगठनों की भूमिका और योगदान

2) शिक्षा और महिलाओं की स्थिति

3) भारत में बालिका शिक्षा, एक आकलन

4) विद्यालय से बाहर के बच्चों की शिक्षा और कार्य–क्षेत्र के प्रति चिंतन

5) भारत में प्रारंभिक शिक्षकों की अवस्थिति

6) नगरीय वंचित वर्गों के लिये शिक्षा

7) भारत में उत्तर–साक्षरता और सतत शिक्षा की बदलती अवधारणाएं और परिवर्तित लक्ष्य

8) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा

9) सबके लिये शिक्षा में जनसंचार माध्यमों की भूमिका

10) प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षार्थी संप्राप्ति

11) आदिवासियों में शिक्षा

12) प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में भारतीय योगदान

13) सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के लिये सहभागितामूलक व्यष्टि स्तरीय योजना

14) प्राथमिक शिक्षा के लिये अधिगम दशाएं

15) सामाजिक लामबन्दी और संपूर्ण साक्षरता अभियान

16) शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा

17) शिक्षा का विकेंद्रीकरण

18) संदर्भगत मूलपाठ : स. ल. शि. 2000 समीक्षा

19) भारत में प्रारंभिक शिक्षा की वित्त व्यवस्था

20) बुनियादी शिक्षा में निजी विद्यालयों की भूमिका

21) हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा

22) स. ल. शि. दशक में प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण

23) मिजोरम में सबके लिये शिक्षा

24) स. लि. शि. में प्रगति : तमिलनाडु का केस अध्ययन

25) राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण : नवाचारी रणनीतियों को ध्यान में रखते हुये अध्ययन

इसके अतिरिक्त नीपा ने स. ल. शि.–2000 भारत रिपोर्ट भी प्रकाशित की है जो कि अखिल भारतीय रिपोर्ट है।

[redacted]

नीपा में समसामयिक आलेखों, जर्नलों, न्यूजलेटरों और रिपोर्टों के माध्यम से शिक्षा के शोध और विकास के प्रचार–प्रसार के लिए एक सुनियोजित प्रकाशन कार्यक्रम हैं। संस्थान की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं – जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन (अंग्रेजी), परिप्रेक्ष्य (हिंदी) और एनट्रिप न्यूज लेटर। संस्थान ने अनेक शोध और संगोष्ठियों/सम्मेलनों की रिपोर्टें पुस्तकाकार में प्रकाशित की है। यह विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों के शैक्षिक प्रशासन पर सर्वेक्षण रिपोर्टों की एक शृंखला प्रकाशित कर रहा हैं।

समीक्षाधीन काल में संस्थान ने निम्नांकित का प्रकाशन किया :

[redacted]

**दूसरे अखिल-भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण से संबंधित पुस्तकें**

नीपा ने दो दशकों के अंतराल के बाद शैक्षिक प्रशासन के बारे में दूसरे अखिल–भारतीय सर्वेक्षण का व्यापक कार्य शुरू किया है। इसमें सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों को समेटा गया है। समीक्षाधीन वर्ष में इस शृंखला में निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की गईं :

1. **एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार : स्ट्रक्चर्स, प्रोसेसेज एंड फ्यूचर प्रास्पेक्ट्स : अनिल सिन्हा, आर. एस. त्यागी, यू. पी. सिंह और टी. एन. चौधरी**
2. **एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तर प्रदेश : स्ट्रक्चर्स, प्रोसेसेज एण्ड फ्यूचर प्रास्पेक्ट्स : आर. एस. त्यागी और शरदिन्दु**

शृंखला की हर पुस्तक संबंधित राज्य/संघीय क्षेत्र प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही आधारित नहीं होती बल्कि द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त अधुनातन आंकड़ों पर भी आधारित होती है। इसमें मुख्य रूप से विद्यालय शिक्षा के प्रशासन पर ध्यान देते हुए संस्था के स्तर से लेकर राज्य/संघीय क्षेत्र के स्तर तक शैक्षिक प्रशासन की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत की जाती है।

ये पुस्तकें शैक्षिक योजना और प्रशासन का एक आलोचनात्मक विश्लेषण पेश करती हैं और साथ ही प्रशासन व्यवस्था के भावी विकास संबंधी सुझाव भी देती हैं। ये शैक्षिक योजनाकर्मियों और प्रशासकों के सामने मौजूद कार्यों की रूपरेखा भी सामने रखती हैं।

ये पुस्तकें शोधकर्ताओं, शिक्षाशास्त्रियों, शैक्षिक योजनाकर्मियों और प्रशासकों के लिए तथा शिक्षा के विकास में दिलचस्पी रखनेवाले सभी लोगों के लिए एक उपयोगी संदर्भ–सामग्री हैं।

3. **मैनेजमेंट आफ आटोनामी इन आटोनोमस कालेजेज - के सुधा राव**
4. **आटोनोमस एण्ड नान-आटोनोमस कालेजेज - सेलेक्टेड केस स्टडीज - के सुधा राव, जार्ज मैथ्यु और सुधीर के सामंत्रे**

[redacted]

5. **लर्निंग दि ट्रेजर विदिन - सं. मर्मर मुखोपाध्याय और अन्य**

6. **बेस्ट प्रैक्टिसेज इन हायर एजुकेशन सेरीज - एकेडेमिक रिन्यूवल एण्ड लिंकिंग एजुकेशन एण्ड इंपलायमेंट - एन इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट - (सं.) के सुधा राव**

**नीपा जर्नल**

संस्थान दो पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है – अंग्रेजी में *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन* और हिन्दी में *परिप्रेक्ष्य*। इस वर्ष दोनो पत्रिकाओं के 6 अंक प्रकाशित किए गए :

1–3 *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन* (समूल्य) जिल्द 13, अंक 2, अप्रैल 1999, जिल्द 13, अंक 3, जुलाई 1999, जिल्द 13, अंक 4, अक्तूबर 1999

4–6 परिप्रेक्ष्य (हिन्दी जर्नल) वर्ष 5, अंक 1–2 अप्रैल–अगस्त 1998, वर्ष 5, अंक 3, दिसंबर 1998 और वर्ष 6, अंक 1–2, अप्रैल–अगस्त 1999

**एनट्रिप न्यूज लेटर**

इस वर्ष एनट्रिप (एशियन नेटवर्क आफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन एजुकेशनल प्लानिंग) न्यूज लेटर के दो अंक (जनवरी–जून 1999 और जुलाई – दिसंबर 1999) प्रकाशित किए गए।

**प्रकाशनाधीन**

1–4 केंद्रीय सरकार, दिल्ली, उड़ीसा और मेघालय के शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण की रिपोर्टें (समूल्य)

5. *स्कूल मैपिंग* : एन एनलिसिस आफ एजुकेशनल फेसिलिटीज इन ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा – एन. वी. वर्गीस और के बिस्वाल (समूल्य)

6. *यूनिवर्सलाइजेशन आफ अपर प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया* : एन एनलिसिस आफ स्कूल फैसिलिटीज एण्ड दियर कास्ट इंप्लिकेशंस – एन. वी. वर्गीस और अरुण सी. मेहता (समूल्य)

7. *बेस्ट प्रैक्टिसेज इन हायर एजुकेशन* – इसूज आन इंटिग्रल एजुकेशन : ए मिशन टू इंटिग्रेट वैल्यूज इन एजुकेशन–सं. के सुधा राव

8. *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन*, जिल्द 14, अंक 1 जनवरी 2000 (समूल्य)

9. *परिप्रेक्ष्य* (हिंदी पत्रिका), वर्ष 6, अंक 3, दिसंबर 1999

**मिमियोग्राफ प्रकाशन**

इनके अलावा विभिन्न शोध अध्ययनों, समसामयिक आलेखों, और संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/संगोष्ठियों की रिपोर्टें/अध्ययन सामग्री के मिमियोग्राफ/फोटो प्रतिलिपि के रूप में प्रकाशन किए जाते हैं।

# अध्याय 4

## पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र और अकादमिक समर्थन प्रणाली

संस्थान के पास शैक्षिक योजना, प्रशासन और शैक्षिक विषयों पर एक समृद्ध पुस्तकालय है। इसे एशिया क्षेत्र में शैक्षिक योजना और प्रबंध के क्षेत्र में सबसे समृद्ध पुस्तकालयों में शामिल किया जा सकता है। इससे केवल संकाय, शोधछात्रों और विभिन्न कार्यक्रमों के भागीदारों की ही जरुरतें पूरी नहीं होती बल्कि अंतरपुस्तकालय ऋण व्यवस्था के माध्यम से दूसरे संगठनों की जरुरतें भी पूरी होती हैं। यहां की वाचनालय सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं।

समीक्षित काल में पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र में 1184 पुस्तकों और दस्तावेजों की वृद्धि हुई। इस समय पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र के पास संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को आर्थिक सहयोग–विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनिसेफ, विश्व बैंक आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों और सम्मेलनों की रिपोर्टों के एक समृद्ध संग्रह के अलावा 52620 पुस्तकों का एक संग्रह भी है।

### पत्रिकाएं

पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र में शैक्षिक योजना, प्रशासन, प्रबंध और दूसरे संबद्ध विषयों की 380 पत्रिकाएं आती हैं। इन पत्रिकाओं में प्रकाशित सभी महत्वपूर्ण लेखों की सूची तैयार की जाती है। समीक्षित काल में इन पत्रिकाओं से 2001 लेखों की सूची तैयार की गई।

### अखबारों की कतरनें

पुस्तकें और पत्रिकाओं के अलावा पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र में आने वाले 24 समाचार पत्रों से शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी समाचार और अन्य सामग्री की कतरनों का एक विशेष संग्रह भी रखा जाता है।

**समसामयिक ज्ञान सेवा**

**शिक्षा संबंधी पत्र-पत्रिकाएं :** हर पखवाड़े में आने वाली शैक्षिक पत्रिकाओं के लेखों के बारे में पाठकों को जानकारी देते रहने के लिए पुस्तकालय ने अपना पाक्षिक अनुलेखित प्रकाशन *पीरियाडिकल्स इन एजुकेशन : टाइटिल्स रिसीव्ड एंड देयर कंटेंट* का प्रकाशन जारी रखा।

**नीपा पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र की प्राप्तियां**

पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र में आनेवाले प्रकाशनों की कंप्यूटर से मासिक सूचियां भी तैयार की जाती हैं। इससे पाठकों को उनकी रुचि के दस्तावेजों, लेखों और नई सामग्रियों की जानकारी मिलती रहे।

**सूचनाओं का चुनिंदा प्रसारण**

पुस्तकालय ने संस्थान के अकादमिक एककों और शोध–परियोजनाओं के अध्ययन दलों को नई सूचनाएं उपलब्ध कराई ताकि वे उसका लाभकारी उपयोग कर सकें।

**संदर्भ-सूची**

इस अवधि में पुस्तकालय ने संस्थान के विभिन्न कार्यकलापों के लिए 168 संदर्भ सूचियां तैयार कीं।

**अमुद्रित सामग्री**

यह पुस्तकालय एक बहुमाध्यमी संसाधन केंद्र है। इसमें वीडियो कैसेटों, आडियो कैसेटों, फिल्मों, माइक्रो फिल्मों और माइक्रोफिंचों का एक संग्रह भी मौजूद है। इस समय यहां 6 फिल्में, 76 वीडियो कैसेट, 82 आडियो कैसेट, 54 माइक्रोफिल्में और 110 माइक्रोफिंचें हैं।

सी डी रोम डाटा बेस

1. एरिक 1985 – मार्च 2000
2. यूनेस्को के वर्ड डाटा आन एजुकेशन के 1998 द्वितीय संस्करण
3. फिफ्टी ईयर्स आफ इंडियन एजुकेशन, मा. स. वि. मं.
4. इनोवा डाटा
5. एजुकेशन एट ए ग्लांस 1999
6. ग्लोबल डवलपमेंट फायनेंस 2000
7. सेंसस आफ इंडिया 1991
8. वर्ड डवलपमेंट इंडिकेटर्स 2000
9. यू. एन. स्टैटिस्टिक्स ईयर बुक अंक 39
10. वुमेन इंडिकेटर्स एण्ड स्टैटिस्टिक्स डाटा बेस संस्करण 3

11. वर्ल्ड डवलपमेंट रिपोर्ट 1978 – 1999 / 2000

12. चाइनीज यूनिवर्सीटीज एण्ड कालेजेज

13. सीटी एण्ड गिल्ड्स प्रोटेक्ट सीडी

14. फार द लव आफ लर्निंग

15. पी सी क्वेस्ट सी डी

16. चीप सी डी

17. डाटा क्वेस्ट सी डी

**पुस्तकालय वेबसाइट**

पुस्तकालय ने अपना वेब साइट आरभं किया हैं : http://niepalib.freeyellow.com. इसमें निम्नांकित सूचनाएं संकलित है :

1. नीपा का परिचय

2. पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र का परिचय

3. नीपा शोध अध्ययन

4. एजुकेशन फाइल : 24 समाचार पत्रों से भारतीय शिक्षा की खबरें

5. पाक्षिक सूचना संदर्भ : भारतीय शिक्षा के विविध पक्षो पर सूचना

6. नीपा पुस्तकालय द्वारा मंगाए जाने वाले जर्नलों की वर्तमान विषय सूची

7. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम : केंद्र और राज्य स्तर पर तैयार दस्तावेजों के बारे में सूचना

8. नया संकलन : पुस्तकालय में संगृहीत नई पुस्तके और जर्नलों के आलेखों की सूची।

**पुस्तकालयों का नेटवर्किंग**

नीपा पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र ने 1995 में दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क (डेलनेट) की सदस्यता ग्रहण की। इससे हमें निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हुईं :

**(अ) फोन पर संपर्क :** दिल्ली के 102 पुस्तकालयों से फोन पर संबंध स्थापित हुआ। ये 102 पुस्तकालय भी नीपा पुस्तकालय के संग्रह के बारे में फोन पर जानकारी पा सकते हैं।

**(ब) ई-मेल सेवा :** दिल्ली की 102 संस्थाओं से संपर्क।

रेनिक (RENNIC) के माध्यम से देश के दूसरे भागों से संपर्क।

विदेश संचार निगम लि के माध्यम से इंटरनेट से संपर्क।

इस सुविधा के सहारे नीपा का संकाय देश–विदेश से अपनी डाक ई–मेल द्वारा मंगा और भेज सकता है। साथ ही पुस्तकालय भी पहले से कम समय में उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताएं पूरी कर सकता है।

**प्रशिक्षण कार्यक्रम**

हरियाणा के महाविद्यालय पुस्तकालय की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम,। 3-7 मई 1999 सहभागी कार्यक्रम में शामिल हुए।

हिमाचल प्रदेश की पुस्तकालय की योजना और प्रबंधन पर 7-11 जून 1999 के दौरान अभिविन्यास कार्यक्रम। इसमें 23 महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्षों और 11 जिला सार्वजनिक पुस्तकालयाध्यक्षों सहित कुल 34 भागीदार शमिल हुए।

**प्रलेखन केंद्र**

संस्थान के कार्यक्रमों और विशेष रूप से राज्यों और संघीय क्षेत्रों की जरुरतों से जुड़े कार्यक्रमों को सूचना संबंधी एक कारगर आधार देने के लिए पुस्तकालय का प्रलेखन केंद्र शैक्षिक योजना और प्रशासन पर उन संदर्भ सामग्रियों का संग्रह करता है जो केंद्र, राज्यों, संघीय क्षेत्रों, शिक्षा विभागों, जिला अधिकारियों और शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। सूचनाओं के संग्रह, भंडारण और प्रसार पर यह केंद्र खास जोर देता है ताकि संस्थान सूचना प्रदाता के रूप में भूमिका निभा सके।

इस वर्ष केंद्र में 651 दस्तावेज शामिल किए गए। इस समय केंद्र के पास 20,802 दस्तावेज हैं। इनमें राज्यों के गजेटियर, राज्य जनगणनाओं की पुस्तिकाएं, शैक्षिक सर्वेक्षण, राज्यों की शैक्षिक योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, बजट, राज्य विश्वविद्यालयों की हस्तपुस्तिकाएं, बुनियादी स्रोतग्रंथ और संदर्भ–सूचियां, अखबारी कतरनें, राज्यों की शैक्षिक आचार संहिताएं, नियम और विनियम, तकनीकी–आर्थिक और प्रतिदर्शी सर्वेक्षण, जिलों के गजेटियर, जिला जनगणनाओं की पुस्तिकाएं, वार्षिक योजनाएं, शैक्षिक योजनाएं, जिला साख योजनाएं, जिलों के प्रतिदर्शी सर्वेक्षण, जिलों के शैक्षिक सर्वेक्षण, जिलों की सांख्यिकीय हस्तपुस्तिकाएं, गांव और प्रखंड स्तर की योजनाएं और अध्ययन, शोधों और परियोजनाओं की रिपोर्टें, संसाधन अध्ययन कोश, तकनीकी–आर्थिक सर्वेक्षण, जि प्रा शि कार्यक्रम की योजनाएं और अध्ययन, तथा विश्वविद्यालयों के शोध प्रबंध शामिल हैं।

देश भर से उपहारों के आदान–प्रदान के आधार पर केंद्र में 105 शिक्षा शास्त्रीय व संबद्ध विषयों की पत्रिकाएं आती हैं।

प्रलेखन केंद्र में संदर्भ सेवा भी उपलब्ध है जिसमें नीपा के निम्नलिखित 6 संग्रह भी संदर्भ प्रयोजन के लिए उपलब्ध हैं :

(1) नीपा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्टें : 1962 से 2000 तक।

डॉ.कर्ण सिंह सुविख्यात शिक्षाविद् और सांसद , राज्य सभा अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा-2000 के प्रशिक्षणार्थियों के साथ

प्रो. के. सुजाता , वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष , अंतर्राष्ट्रीय एकक , नीपा अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा-2000 के प्रशिक्षणार्थियों के साथ

पुस्तकालय की एक झलक

राजभाषा स्वर्ण जयंती कविगोष्ठी के अवसर पर श्री बालकवि बैरागी के साथ कविगण

(2) शैक्षिक योजना और प्रशासन के डिप्लोमा और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रमों के भागीदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए लघु शोध प्रबंध : 1982–2000

(3) नीपा के अनुसंधान अध्ययनों की विषयवार सूची : 2000.

(4) विश्वविद्यालयों के शोध प्रबंध; विषयवार वर्गीकृत : 2000.

(5) जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजनाओ की सूची रिपोर्टें : 2000.

(6) आइडेपा के परियोजना अध्ययनों 2000 तक की वर्गीकृत सूची

केन्द्र पाठकों की सुविधा के लिए 24 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्र मंगाता है।

प्रलेखन केंद्र की सामग्री केवल संदर्भ सेवा के लिए है। नीपा के संकाय, शोधकर्ता स्टाफ और प्रशिक्षार्थी ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं के शोधछात्र भी इसका व्यापक और कारगर उपयोग करते हैं। इस वर्ष 2846 विद्वानों ने केंद्र की सेवाओं का उपयोग किया।

## कम्प्यूटर कक्ष

नीपा अपनी रोजमर्रा की शैक्षिक और गैर–शैक्षिक गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने में अग्रणी रहा है। संस्थान के पास एक सुसज्जित कंप्यूटर केंद्र हैं जिसमें अनेक प्रकार के कंप्यूटर और प्रिंटर मौजूद हैं। (विप्रो सुपर जिनियस, पेंटियम–III, कंपेक डेस्कप्रो, पेंटियम–II) प्रिंटर–एच.पी.एल. लेज़र जेट 4000 एन, एच.पी.एल. लेज़र जेट 4 एम.पी., एच.पी. लेज़र जेट 5 एम.पी., एच.पी. लेज़र जेट 6 एल गोल्ड और स्केनर (यूमैक्स पावर ब्लाक–II, एच.पी. ऑफिस जेट 65) कंप्यूटर केंद्र संस्थान की सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह केंद्र सभी अकादमिक एककों तथा पुस्तकालय, प्रशासन और वित्त अनुभाग को भी कंप्यूटर की सुविधाए प्रदान करता है। अकादमिक एककों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और मात्रात्मक आंकड़ा विश्लेषण प्रणाली स्तर के प्रबंधन मुद्दे और दूसरे कार्यकलापों में सहायता दी जाती है। यह केंद्र प्रेस–पूर्व पृष्ठ तैयार करके संस्थान के विभिन्न प्रकाशन–कार्यों में भी सहयोग देता है। जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एनट्रिप न्यूजलेटर, वार्षिक रिपोर्ट आदि ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं। केंद्र के पास ई–मेल और इंटरनेट की सुविधाएं भी हैं।

केंद्र स्थानीय नेटवर्क 50 नोडों पर आधारित है पर संस्थान के लगभग सभी कक्ष इससे जोड़े गए हैं। इस तरह अधिक बिंदुओं पर प्रिंट सर्वर सुलभ होता हैं और विभिन्न स्थानों से अनेक एप्लिकेशन साफ्टवेयर्स का उपयोग किया जा सकता हैं।

उपरोक्त हार्डवेयर के अलावा केंद्र में अलग–अलग प्रयुक्त होने वाले तथा स्थानीय नेटवर्क की श्रेणी वाले अनेक प्रकार के साफ्टवेयर पैकेज हैं–इनमें से कुछ साफ्टवेयर इस प्रकार हैं : माइक्रो साफ्ट विंडों 95/98, एम. एस. – आफिस 2000 और विंडो एस. वी. एस. एस. रिलीज 10 एडोवफोटो डीलक्स, फाइन रीडर। अनेक साफ्टवेयर सरल उपयोग वाले भी हैं। इनका उपयोग शिक्षा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े आंकड़ों के परिमाणात्मक विश्लेषण के लिए किया जाता है।

## मानचित्रण कक्ष

मानचित्रण कक्ष विभिन्न प्रकाशनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शोध परियोजनाओं के लिए

मानचित्रों, ग्राफों, चार्टों, तालिकाओं और पारदर्शियों के माध्यम से आंकड़ों और सूचनाओं को प्रस्तुत करने की नई–नई विधियां विकसित करता रहा है। यह कक्ष चित्रों, आर्गेनोग्रामों, आंकड़ों के पोस्टरों और शीर्षक पृष्ठों आदि की तैयारी में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं और कार्यक्रमों को कंप्यूटर ग्राफिक की सुविधाएं प्रदान करता है।

इस कक्ष ने राजस्थान, उड़ीसा और दिल्ली के शैक्षिक प्रशासन संबंधी प्रकाशनों में भी अनेक चित्रों का योगदान किया है।

**हिंदी कक्ष**

हिंदी कक्ष अनुवाद की सुविधाएं और अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रशासन में अकादमिक सहायता प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकाशनों के हिंदी संस्करण प्रकाशित करने में ही नहीं बल्कि राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में भी सहायता प्रदान करता है।

संस्थान के हिंदी कक्ष ने समीक्षित वर्ष में रोजमर्रा के कार्यों के अलावा अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए :

(अ) हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

(ब) परिप्रेक्ष्य के तीन अंक प्रकाशित किए गए और अगले तीन अंकों की पांडुलिपियां तैयार की गईं।

(स) हिंदी में निम्नलिखित का अनुवाद और उन्हें प्रकाशन के लिए तैयार किया गया :

(1) वार्षिक रिपोर्ट : 1998-99

(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम : 1999-2000

(द) हिंदी दिवस का आयोजन : हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर 1999 को राजभाषा स्वर्णजयंती वर्ष का शुभारंभ किया गया। इस वर्ष हिंदी प्रोत्साहन योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत 12 अधिकरियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

(य) 14 से 20 सितंबर 1999 तक पांच दिनों की हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें संस्थान के 35 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(र) राजभाषा प्रयोग सहायिका, भाग 2 (अकादमिक) की पांडुलिपि के पहले प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया।

# अध्याय 5

## संगठन, प्रशासन और वित्त

### संगठनात्मक ढांचा

नीपा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत स्वायत्त संगठन है और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से उसे वित्तीय सहायता–अनुदान प्राप्त होता है। नीपा के प्रमुख निकाय हैं : नीपा परिषद्, कार्यकारी समिति, वित्त समिति, और योजना और कार्यक्रम समिति। संस्थान का निदेशक उसका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है और भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसकी सहायता संयुक्त निदेशक करता है। कुलसचिव कार्यालय का प्रमुख तथा पूरे प्रशासन का प्रभारी होता है।

### परिषद

संस्थान का शीर्ष निकाय परिषद है। इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है जिसे भारत सरकार मनोनीत करती है। नीपा का निदेशक परिषद का उपाध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय और प्रादेशिक शिक्षा व्यवस्थाओं के कार्यपालक और यशस्वी शिक्षाशास्त्री परिषद के सदस्य होते हैं, जैसे–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष; भारत सरकार के चार सचिव (शिक्षा, वित्त, कार्मिक और योजना आयोग); राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का निदेशक; राज्यों और संघीय क्षेत्रों के छः शिक्षा सचिव और छः शिक्षा निदेशक; छः यशस्वी शिक्षाशास्त्री; नीपा कार्यकारी समिति के सभी सदस्य; और नीपा संकाय के तीन सदस्य। नीपा का कुलसचिव परिषद का सचिव होता है।

परिषद का मुख्य कार्य संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाना और उसके कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करना है।

31 मार्च 2000 के अनुसार परिषद के सदस्यों की सूची परिशिष्ट I मे दी गई है।

## कार्यकारी समिति

संस्थान का निदेशक इसका पदेन अध्यक्ष होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के सचिव, किसी एक राज्य का शिक्षा सचिव, एक यशस्वी शिक्षाशास्त्री, एक राज्य सरकार का निदेशक, शैक्षिक योजना और प्रबंध में सक्रिय एक राज्य शिक्षा संस्थान का निदेशक, नीपा का संयुक्त निदेशक, तथा नीपा परिषद् में शामिल तीन संकाय सदस्यों में से दो कार्यकारी समिति के सदस्य होते हैं। नीपा का कुलसचिव कार्यकारी समिति का सचिव होता है।

यह समिति संस्थान के मामलों और धन के प्रबंध के लिए जिम्मेदार होती है और परिषद की सभी शक्तियों के प्रयोग का अधिकार रखती है। 31 मार्च 2000 के अनुसार कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट II में दी गई है।

## वित्त समिति

वित्त समिति का गठन अध्यक्ष करता है। इसमें संस्थान के निदेशक की पदेन अध्यक्षता में पांच सदस्य होते हैं। इसमें परिषद् के वित्तीय सलाहकार और वे सदस्य शामिल होते हैं जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत हों। नीपा का कुलसचिव वित्त समिति के सचिव का कार्य करता है।

यह समिति खातों और बजट के अनुमानों की छानबीन करती है और व्यय के नए प्रस्तावों और दूसरे वित्तीय विषयों पर अपनी सिफारिशें देती हैं। 31 मार्च 2000 के अनुसार वित्त समिति के सदस्यों की सूची पारिशिष्ट III में दी गई है।

## योजना एवं कार्यक्रम समिति

नीपा निदेशक योजना और कार्यक्रम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अलावा संयुक्त निदेशक, नीपा के अकादमिक एककों के अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), योजना आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक–एक प्रतिनिधि, एक विश्वविद्यालय का कुलपति (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत), राज्य सरकारों के दो शिक्षा सचिव और दो शिक्षा निदेशक (भारत सरकार द्वारा मनोनीत); और अध्यक्ष द्वारा मनोनीत छः शिक्षाशास्त्री/समाज वैज्ञानिक/प्रबंध के विशेषज्ञ (जिनमें से दो महिलाओं/लड़कियों की शिक्षा, एक अनुसूचित जातियों/जनजातियों की शिक्षा और एक अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबद्ध हो) इस समिति के सदस्य होते हैं। 31 मार्च 2000 के अनुसार इस समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट IV में दी गई है।

इस समिति से अपेक्षा की जाती है कि संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा करें। वह संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों को स्वीकृति और अंतिम रूप दे, वह उसके दीर्घकालिक और अल्पकालिक अकादमिक परिप्रेक्ष्यों और योजनाओं का विकास करे, संस्थान द्वारा नियोजित अनुसंधान, प्रशिक्षण–प्रसार और परामर्शकारी कार्यक्रमों का वार्षिक समेकन करे, उनका अध्ययन करे तथा कमियों और प्राथमिकता के क्षेत्रों की पहचान करे।

## अकादमिक एकक

संस्थान का संकाय निम्नलिखित नौ अकादमिक एककों में विभाजित है :

शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक वित्त, शैक्षिक नीति, विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रादेशिक प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय, और संक्रियात्मक अनुसंधान और प्रणाली प्रबंधन।

इन एककों के कार्यक्षेत्र और शौक्षिक प्राथमिकताओं का वर्णन अध्याय 1 में किया जा चुका है। इनमें शैक्षिक नीति एकक को छोड़ कर शेष सभी एककों के अध्यक्ष वरिष्ठ अध्येता है।

सभी अकादमिक एकक अपने–अपने क्षेत्र में पूरे दायित्व के साथ विकास और प्रशिक्षण, अनुसंधान संबंधी कार्य करते हैं और साथ ही अपेक्षित परामर्शकारी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

## कार्यबल और समितियां

निदेशक द्वारा विशेष कार्यक्रमों के लिए समय–समय पर विशेष कार्यबलों और समितियों का गठन किया जाता है।

विभिन्न शोध परियोजनाओं में सलाह देने तथा उनकी प्रगति पर निगरानी रखने के लिए विशेषज्ञों को शामिल करके परियोजना सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं।

निदेशक की अध्यक्षता में एक अनुसंधान अध्ययन सलाहकार मंडल शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी अध्ययनों के लिए सहायता–योजना हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करता है। इसमें अन्य सदस्यों के अलावा अकादमिक एककों के अध्यक्ष भी सदस्य होते हैं। कुलसचिव इसका सदस्य सचिव होता है।

## प्रशासन एवं वित्त

संस्थान के प्रशासनिक ढांचे में तीन अनुभाग – अकादमिक प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, सामान्य प्रशासन, और दो कक्ष के प्रशिक्षण कक्ष और समन्वय कक्ष हैं। अकादमिक प्रशासन और समन्वय कक्ष सीधे कुलसचिव को रिपोर्ट देते हैं। कुलसचिव के संपूर्ण प्रभार के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी कार्मिक प्रशासन, सामान्य प्रशासन और प्रशिक्षण कक्ष के कामों पर निगरानी रखता है।

वित्त अधिकारी वित्त और लेखा अनुभाग का प्रभारी होता है और कुलसचिव को रिपोर्ट देता है।

31 मार्च 1999 तक संस्थान की कुल स्टाफ संख्या 181 थी। संस्थान के स्वीकृत स्टाफ का श्रेणीवार वितरण इस प्रकार है :

| संवर्ग पद | संख्या |
|---|---|
| संकाय | 50 |
| अकादमिक सहायता | 14 |
| प्रशासन, वित्त, अनुसचिवीय और अन्य | |
| तकनीकी स्टाफ | 73 |
| समूह घ | 44 |
| **योग** | **181** |

## [illegible]

श्री आर.एस. शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त होकर दिनांक 7.10.1999 (अपराह्न) को संस्थान में वित्त आधिकारी का पदभार ग्रहण किया। दिनांक 5.4.2000 को उन्होंने नीपा से कार्यमुक्त होकर दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया।

## विदेश यात्राएं

**प्रो. बी. पी. खण्डेलवाल,** निदेशक ने 9-13 सितंबर 1999 के दौरान आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, आक्सफोर्ड, इंग्लैंड में शिक्षा और विकास पर आयोजित 5वें आक्सफोर्ड अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

**डॉ. आर. गोविंद,** वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, विद्यालय और अनौपचरिक शिक्षा एकक ने 14-18 फरवरी 2000 के दौरान साक्षरता संसाधन केद्रों की क्षमता निर्माण पर कोटाबाटो, फिलिपाइंस में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।

**डा जे.बी.जी तिलक,** वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, शैक्षिक नीति एकक ने यूनेस्को द्वारा सबके लिए शिक्षा 2000 आकलन पर काठमांडू, नेपाल में आयोजित द्वितीय उप क्षेत्रीय कार्यशाला (12-13 अक्टूबर 1999) में भी सहभागी थे।

माकाटी, सिटी फिलिपाइंस में 7-8 जनवरी 2000 के दौरान "अगली सहस्त्राब्दी में एशिया" पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में एशिया में विकास के लिए शिक्षा पर विशेष व्याख्यान दिया।

उन्होंने बैंकाक , थाईलैंड में सबके लिए शिक्षा–आलकन 2000 पर आयोजित एशिया प्रशांत सम्मेलन (16-21 जनवरी 2000) में भी भाग लिया।

**डा. (श्रीमती) के. सुधा राव,** वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, शैक्षिक नीति ने पोलैंड, ओरेगान में 28-30 अक्टूबर 1999 के दौरान उच्च शिक्षा की परंपरा और परिवर्तन पर आयोजित एशिया प्रशांत सम्मेलन में भाग लिया और स्वायत्त प्रशासन और गुणवत्ताः उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए चुनौतियां विषय पर आलेख प्रस्तुत किया।

**डा. (श्रीमती) वाई. जोसेफीन,** सह–अध्येता, शैक्षिक प्रशासन एकक ने 9-13 सितंबर 1999 के दौरान बर्गिंघम, इंग्लैंड में शैक्षिक विकास-1999 पर आयोजित आक्सफोर्ड अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और 'बालिका शिक्षा पर गरीबी का प्रभाव–भारत का केस अध्ययन, पर आलेख प्रस्तुत किया।

**डा. (श्रीमती) रश्मि दीवान,** सह–अध्येता, विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक ने 29-31 मार्च 2000 के दौरान कैंब्रिज में आयोजित बी.ई.एम.ए.एस. छठा अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन–2000 में भाग लिया।

## परिसर की सुविधाएं

संस्थान के पास चार मंजिलों वाला एक कार्यालय भवन, सात मंजिलों वाला छात्रावास है जिसमें स्नानघरों से युक्त 60 कमरे तथा वार्डेन आवास, अतिथि संकाय आवास हैं। एक आवासीय परिसर जिसमें टाइप एक के 16, टाइप दो से पांच तक के 8-8 क्वार्टर तथा निदेशक आवास हैं।

## वित्त

इस वर्ष संस्थान को 478.00 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ (इसमें गैर–योजना मद में 178.00 लाख और योजना मद में 300.00 लाख रुपये शामिल थे) जबकि 1998-99 में 243.65 लाख रुपये (गैर–योजना में 138.65 लाख योजना में 105.00 लाख रुपये) प्राप्त हुए थे। साल के शुरू में संस्थान के पास 32.96 लाख रुपये (गैर–योजना में 0.00 लाख, योजना में 32.96 लाख रुपये) की राशि थी। इस साल कार्यालय और छात्रावास से 65.00 लाख रुपये की प्राप्ति हुई।

दूसरे संगठनों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों/अध्ययनों की मद में संस्थान के पास 89.17 लाख रुपये की राशि थी और इस साल 305.51 लाख रुपयों की राशि प्राप्त हुई। इस साल प्रायोजित कार्यक्रमों और अध्ययनों पर कुल 223.34 लाख रुपये व्यय किए गए।

वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा की विस्तृत रिपोर्ट परिशिष्ट VI में प्रस्तुत है।

# अनुलग्नक - 1

## प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/सम्मेलन

| क्रम सं. | एकक का कोड | कार्यक्रम का शीर्षक | तिथि व अवधि | भागीदारों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

[redacted]

### राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम

| क्रम सं. | एकक का कोड | कार्यक्रम का शीर्षक | तिथि व अवधि | भागीदारों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.0 जारी | जिला शिक्षा अधिकारियों (जि. शि. अ.) / डाइट संकाय तथा अन्य शिक्षा कर्मियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासक में 19वां राष्ट्रीय डिप्लोमा (चरण–II) | 30 जनवरी–29 अप्रैल 1999 (29 दिन) | 19 |
| | | चरण–III | 12-16 जुलाई 2000 (5 दिन) | |
| 2. | 05.0 | शैक्षिक योजना और प्रशासन में 20वां राष्ट्रीय डिप्लोमा (चरण–I & II) | 1 नवंबर 1999 – 30 अप्रैल 2000 (152 दिन) | 24 |
| | | **2** | **186** | **43** |

### अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम

| क्रम सं. | एकक का कोड | कार्यक्रम का शीर्षक | तिथि व अवधि | भागीदारों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 3. | 08.0 जारी | शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (चरण–I & II) | 1 फरवरी–30 जुलाई 1999 (121 दिन) | 31 |
| 4. | 08.3 | शैक्षिक योजना और प्रशासन में 15वां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा | 1 फरवरी–30 अप्रैल 2000 (60 दिन) | 32 |
| | | 2 | 181 | 63 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| **शैक्षिक योजना और प्रशासन में विषयवार कार्यक्रम** | | | | |
| **विद्यालय प्रधानाचार्य के लिए योजना और प्रबंधन में प्रशिक्षण** | | | | |
| 5. | 02.4 | विद्यालय प्रधानाचार्यो के लिए संसाधन की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम | 23–27 अगस्त 1999 (5 दिन) | 19 |
| 6. | 05.4 | उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रद्यानाचार्यों के लिए योजना और प्रबंधन पर कार्यशाला (क्षेत्र आधारित–पणजी, गोवा) | 4–8 अक्तूबर 1999 (5 दिन) | 19 |
| 7. | 02.5 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के शिक्षा अधिकारियों और विद्यालयों प्रधानाचार्यो के लिए संस्थान की योजना और प्रबंधन पर कार्यशाला सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्षेत्र आधारित – पोर्ट बलेयर) | 10–14 जनवरी 2000 (5 दिन) | 27 |
| | | **3** | **15** | **65** |
| **उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंधन** | | | | |
| 8. | 06.1 | हिमाचल प्रदेश के महाविधालयों और राजकीय सहायता प्राप्त महाविधालयों के प्राचार्यो के लिए महाविधालय की योजना और प्रबंधन में अभिविन्यास कार्यक्रम (क्षेत्र आधारित – शिमला) | 24–28 मई (5 दिन) | 30 |
| 9. | 06.3 | भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण और विदेशी विश्वविद्यालयों के संचालन पर नीतिगत संप्रेक्ष्य संगोष्ठी | 26–27 नवंबर (2 दिन) | 44 |
| 10. | 06.4 | उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के आकलन : प्रतिमान और संकेतक पर संगोष्ठी | 18–19 जनवरी (2 दिन) | 34 |
| 11. | 06.5 | महाविद्यालयों के प्रचार्यो के लिए महाविद्यालयों की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम | 7–25 फरवरी (19 दिन) | 42 |
| | | **4** | **28** | **150** |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| **जिला शिक्षा और प्रशासन संस्थान (डाइट) की योजना और प्रबंधन** | | | | |
| 12. | 07.1 | डाइट और सी टी ई के प्रचार्यों के लिए योजना और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्षेत्र आधारित–बैंगलौर) | 20–24 अप्रैल (5 दिन) | 28 |
| 13. | 05.1 | डाइट के राज्यवार मुल्यांकन के लिए आंकडा विश्लेषण हेतु रूपरेखा के विकास पर कार्यशाला | 7–8 जून (2 दिन) | 12 |
| 14. | 02.3 | डाइट कार्यक्रमों की योजना पर बैठक | 21 जुलाई (1 दिन) | 14 |
| 15. | 07.6 | डाइट संकाय के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम | 17–28 जनवरी (12 दिन) | 26 |
| 16. | 05.7 | राज्य स्तरीय अध्ययनों पर राष्ट्रीय बैठक (डाइट के राष्ट्रीय मूल्यांकन का भाग) | 24–25 जनवरी (2 दिन) | 12 |
| | | **5** | **22** | **92** |
| **शैक्षिक योजना में मात्रात्मक तकनीकें** | | | | |
| 17. | 01.1 | शैक्षिक योजना में मात्रात्मक तकनीक के प्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम | 12–23 जुलाई (12 दिन) | 16 |
| 18. | 07.7 | शैक्षिक योजना में संकेतकों के प्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम | 7-11 फरवरी 2000 (3दिन) | 38 |
| 19. | 09.3 | शिक्षा में उन्नत मात्रात्मक विधियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम | 6–16 मार्च (11 दिन) | 14 |
| | | **3** | **28** | **68** |
| **वित्तीय प्रबंधन** | | | | |
| 20. | 03.1 | विश्वविद्यालयो वित्त व्यवस्था के प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम | 23–29 सितंबर (7 दिन) | 30 |
| 21. | 03.1 | शैक्षिक वित्त व्यवस्था के प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम | 29 नवंबर–3दिसंबर (5 दिन) | 10 |
| | | **2** | **12** | **40** |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| **अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रबंधित संस्थानों की योजना और प्रबंधन** | | | | |
| 22. | 07.4 | अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रबंधित संस्थानों के प्रमुखों के लिए योजना और प्रबंधन में अभिविन्यास कार्यक्रम | 13–24 सितंबर (12 दिन) | 16 |
| | | **1** | **12** | **16** |
| **सामुदायिक भागीदारी** | | | | |
| 23. | 05.6 | प्राथमिक शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी और सबलीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी | 8–10 दिसंबर (3 दिन) | 66 |
| | | **1** | **3** | **66** |
| **आदिवासी शिक्षा की योजना और प्रबंधन** | | | | |
| 24. | 08.1 | आंध्र प्रदेश आदिवासी कल्याण आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसायटी, हैदराबाद के शैक्षिक संस्थानों के प्रचार्यों के लिए संस्थानिक योजना और प्रबंधन में अभिविन्यास कार्यक्रम | 11–15 अक्तूबर (5 दिन) | 25 |
| | | **1** | **5** | **25** |
| **प्रांरभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण** | | | | |
| 25 | 07.5 | पूर्वोत्तर राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर कार्यशाला (क्षेत्र आधारित – एजावल) | 15–19 नवंबर (5 दिन) | 19 |
| | | **1** | **5** | **19** |
| **विद्यालय मानचित्रण और व्यष्टिस्तरीय योजना** | | | | |
| 26. | 07.2 | विद्यालय मानचित्रण और व्यष्टि स्तरीय योजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम | 9–13 अगस्त (5 दिन) | 24 |
| | | **1** | **5** | **24** |
| **साक्षरता कार्यक्रम** | | | | |
| 27. | 05.3 | प्रौढ़ शिक्षा के राज्य संसाधन केंद्रों के मूल्यांकन पर बैठक | 27 जुलाई (1 दिन) | 15 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 28. | 05.8 | साक्षरता आकलन कार्यनीतियां और प्रक्रियाएं पर कार्यशाला | 29 फरवरी – 3 मार्च (4 दिन) | 27 |
| | | **2** | **5** | **42** |
| **शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन** | | | | |
| 29 | 0.21 | शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन पर कार्यशाला | 13–15 जुलाई (3 दिन) | 19 |
| 30. | 02.2 | अनुक्रियात्मक टी वी संप्रेषण के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्राचार्यों के लिए संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम | 20 जुलाई (1 दिन) | 316 |
| | | **2** | **4** | **335** |
| **पुस्तकालयों की योजना और प्रबंधन** | | | | |
| 31. | 10.0 जारी | गुजरात के डाइट पुस्तकालयों की योजना और प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्षेत्र आधारित–गांधीनगर) | 29 मार्च–3 अप्रैल 1999 (6 दिन) | 19 |
| 32. | 10.1 | हरियाणा के महाविधालयों की पुस्तकालयों की योजना और प्रबंधन | 3–7 मई (5 दिन) | 19 |
| 33. | 10.2 | हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों और जिला पुस्तकालयों की योजना और प्रबंधन (क्षेत्र आधारित – शिमला) | 7–12 जून (6 दिन) | 34 |
| | | **3** | **17** | **72** |
| **अध्ययन दौरा कार्यक्रम** | | | | |
| 34. | 08.2 | बंगलादेश के उच्चस्तरीय शिक्षा शिक्षा प्रतिनिधि मंडल का अध्ययन दौरा कार्यक्रम | 1–15 दिसंबर (15 दिन) | 10 |
| 35. | 07.3 | आई एस एस प्रविक्षाधीन अधिकारियों द्वारा नीपा दौरा | 8 सितबंर (1 दिन) | 27 |
| | | **2** | **16** | **37** |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| **अन्य कार्यक्रम** | | | | |
| 36. | 06.2 | तृतीयक शिक्षा में मानवाधिकार पर विचारोत्तेजक सत्र | 3 जून (1 दिन) | 20 |
| 37. | 05.2 | हिमाचल प्रदेश में विद्यालय सुधार की योजना पर कार्यशाला | 26–27 जुलाई (2 दिन) | 10 |
| 38. | 09.1 | डी आई एस ई आंकडा के प्रतिदर्श वैधता पर राष्ट्रीय कार्यशाला | 30–31 अगस्त (2 दिन) | 23 |
| 39. | 09.2 | परियोजना की योजना और मानिटरिंग | 14–18 फरवरी (5 दिन) | 25 |
| 40. | 04.1 | राष्ट्रीय शिक्षानीति के विश्लेषण और समीक्षा हेतु परिचर्चा बैठक | 13–14 मार्च (2 दिन) | 66 |
| 41. | 08.4 | भूटानी शैक्षिक कार्मिकों के लिए कार्यालय प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम | 20–21 मार्च (2 दिन) | 2 |
| | | **6** | **14** | **146** |
| **महायोग** | | **41** | **558** | **1303** |

* इस सूची में पिछले वर्ष से चल रहे डिप्लोमा कार्यक्रम (एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय) भी शामिल हैं।

**कोड संख्या**

01. शैक्षिक योजना एकक
02. शैक्षिक प्रशासन एकक
03. शैक्षिक वित्त एकक
04. शैक्षिक नीति एकक
05. विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक
06. उच्च शिक्षा एकक
07. प्रादेशिक प्रणाली एकक
08. अंतर्राष्ट्रीय एकक
09. संक्रियात्मक अनुसंधान और प्रणाली प्रबंधन एकक
10. पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र

# अनुलग्नक II

## संकाय का अकादमिक योगदान : 1999-2000

**जी. डी. शर्मा**

**रिपोर्ट**

'इंटरनेशनलाइजेशन आफ हायर एजुकेशन – इसूज एण्ड पालिसी सजेसंस,' भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्टीयकरण और विदेशी विश्वविद्यालयों का संचालन पर 26–27 नवंबर 1999 को आयोजित संगोष्ठी की रिपोर्ट

'टूवार्ड्स एसेसमेंट आफ क्वालिटि आफ हायर एजुकेशन' "उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का आकलन : प्रतिमान और संकेतक" पर 18–19 जनवरी को आयोजित संगोष्ठी की रिपोर्ट

महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम (7–25 फरवरी 2000)

*दीक्षांत संभाषण*

"उच्च शिक्षा : जन सामान्य और विकास", डी. ए. वी. महाविद्यालय, चंडीगढ़, 25 मार्च 2000

**आलेख और शोध पत्र**

मेकिंग दि सिस्टम आफ हायर एजुकेशन ऐज डायनामिक्स ऐज नेवर बिफोर आइडेंटिटी एण्ड सोशल पोजीशन आफ वूमेन इन दि डवलमेंट कांटेक्स्ट – कमला नेहरू कालेज फगवाड़ा में प्रस्तुत आलेख

फायनेंसिंग आफ हायर एजुकेशन इन इंडिया – इन रेट्रोस्पेक्ट एण्ड प्रास्पेक्ट – दिल्ली

विश्वविधालय में प्रस्तुत आलेख

पर्सपेक्टिव्स आफ डवलपमेंट इन 21 सेंचुरी – आलेख

इंटरनेशनलाइजेशन आफ हायर एजुकेशन – स्टेटस एण्ड पालिसी सजेंसंस

पालिसी स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फायनेंसिंग आफ हायर एजुकेशन

टूवार्ड्स फ्यूचर डवलपमेंट आफ एजुकेशन, डेमोक्रेसी एण्ड दि सोसायटी – दीक्षांत संभाषण

प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस्टेबलिशमेंट बिल

रिफार्म्स इन एजुकेशन इन इंडिया–ए पोजिशन पेपर पर संक्षिप्त टिप्पणी

**बैठकों और संगोष्ठियों में भागीदारी**

नीपा में विश्वविद्यालयी वित्त व्यवस्था पर आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम में व्याख्यान, 23–29 सितंबर 1999

जामिया हमदर्द में उच्च शिक्षा में नीति योजना पर आयोजित संगोष्ठी में व्याख्यान, 15–16 सितंबर 1999

सामाजिक परिवर्तन के विशेष संदर्भ में भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था : शुरुआत और हस्तक्षेप पर मुख्य व्याख्यान दिया

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में मूल्य आधारित शिक्षा पर 13–14 नवंबर 1999 को आयोजित संगोष्ठी में सहभागिता

कमला नहेरू कालेज फगवाड़ा में दिसंबर 1999 में 'नारी अस्मिता का संघर्ष : साहित्य, समाज और राजनीति के संदर्भ में' पर आयोजित संगोष्ठी में आलेख प्रस्तुत किया।

जाकिर हुसेन शिक्षा अध्ययन केंद्र, जवाहर लाल नहेरू विश्वविद्यालय में 'गुणवत्ता की संप्राप्ति: उच्च शिक्षा की चुनौतियां, पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया और डेलोर्स समिति रिपोर्ट – विद्या : एक अतःस्थित निधि पर आलेख प्रस्तुत किया।

कोयंबटूर में 25–26 दिसंबर 1999 को आयोजित भारतीय समाज विज्ञान अकादमी की बैठक में भाग लिया।

मानव संसाधन विकास केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय में 20 जनवरी 2000 को विश्वविद्यालय प्रशासकों का प्रशिक्षण और विकास पर आयोजित परिसंवाद गोष्ठी में भाग लिया।

सामुदायिक शिक्षा शोध और विकास केंद्र, चेन्नई में 18–19 फरवरी 2000 को भारत में वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा व्यवस्था के रूप में सामुदायिक महाविद्यालय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

सी आर शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक, हरियाणा में 24–25 मार्च 2000 को अध्यापक की जवाबदेही और अध्यापक संगठन पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

चयन समिति की विभिन्न बैठकों में भाग लिया।

पुणे में दिसंबर 1999 में आई सी एफ वार्षिक सम्मेलन में महाविद्यालय प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर व्याख्यान।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली में आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम में भागीदारों के समक्ष व्याख्यान।

**एम. मुखोपाध्याय**

**प्रकाशन**

लर्निंग : दि ट्रिजर विदिन – इंप्लिकेसंस फार एशिया, एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन की रिपोर्ट, नीपा : नई दिल्ली 1999

इंडियन ओपन एण्ड डिस्टेंस एजुकेशन : प्रास्पेक्ट्स *ओपन एण्ड डिस्टेंस एजुकेशन* (सं) मंजूलिका एस. और रेडी वी. नई दिल्ली, अल्वा 2000

एजुकेशन इन दि 21 सेंचूरी, *इंडिया फोरम बुलेटिन,* अप्रैल 1999

चैंजिंग फेसेज आफ एजुकेशनल टेक्नालाजी, वि. अ. आ. द्वारा प्रायोजित और पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य व्याख्यान

टैक्सानॉमी आफ एजुकेडनेस, *यूनिवर्सिटी न्यूज* जून 1999

एजुकेशन इन फंडामेंटल ड्यूटीज एट स्कूल लेवल, वर्मा आयोग की रिपोर्ट में योगदान, एन सी ई आर टी, नई दिल्ली 1999

फंडामेंटल ड्यूटीज इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वर्मा आयोग की रिपोर्ट में योगदान, एन सी ई आर टी, नई दिल्ली

**सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भागीदारी**

सबके लिए शिक्षा, नई दिल्ली, 1999

संप्रेषण प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, गुवाहाटी, 1999

सूचना प्रौद्योगिकी, एन सी ई आर टी, नई दिल्ली 2000

**विद्वत सोसाइटियों को संबोधन**

अंतरविषयी शिक्षा, भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे, अगस्त 1999

बहुमाध्यमी शिक्षा, स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, आकाशवाणी, 15 अक्तूबर 1999

अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या का ढांचा, वाई सी एम ओ यू, नासिक, 23 मार्च, 2000

अनुक्रियात्मक संप्रेषण प्रौद्योगिकी, गुवाहाटी, 1999

विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के संगठनात्मक पक्ष, एन सी ई आर टी, नई दिल्ली, 2000

**समितियों की सदस्यता**

अध्यक्ष, शासी निकाय, रविंद्र मुक्त विद्यालय, (पश्चिम बंगाल मुक्त विद्यालय)

सदस्य, कार्यकारी समिति, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, पश्चिम बंगाल, कोलकाता

सदस्य, कार्यकारी समिति, गुजरात राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, अहमदाबाद

सदस्य, कार्यकारी परिषद्, तालीम शोध पीठ, भोपाल, अहमदाबाद

सदस्य, परामर्शकारी समिति, भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन शोध संस्थान, जयपुर

सदस्य, फिक्की शिक्षा समिति, नई दिल्ली

सदस्य, परामर्शकारी समिति, डी ई पी – डी पी ई पी, इं. गा. रा. मु. विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

कार्यकारी सदस्य, अखिल भारतीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संघ

अध्यक्ष, हावड़ा ग्रामीण अध्यापक मंच, उदांग, हावड़ा

**जे.बी.जी. तिलक**

**संचालित प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रम**

विश्वविद्यालयी वित्तव्यवस्था के प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 23–29 सितंबर 1999

शिक्षा की वित्तव्यवस्था के प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम (29 नवंबर – 3 दिसंबर 1999)

**शोध**

**आलेख/पुस्तकें/पुस्तकाकार मोनोग्राफ* (संदर्भित प्रकाशन)**

'एजुकेशन एण्ड डवलपमेंट : लेसंस फ्राम एशियन एक्सपेरियंस', विशेष व्याख्यान, अगली सहस्त्राब्दि में एशिया : शांति और विकास की संभावनाएं, मकती, फिलीपाइंस (7–8 जनवरी 2000)

*''एजुकेशन पावर्टी इन इंडिया'', *वर्ल्ड डवलपमेंट रिपोर्ट 2000* भारत में गरीबी पर एन जी ओ अकादमिक पेपर के लिए आधार आलेख (मई 1999)

''स्टैटिस्टिक्स आन एजुकेशन : स्कोप, रिक्वायर्मेंट्स, गैप्स एण्ड स्टेटस'',, *डाटा बेस आफ इंडियन इकानमी* (सं. सी. पी. चंद्रशेखर और जांध्याला बी. जी तिलक) नई दिल्ली : भा. सा. वि. अ. प. (प्रेस में) (पी आर पंचमुखी के साथ)

एजुकेशन फार आल इन साउथ एण्ड वेस्ट एशिया : ए डिकेड आफ्टर जोमेतियन : एन एसेसमेंट : संश्लिष्ट रिपोर्ट नई दिल्ली यूनेस्को/दक्षिण और पश्चिम एशिया क्षेत्रीय तकनीकी सलाहकारी समूह, फरवरी 2000

*'इनवेस्टमेंट इन हयूमन कैपिटल इन इंडिया : एन इंटर स्टेट एनलिसिस आफ स्टॉक एण्ड फ्लो आफ हयूमन कैपिटल'' *पर्सपेक्टिव्स इंडियन डवलपमेंट : इकानमी पोलाइटी, एण्ड सोसायटी* प्रो. बी सर्वेश्वर राव के सम्मान में निबंध, (नई दिल्ली : स्टार्लिंग 200) पृ. 275–246

*''इमर्जिंग ट्रेंड्स एण्ड इवाल्विग पब्लिक पालिसीज आन प्राइवेटाइजेशंन आफ हायर एजुकेशन इन इंडिया'' *प्राइवेट प्रामेथस : प्राइवेट हायर एजुकेशन एण्ड डवलपमेंट इन दि 21 सेंचुरी* सं पी. जी. रिलम्टैंट, ग्रीनवुड पब्लिशिंग, वेस्ट वोर्ट 1999, पृ. 113–135

*''डवलपमेंट एसिस्टेंस टू प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया : ट्रांसफार्मेशन आफ इनथ्रूजियास्टिक डोनर्स एण्ड रेसिपिएंटस, चैंजिंग इंटरनेशनल एड टू एजुकेशन : ग्लोबल पैटर्न एण्ड, नेशनल कांटेक्सटस (सं. केनेथ किंग और लेने बूचर) नोराग के सहयोग से यूनेस्को 1999, पृ. 307–17

"फायनेंसिग टेक्निकल हायर एजुकेशन इन इंडिया" इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग : (सं.) एस. मिश्रा और पी जी वी चंद नई दिल्ली : मैक्ग्रा हिल, 1999

'एलिमेंटरी एजुकेशन इन रूरल इंडिया : प्रामिजेज एण्ड परफार्मेंस" बेसिक रूरल इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज फार इंप्रूव्ड क्वालिटि आफ लाइफ : (सं.) आर सी चौधरी और पी दुर्गा प्रसाद हैदराबाद : राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान, 1999 पृ. 449–78

"एजुकेशन एण्ड पावर्टी इन साउथ एशिया" *प्रास्पेक्ट्स* 29 (4) दिसंबर 1999 : 517–33

एक्सप्लोडिंग सम इकानमिक मिथ्स आफ एलिमेंटरी एजुकेशन, दि हिंदू (5 अक्तूबर 1999)

"मेक एजुकेशन कंपलसरी ? " *इकानमिक टाइम्स* (7 दिसंबर 1999)

**पुस्तक समीक्षाएं**

दि वैल्थ आफ दि वर्ल्ड एण्ड दि पावर्टी आफ नेशंस *(डी कोडन) जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन* 14(1) जनवरी 2000 : 122–23

वर्ल्ड इंपलायमेंट रिपोर्ट (आई एल ओ) और वर्ल्ड डवलमेंट रिपोर्ट 1999 (वर्ल्ड बैंक), *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन* 13 (4) अक्तूबर 1999 : 509–11

आपर्च्यूनिटी फारगॉन : एजुकेशन इन ब्राजील : (सं.) एन बर्डसाल और आर सबोट आदि, *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन* 13 (3) जुलाई 1999 : 385–86

इकानॉमिक एण्ड सोशल डवलपमेंट इनटू दि XXI सेंचुरी *(एल. इम्मरीज), जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन* 13(2) अप्रैल 1999 : 261–63

**संगोष्ठियों में भागीदारी**

संसाधनों की लामबंदी : शिक्षा के क्षेत्र में नीतियां और रणनीतियां, पटना, राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान (25 मार्च 2000) (एक सत्र की अध्यक्षता और एक आलेख का प्रस्तुतिकरण)

शिक्षा की प्राथमिकता का निर्धारण : शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करना, जयपुर, कनोड़िया पी जी महिला महाविद्यालय, (13–15 मार्च 2000) (व्याख्यान)

अगली सहस्त्राब्दी में एशिया : शांति और विकास की संभावनाएं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मकती, सिटी, फिलीपाइंस (8 जनवरी 2000) (विशेष व्याख्यान )

सबके लिए शिक्षा : आकलन 2000 पर एशिया–प्रशांत सम्मेलन, बैकांक : यूनेस्को : प्रॉप 17–20

जनवरी 2000 (संश्लिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की और दक्षिण–पश्चिम एशिया उपक्षेत्रीय स्म्मेलन के लिए मुख्य रिपोर्टर की भूमिका निभाई)

शिक्षा : दक्षिण एशिया के सदर्भ में शिक्षा पर दक्षिण एशियाई सम्मेलन : दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय (14–18 नवंबर 1999){परिचर्चाकार}

गुणवत्ता संप्राप्ति : उच्च्य शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां पर संगोष्ठी, मई दिल्ली : जवाहर लाल नहेरू विश्वविद्यालय (3–4 नवंबर 1999) { वित्त व्यवस्था पर प्रस्तुतिकरण}

शिक्षा में वित्तव्यवस्था, सुलभता और अवसर पर खुलामंच, नई दिल्ली : इंडिया हैविटैंट सेंटर {परिसंवादकर्ता} (29 अक्तूबर 1999)

सबके लिए शिक्षा–आकलन 2000 पर दूसरी उपक्षेत्रीय कार्यशाला, यूनेस्को/दक्षिण और पश्चिम एशिया क्षेत्रीय तकनीकी परामर्शकारी समूह (काठमांडु, नेपाल, 12–13 अक्तूबर 1999) {संश्लिष्ट रिपोर्ट का प्रारूप प्रस्तुत किया}

"शैशवकालीन देखभाल और विकास" पर विचारोत्तेजक कार्यशाला, चेन्नई : एम एस स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान (30 सितंबर – 1 अक्तूबर) { शै. का. दे. वि. की लागत के अनुमान पर प्रस्तुति}

भारत में आर्थिक और नीतिगत सुधार पर ए डी बी–एन सी ए ई आर कार्यशाला, नई दिल्ली: राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक शोध परिषद् (19–10 सितंबर 1999) { परिचर्चाकार}

शैक्षिक शोध में अंतर–शास्त्रीयता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, पुणे : भारतीय शिक्षा संस्थान (30 अगस्त–1 सितंबर 1999) { आलेख प्रस्तुति}

प्राथमिक शिक्षा की लागत और अपव्यय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, बैंगलौर : सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान (11–13 अगस्त 1999) { परिसंवादकर्ता}

21वीं शताब्दी के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कार्यसूची का निर्धारण : केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की कार्यशाला, शांतिनिकेतन : विश्वभारती, मा. स. वि. मं. (30 जुलाई – 1 अगस्त 1999) { विश्वविद्यालयों की वित्त व्यवस्था पर एक प्रस्तुति}

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में नागरिक पहल का जनाधार, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में नागरिक पहल, नई दिल्ली (8-10 जून 1999, नैनीताल) प्ररंभिक शिक्षा के आर्थिक पक्षों पर एक प्रस्तुतिकरण

प्रारंभिक शिक्षा आकलन पर दक्षिण और पश्चिम एशिया क्षेत्र की कार्यशाला : यूनेस्को/दक्षिण और पश्चिम एशिया क्षेत्रीय तकनीकी परामर्शकारी समूह (25–26 मई 1999) { राष्ट्रीय आलेखों पर टिप्पणी की प्रस्तुति}

सबके लिए शिक्षा : आकलन 2000 पर राष्ट्रीय कार्यशाला, नई दिल्ली : भारत सरकार, यूनिसेफ और यूनेस्को (20 मई 1999)

भारत में सामाजिक सुरक्षा पर संगोष्ठी, नई दिल्ली : मानव विकास संस्थान और भारतीय श्रम अर्थशास्त्र सोसायटी (15–17 अप्रैल 19999) { परिचर्चाकार की भूमिका निर्वहन}

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति पर सम्मेलन, नई दिल्ली : राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (5–6 अप्रैल 1999)

शिक्षा का व्यावसायीकरण : नई सहस्त्राब्दी का संप्रेक्ष्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन, भोपाल : पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान नई दिल्ली (4–6 अप्रैल 1999)

**अन्य**

शिक्षा गारंटी योजना पर परिसंवाद, (दूरदर्शन समाचार चैनल–1999)

**व्यावसायिक निकायों की सदस्यता**

आजीवन सदस्य, आर्थिक और सामाजिक शोध सोसायटी, दिल्ली

आजीवन सदस्य, आंध्र प्रदेश इकानामिक्स एसोसिएशन

आजीवन सदस्य, भारतीय शैक्षिक योजना और प्रशासन परिसंघ

मानद सदस्य, रिसर्च बोर्ड आफ डायरेक्टर्स, अमरीकी जैव वैज्ञानिक संस्थान

**व्यावसायिक जर्नलों के संपादक मंडल की सदस्यता**

संपादक, जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन

सदस्य, संपादकीय सलाहकार मंडल, हायर एजुकेशन पालिसी

संपादकीय सलाहकार, *स्टडीज इन एजुकेशन* (नाईजिरिया)

संमीक्षकों की संपादकीय सलाहकारी परिषद, *फिलीपाईन जर्नल आफ हायर एजुकेशन* (मनीला)

सदस्य, संपादकीय मंडल, मैनपावर जर्नल

संपादकीय सलाहाकर, जर्नल एजुकेशन सिस्टम्स रिसर्च एंड डवलपमेंट (नाईजीरिया)

सदस्य, संपादक मंडल, इंटरनेशनल जर्नल आफ एजुकेशनल पालिसी रिसर्च एण्ड प्रैक्टिस (फलोरिडा, अमेरिका)

**परामर्शकारी सेवाएं**

मालद्वीप में 'सबके लिए शिक्षा', पर देश की रिपोर्ट और दक्षिण तथा पश्चिम एशिया (1999–2000) में सबके लिए शिक्षा पर संश्लिष्ट रिपोर्ट तैयार करने में यूनेस्को को परामर्शकारी सेवाएं प्रदान की।

**भारत सरकार और अन्य निकायों के लिए परामर्शकारी सेवाएं**

**सदस्य, कार्यकारी समिति, आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा सोसायटी**

**सदस्य, महापरिषद, आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा सोसायटी**

**सदस्य, राज्य स्तरीय साधिकार समिति,** (डाइट की स्थापना पर) शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार

**संयोजक, शैक्षिक आंकड़ा बैंक की स्थापना के उद्देश्य से कार्यवाई योजना के विकास के लिए शिक्षा का कार्यबल, भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद**

**सदस्य, आर्थिक अध्ययन पर लोक जुम्बिश समिति,** जयपुर लोक जुम्बिश परिषद

**सदस्य, शिक्षा चिंतन मंच, सूर्या फाउंडेशन, नई दिल्ली**

**सदस्य, अकादमिक परिषद, शिक्षा संकाय,** दिल्ली विश्वविद्यालय

**सदस्य, शिक्षा समिति, फिक्की, नई दिल्ली**

**विदेश दौरे**

**फिलिपाइंस :** नई सहस्त्राब्दी में एशिया : शांति और विकास की संभावनाएं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेष व्याख्यान (7–8 जनवरी 2000)

**थाइलैंड :** दक्षिण और पश्चिम एशिया उप क्षेत्रीय सम्मेलन और सबके लिए शिक्षा आकलन – 2000 पर एशिया प्रशांत सम्मेलन में दक्षिण और पश्चिम एशिया में सबके लिए शिक्षा पर संश्लिष्ट रिपोर्ट की प्रस्तुति, बैंकाक : यूनेस्को : प्रोप, 17–20 जनवरी 2000

**मालदीव :** सबके लिए शिक्षा की रिपोर्ट को अंतिम रूप देना, (4–8 अक्तूबर 1999) (यूनेस्को, नई दिल्ली)

**नेपाल :** सबके लिए शिक्षा–आकलन 2000 पर द्वितीय उपक्षेत्रीय कार्यशाला में सहभागिता, यूनेस्को/दक्षिण और पश्चिम एशिया क्षेत्रीय तकनीकी परामर्शकारी समूह (काठमांडु, नेपाल, 12–13 अक्तूबर 1999)

**अन्य**

*जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन* का संपादन कार्य

**वाई. पी. अग्रवाल**

**प्रकाशित पुस्तकें**

प्राइमरी एजुकेशन इन अनरिकगनाइज्ड स्कूल्स इन हरियाणा : ए स्टडी आफ डी पी ई पी डिस्ट्रिक्ट्स, नीपा, नई दिल्ली

ट्रेंड्स इन एसेस एण्ड रिटेंशन : ए स्टडी आफ प्राइमरी स्कूल्स डी पी ई पी, नीपा,/एडसिल, नई दिल्ली, अक्तूबर 1999

**प्रकाशनाधीन पुस्तकें**

प्राइमरी एजुकेशन इन दिल्ली : हाउ मच डू दि चिल्ड्रेन लर्न? नीपा, नई दिल्ली

**प्रकाशित आलेख**

एसेस एण्ड रिटेंशन अंडर डी पी ई पी : इमार्जिंग ट्रेंड्स, *डी पी ई पी कालिंग,* दिसंबर 1999

स्कूल एटेंडेंस : इविडेंस फ्राम सेलेक्टेड डी पी ई पी डिस्ट्रिक्ट्स, *डी पी ई पी कालिंग,* जून 1999

रिविटेलाइजेशन आफ एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार

इनफार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेकनोलाजीस इन एजुकेशनल मैनेजमेंट : दि

मिसिंग डायमेंशन इन डवलपिंग कांट्रीज, *पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन,* विशेषांक, 1999

**प्रकाशनार्थ स्वीकृत आलेख**

एजुकेशन एण्ड चेंजिंग डिमांड्स आफ दि वर्ल्ड : सम रेफलेक्शंस, *इंडियन जर्नल आफ वोकेशनल एजुकेशन*

**संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत आलेख**

भारतीय शैक्षिक योजना और प्रशासक सघ तथा वरिष्ठ नागरिक मंच, नीपा द्वारा संयुक्त रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रबंधन पर आयोजित संगोष्ठी में *दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे कितना सीखते हैं ?* विषय पर व्याख्यान

एन सी ई आर टी, नई दिल्ली में 21वीं सदी में व्यावसायिक शिक्षा पर आयोजित संगोष्ठी में कार्य की दुनिया में मांगों के बदलते स्वरूप और शिक्षा पर व्याख्यान

एन सी ई आर टी द्वारा विज्ञान भवन में प्राथमिक स्तर पर विद्यालय की प्रभाविकता संबंधी शोध विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में *डी पी ई पी के अंतर्गत सुलभता और धारण क्षमता : कुछनवीनतम रुझान पर व्याख्यान, जुलाई 1999*

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 8 जुलाई 1999 को दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर आलेख प्रस्तुति

श्रीलंका में यूनिसेफ संगोष्ठी में 'भारत : अधिगम संप्राप्ति का एक आकलन' विषय पर आलेख प्रस्तुति, जुलाई 1999

सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बैंगलोर में प्राथमिक शिक्षा की लागत और अपव्यय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर सांस्थानिक लागतों की संरचना और प्रवृत्तियां : एक केस अध्यय विषय पर आलेख प्रस्तुति

बैंगलोर में सूचना प्रणाली समीक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत में विद्यालय सूचना प्रणाली की समीक्षा और वैधता : एक अध्ययन पर आलेख प्रस्तुति, दिसंबर 1999

विज्ञान भवन में एन आई सी और ब्रिटिश कांउसिल द्वारा टास्कनेट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम विकास और शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रयोग विषय पर आलेख प्रस्तुति, नवंबर 1999

**पूरे किए गए शोध अध्ययन/आलेख**

पांच वर्षों में कितने बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करते हैं : तमिलनाडु के चुनिंदा डी पी ई पी जिलों के साक्ष्य, नीपा 2000

शिक्षा में राजकीय और निजी साझेदारी : हरियाणा के गैर–मान्यता प्राप्त विद्यालयों का केस अध्ययन

डी आई एस ई आंकडा की उत्तर–परिगणन प्रतिदर्श वैधता, डी पी ई पी द्वारा प्रायोजित अनुसंधान अध्ययन की रिपोर्ट (अप्रैल 1999)

**राज्यों/केंद्रीय सरकार को व्यावसायिक/तकनीकी समर्थन**

15 डी पी ई पी राज्यों को जिला शिक्षा सूचना प्रणाली स्थापित करने और उनके रखरखाव के लिए तकनीकी और व्यावसायिक समर्थन

डी पी ई पी जिलों के गुच्छक (कोहर्ट) अध्ययनों के रुपांकन और संयोजन में तमिलनाडु डी पी ई पी परियोजना को सहायता

असम में शैक्षिक आंकड़ा की वैधता के लिए उत्तर परिगणन सर्वेक्षण के संयोजन में डी पी ई पी को सहायता

उड़ीसा में डी पी ई पी जिलों में बालविकास प्रणाली के रूपांकन और विकास में सहयोग

प्राथमिक कक्षाओं की पूर्णता दर का अनुमान लगाने के उद्देश्य से गुच्छक (कोहर्ट) अध्ययन के

संचालन के लिए हरियाणा डी पी ई पी को सहायता

राज्य स्तरीय विद्यालय सूचना प्रणाली और डी आई एस ई के बीच अंतरापृष्ठ के विकास में आंध्र प्रदेश को सहायता

शिक्षा पर पारिवारिक आंकड़ा के विश्लेषण में कर्नाटक को सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के लिए *भारत में साक्षरता की स्थिति का विश्लेषण,* विषय पर आलेख प्रस्तुति

**के. सुधा राव**

**प्रकाशित पुस्तकें**

मैनेजमेंट आफ आटोनोमी इन आटोनोमस कालेजेज, विकास पब्लिशर्स, नीपा, नई दिल्ली 1999

केस स्टडीज आफ आटोनोमस एण्ड नान आटोनोमस, विकास पब्लिशर्स, नीपा, नई दिल्ली 1999

संपादन, बेस्ट प्रैक्टिसेज इन हायर एजुकेशन

एकेडेमिक रिन्यूवल एण्ड लिंकिंग एजुकेशन एण्ड इंप्लायमेंट–एन एनोवेटिव एक्सपेरिमेंट, नीपा, नई दिल्ली 1999

**शोध परियोजना रिपोर्ट**

प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट आफ वोकेशनलाइजेशन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल : दि स्टेट आफ आर्ट, नीपा 1999 (बी.के.बारीक के साथ)

**स्वअधिगम सामग्री**

प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट आफ हायर एजुकेशन एट सिस्टमेटिक लेवल : दूरवर्ती शिक्षा स्टाफ प्रशिक्षण और शोध संस्थान, इं.गां.रा.मु.वि., 1999

प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट आफ हायर एजुकेशन एट इंस्टीट्यूशनल लेवल, दूरवर्ती शिक्षा स्टाफ प्रशिक्षण और शोध संस्थान, इं.गां.रा.मु.वि. 1999

**शोध पत्र/आलेख**

आटोनामी एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड क्वालिटी : चैलेजेंज फार इंस्टीट्यूशंस आफ हायर लर्निंग,, पोर्ट लैंड ओरेगांन, अमरीका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत आलेख, संगोष्ठी कार्रवाई रिपोर्ट में प्रकाशित, अक्तूबर 1999

ह्यूमन राइट्स एट दि कालेज लेवल : प्रिंसिपल पर्सपेक्टिव, नीपा मिमियोग्राफ (सुश्री आरती छत्रपथी) 1999

## संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं/टी वी वार्ताओं में भागीदारी

### अंतर्राष्ट्रीय

"उच्च शिक्षा में परंपरा और परिवर्तन : भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में परंपरा और नव परिवर्तन का एशिया – प्रशांत संप्रेक्ष्य पर एशिया – प्रशांत सम्मेलन : स्वायत्तता, प्रशासन और गुणवत्ता: उच्च शिक्षा संस्थानों की चुनौतियां विषय पर आलेख प्रस्तुत किया, पोर्टलैंड, ओरेगांन अमरीका 28–30 अक्तूबर 1999

जामिया हमदर्द के प्लेटिनम जुबिली वर्ष के उपलक्ष्य में ब्रिटिश काउंसिल, ब्रिटिश हाईकमीशन और जामिया हमदर्द के सहयोजन में भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ (ए आई यू ) द्वारा मानव विकास के लिए उच्च शिक्षा पर संगाष्ठी, 22–24 फरवरी 2000

### राष्ट्रीय

शिक्षा का व्यावसायीकरण : नई सहस्त्राब्दी के लिए संप्रेक्ष्य पर एन सी ई आर टी, द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन, आई आई टी सेमिनार हाल, नई दिल्ली 4–6 अप्रैल 1999

फिक्की, एसोचम, स्कोप, एन सी ए ई आर द्वारा राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धानीति पर प्रायोजित राष्ट्रीय सम्मेलन, विज्ञान भवन, नई दिल्ली 5–6 अप्रैल 1999

मानवाधिकार शिक्षा : अनुभव और प्रत्याशाएं विषय पर वि.अ.आ. द्वारा एन एस सी नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला, 13–14 अप्रैल 1999

महिला प्रबंधकों में उत्कृष्टता का विकास पर राष्ट्रीय एकीकृत प्रबंधन और प्रशिक्षण अकादमी द्वारा आयोजित संगोष्ठी, 'निर्णय कार्य में महिलाएं' विषय आलेख की प्रस्तुति, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 7 मई 1999

टी वी कार्यक्रम – क्रास फायर में विश्वविद्यालयी शिक्षा और आवश्यक सुधार विषय पर आयोजित परिचर्चा में परिसंवादकर्ता

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के लिए विश्वभारती, शांति निकेतन, कोलकाता में 21वीं सदी के परिवर्तन की कार्यसूची निर्धारण पर आयोजित संगोष्ठी, 30 जुलाई – 1 अगस्त 1999

भारतीय समाज विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा मानवाधिकार शिक्षा पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला, मानवाधिकार महाविद्यालय : प्राचार्यों के दृष्टिकोण विषय पर आलेख प्रस्तुति, 27–28 अगस्त 1999

जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर नई दिल्ली के सहयोग से भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ द्वारा उच्च शिक्षा की नीति संबंधी योजना पर आयोजित संगोष्ठी, 5–6 सितंबर 1999

केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानवाधिकार संगोष्ठी सहित कार्यशाला, इंडिया हैबिटैट सेंटर, लौदी रोड, नई दिल्ली 28 फरवरी 2000

पी एस एस सी आई वी ई/एन सी ई आर टी द्वारा विद्यालयी शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संरचना के प्रारूप पर परिचर्चा, भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, हैदराबाद, 7 मार्च 2000

सर्व शिक्षा अभियान की मार्गदर्शिका के प्रारूप पर चर्चा के लिए एक दिवसीय संगोष्ठी, नीपा नई दिल्ली, 8 मार्च 2000

एन ए आई एम टी द्वारा अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व. वर्ग के कार्यपालकों में उत्कृष्टता का विकास पर संगोष्ठी, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली, 9–10 मार्च 2000

उच्च शिक्षा की प्राथमिकताएं पर संगोष्ठी, कनोडिया कालेज, जयपुर 15 मार्च 2000

**प्रमुख परामर्श और सलाहकारी सेवाएं**

सदस्य, विशेषज्ञ समिति, दीर्घ/लघु शोध परियोजनाएं, दूरवर्ती शिक्षा परिषद, इं.गां.रा.मु.वि., हौज खास, नई दिल्ली

सदस्य, महिला अध्ययन पर वि.अ.आ. की स्थाई समिति की उपसमिति, वि.अ.आ., नई दिल्ली

सदस्य, विश्वविद्यालय योजना बोर्ड, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली

सदस्य, तेरहवां विकास सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

सदस्य, लघु शोध परियोजनाओं की वि.अ.आ. मूल्याकंन विशेषज्ञ समिति, वि.अ.आ. नई दिल्ली

सदस्य, अकादमिक परिषद, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, राजस्थान

सदस्य, अकादमिक सलाहकार परिषद्, उच्च शिक्षा व्यावसायिक केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

सदस्य, विशेषज्ञ समिति, उत्तर प्रदेश उच्च सेवा आयोग, इलाहाबाद उ.प्र.

सदस्य, सत्रमध्य समीक्षा समिति, पेरियार विश्वविद्यालय, (वि.अ.आ. द्वारा मनोनीत)

सदस्य, विशेषज्ञ समिति, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली

सदस्य, अकादमिक स्टाफ कालेज की अकादमिक सलाहकार समिति, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली

सदस्य, सलाहाकार समिति, गोवा विश्वविद्यालय अकादमिक स्टाफ कालेज, गोवा

सदस्य, स्वायत्त महाविद्यालय समीक्षा समिति (वि.अ.आ. मनोनीत), उदय प्रताप कालेज, वनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

सदस्य, परियोजना सलाहाकार समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर डी एस टी परियोजना, भारत में निर्माण उद्योग के लिए जनशक्ति विकास, आई एस टी ई, नई दिल्ली

**के. सुजाता**

**प्रशिक्षण कार्यक्रम/अध्ययन दौरे/कार्यशालाएं**

तंजानिया के वरिष्ठ अधिकारियों का अध्ययन दौरा

रवांडा के एक प्रतिनिधिमंडल का अध्ययन दौरा

बंगला देश के शिक्षा अधिकारियों का अध्ययन दौरा

एरिट्रिया के एक प्रतिनिधिमंडल का अध्ययन दौरा

नेपाल के एक प्रतिनिधिमंडल का अध्ययन दौरा

बंगला देश के बी आर ए सी अधिकारियों का अध्ययन दौरा

अंतर्राष्ट्रीय क्रिश्चियन विश्वविद्यालय, टोक्यो, जापान के छात्रों का अध्ययन दौरा

भूटानी अधिकारियो के लिए कार्यालय प्रबंधन में अभिविन्यास कार्यक्रम

शैक्षिक योजना और प्रशासन में 16वां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा)

**सुदेश मुखोपाध्याय**

**प्रकाशन**

मैनेजमेंट् आफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स फार पीपुल विद विजुवल इंपेयरमेंट्स (सं) फर्नांडीज जी और अन्य, *सी विद दि ब्लाइंड*, बैंगलौर : क्रिस्टोफल ब्लाइंडेन मिशन एण्ड बुक फार चेंज, 1999

माध्यमिक शिक्षा के उभरते मुद्दे, *परिप्रेक्ष्य*, वर्ष 6 अंक 3, दिसंबर 1999

**परामर्शकारी सेवाएं**

निदेशक, एस सी ई आर टी, दिल्ली के रूप में दिल्ली सरकार के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रोन्नति परियोजना का मार्गदर्शन

डी पी ई पी के दसवें संयुक्त पर्यवेक्षण मिशन में सहभागिता (10–24 नवंबर 1999)

**अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भागीदारी**

नारी अस्मिता का संघर्ष पर कमला नहेरू कालेज फगवाड़ा में आयोजित संगोष्ठी में विकलांग महिलाएं : अस्मिता की तलाश पर आलेख प्रस्तुति, 17–19 दिसंबर 1999

दृष्टिहीनों की शिक्षा पर आई सी बी आई और डी वी आई के संयुक्त एशियाई सम्मेलन में दृष्टिहीनों की शिक्षा में गुणवत्ता सरोकार पर आलेख प्रस्तुति, अहमदाबाद, 8–10 फरवरी 2000

**प्रमिला मेनन**

**प्रशिक्षण सामग्री**

डाइट संकय और अल्पसंख्यक प्रबंधित संस्थानों के प्रमुखों के लिए प्रशिक्षण सामग्री–

बुनियादी शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी

अल्पसंख्यक शिक्षा की योजना और प्रबंधन

**प्रमुख परामर्शकारी और सलाहकारी सेवाएं**

शिक्षा विभाग, इं.गां.रा.मु.वि. द्वारा प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यचर्या के विकास के लिए आयोजित कार्यशाला में सहभागिता (प्रौढ़ शिक्षाकर्मियों के लिए व्यावसायिक विकास पाठ्यक्रम, 10 अगस्त 1999)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डी पी ई पी चरण I के राज्यों के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा पर तैयारी कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में सहभागिता, 14–16 फरवरी 2000

शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान की राज्य स्तरीय बैठक में सहभागिता, 4–5 फरवरी 2000

**संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भागीदारी**

डी एफ आई डी द्वारा सामुदायिक भागीदारी के लिए क्षमताओं का उन्नयन विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में सहभागिता और शैक्षिक विकास में सामुदायिक भागीदारी : भारतीय अनुभवों की समीक्षा'' विषय पर आलेख प्रस्तुति

**अरुण सी मेहता**

**संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी**

उच्च प्राथमिक शिक्षा पर आयोजित कार्यशाला में सहभागिता और उच्च प्राथमिक शिक्षा के अध्ययन के सारांश की प्रस्तुति, 14–15 फरवरी 2000, एडशिल, नई दिल्ली

सबके लिए शिक्षा आकलन वर्ष 2000 पर यूनेस्को, यूनिसेफ और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यशाला में सहभागिता और स.लि.शि. (सबके लिए शिक्षा) की प्रस्तुति, इंडिया हैबिटैंट सेंटर,

20 मई 1999, नई दिल्ली

दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया क्षेत्र के तकनीकी सलाहकार समूह द्वारा दक्षिण और पश्चिम एशिया की एजेंशियों के लिए आयोजित कार्यशाला में सहभागिता और स.लि.शि. के संकेतकों का प्रस्तुतिकरण, यू एन डी पी सम्मेलन कक्ष, 25–26 मई 1999, नई दिल्ली

भारत सरकार के एक दिवसीय कार्यशाला में सहभागिता और उच्च प्राथमिक शिक्षा के उभरते प्रमुख मुद्दों की प्रस्तुति, एन सी ई आर टी, 22 जून 1999, नई दिल्ली

**प्रकाशन**

एलिमेंटरी एजुकेशन इन इंडिया : एन ओवरव्यू, अमस्ता–मंगोल टीचर्स डे विशेषांक, मार्च/सितंबर 1999, वर्ष 4, अंक 5, 1995, मणिपुर विद्यालय अध्यापक परिसंघ

शैक्षिक योजना के लिए सूचना संबंधी आवश्यकताएं और मौजूदा सूचना व्यवस्था की कमियां, परिप्रेक्ष्य, अप्रैल–अगस्त 1998

स्टेटस आफ यू ई ई एन दि लाइट आफ एन सी ई आर टी सिक्स्थ आल इंडिया एजुकेशनल सर्वे, नीपा, सामयिक आलेख सं. 27, नई दिल्ली

**परामर्शकारी सेवाएं**

सदस्य, आध्र प्रदेश आकलन दल, डी पी ई पी, 11–16 मई 1999

सदस्य, स. लि. शि. आकलन वर्ष 2000 का राष्ट्रीय केंद्रिक समूह, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

सदस्य, राष्ट्रीय केंद्रीय समूह, उच्च प्राथमिक शिक्षा, मा. सं. वि. मं.

सदस्य, डी पी ई पी उत्तर प्रदेश के लिए भारत सरकार आकलन दल, जून 1999

**शोध परियोजना**

'भारत में उच्च प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण : विद्यालयी सुविधाओं और उनके लागत प्रतिफलों का विश्लेषण'' का संशोधित संस्करण (डॉ. एन.वी.वर्गीस के साथ)

शिक्षा क्षेत्र के लिए समान संयुक्त राष्ट्र आंकड़ा आधार के विकास के लिए एक अध्ययन कार्य पूरा किया। (यूनेस्को प्रायोजित अध्ययन)

सबके लिए शिक्षा – आकलन वर्ष 2000 के संबंध में स.लि.शि. के 18 मूल संकेतको का विकास

**पठन सामग्री**

विद्यालय प्रभाविकता के कारकों का अनुश्रवण करने के लिए स्थानीय सूचना प्रणाली के विकास की आवश्यकता

**अन्य शैक्षिक गतिविधियां**

सदस्य, संपादक मंडल, परिप्रेक्ष्य (हिंदी जर्नल), नीपा, नई दिल्ली।

**नलिनी जुनेजा**

**शोध रिपोर्टें**

प्राइमरी एजुकेशन फार आल इन दि सिटी आफ मुंबई, मिमियोग्राफ, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस

**परामर्शकारी सेवाएं**

अनिवार्य शिक्षा संबंधी विधेयक के अनुवर्तन पर कार्य समूह की प्रथम बैठक में सहभागिता, नवंबर 1999, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

अनिवार्य शिक्षा संबंधी विधेयक के अनुवर्तन पर कार्य समूह की दूसरी बैठक में सहभागिता, 28 फरवरी 2000, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

**अन्य शैक्षिक गतिविधियां**

इं.गां.रा.मु. विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति (संपर्क कार्यक्रम में योगदान), जून 1999

सी.बी.एस.ई. से संबद्धता के लिए दो विद्यालयों की निरीक्षण समितियों की संयोजिका, फरवरी 2000 और मई 2000

हिंदी जर्नल परिप्रेक्ष्य के संपादक मंडल की बैठक में सहभागिता, 21 जनवरी 2000

**संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भागीदारी**

राष्ट्रीय नगरीय उत्थान संस्थान द्वारा 18 और 19 मई को शिक्षा की नगर योजना पर आयोजित कार्यशाला में सहभागिता, नई दिल्ली

शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रारूपण पर आयोजित परामर्शकारी बैठक में सहभागिता, 9 जुलाई, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

भारत के चुनिंदा नगरों में विद्यालय से बाहर के बच्चों की अवस्थिति पर राष्ट्रीय स्तर की परिचर्चा बैठक में सहभागिता, एन आई यू ए, नई दिल्ली अक्तूबर 1999.

मुंबई में प्रस्तुतिकरण बैठक में सहभागिता, प्रथम सप्ताह, अक्तूबर 1999.

प्राथमिक शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी और सशक्तिकरण पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में सहभागिता, 8–10 दिसंबर 1999.

इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड में सबके लिए शिक्षा 2000 : आकलन की दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला में सहभागिता, 5–7 जनवरी 2000.

**एस. एम. आई. ए. जैदी**

**संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम**

शैक्षिक योजना में मात्रात्मक तकनीकों का प्रयोग, 12–23 जुलाई 1999, 12 दिन, 8 राज्यों/संध क्षेत्रों– असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और नीकोबार द्वीपसमूह तथा दादर और नागर हवेली से 16 भागीदार।

विद्यालय मानचित्रण और व्यष्टि स्तरीय योजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 9–13 अगस्त 1999, 5 दिन, 13 राज्यों/संघ क्षेत्रों–असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 24 भागीदार।

कार्यनीतियों के कार्यान्वयन को केंद्रित करके पूर्वोत्तर राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर कार्यशाला, 5 दिन, 15–19 नवंबर 1999, एजावल, 6 पूर्वोत्तर राज्यों–अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से कुल 19 भागीदार। सुश्री जयश्री जलाली इस कार्यशाला की संयोजिका थीं।

**जारी शोध अध्ययन**

डी पी ई पी के अंतर्गत जिला और उपजिला प्रबंधन संगठनों पर एक शोध अध्ययन शुरू किया गया है। इय अध्ययन के चारपक्षीय उद्देश्य हैं :

(अ) डी पी ई पी में प्ररिकल्पित ढांचे के अनुसार जिला और उप–जिला स्तर के प्रबंधन ढांचों की भूमिका और कार्यकलापों का अध्ययन;

(ब) डी पी ओ, प्रखंड संसाधन केंद्रों और संकुल संसाधन केंद्रों की परिकल्पित भूमिका और कार्यकलापों के सापेक्ष उनके कार्यकलापों का अध्ययन और विश्लेषण करना;

(स) दूसरे शैक्षिक और प्रशासनिक संस्थानों के साथ जिला और उप–जिला प्रबंधन ढांचों के बहुस्तरीय संबंधों का विश्लेषण करना और;

(द) उप–जिला स्तरीय संगठनों, जैसे–प्रखंड संसाधन केंद्रों और संकुल संसाधन केंद्रों और संकुल संसाधन केंद्रों की भावी भूमिका और कार्यप्रणाली के बारें में सुझाव देना।

यह अध्ययन अभी आरंभिक चरण में हैं। यह अध्ययन सघन क्षेत्र कार्य पर आधारित है। शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य बिहार और उच्च शैक्षिक राज्य केरल के एक–एक जिले को अध्ययन के लिए चुना गया है। डॉ. एस.एम.आई.ए. जैदी इसके परियोजना निदेशक हैं।

**प्रकाशित पुस्तक समीक्षाएं**

एजुकेशनल स्टेटस आफ मुस्लिम्स : प्राबलम्स, प्रास्पेक्ट्स एण्ड प्रीआरटीज, शेख रहीम मोंडल, *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन,* वर्ष 13, अंक 2, अप्रैल 1999

डिसेंट्रलाइजेशन आफ एजुकेशन : लीगल इसूज, के फोरेस्टाल और आर कायर, *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन,* वर्ष 13, अंक 3, जुलाई 1999

डिसेंट्रलाइजेशन आफ एजुकेशन : टीचर मैनेजमेंट, कैथी गेनर, *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन,* वर्ष 13, अंक 3, जुलाई 1999

एजुकेशनल परफार्मेस आफ शेड्यूल्ड कास्ट्स : रमैया किनजाराम, जेपा, वर्ष 13, अंक 4, अक्टूबर 1999

**प्रशिक्षण सामग्री**

सांस्थानिक स्तर पर योजना : अवधारणा और प्रक्रिया, डिप्लोमा और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सामग्री

**अंतर्राष्ट्रीय बैठक में प्रस्तुत आलेख**

कोरिया शैक्षिक विकास संस्थान, सियोल, कोरिया गणराज्य, में 16–18 अक्तूबर 1999 के दौरान शैक्षिक योजना और प्रबंधन पर संसाधन व्यक्तियों की के डी–यूनेस्को संयुक्त बैठक में भारत में शैक्षिक विकास पर आलेख प्रस्तुत किया।

**संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भागीदारी**

भुवनेश्वर में 29–30 अप्रैल 1999 के दौरान ए डब्ल्यू पी और बी तथा उड़ीसा के डी पी ई पी जिला विस्तार के लिए प्रासंगिक योजना के विकास पर आयोजित कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में सहभागिता

एन. एस. डी. ए. आर. टी., मसूरी द्वारा अगस्त के दौरान सी आई ई टी, एस सी ई आर टी, नई दिल्ली में ए डब्लयू पी और बी की तैयारी में प्रयुक्त प्रशिक्षण माहपूल के सुधार पर आयोजित कार्यशाला में में संसाधान व्यक्ति के रूप में भागीदारी (16-18 अगस्त 1999)

गांधी नगर में 22-24 सितंबर 1999 के दौरान जिला विस्तार के जिला योजना समूह के लिए डी पी ई पी राज्य परियोजना अधिकारी द्वारा आयोजित मानसदर्शन कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति

पटना, बिहार में 4-5 फरवरी 2000 के दौरान शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, डी पी ई पी और स्पीड, यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से सर्वशिक्षा अभियान पर आयोजित कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति

कोरिया शैक्षिक विकास संस्थान, सियोल, कोरिया गणराज्य में 18-22 अक्तूबर 1999 के दौरान शैक्षिक योजना और प्रबंधन पर संयुक्त संसाधन व्यक्तियों की केडी–यूनेस्को बैठक में संसाधान व्यक्ति के रुप में भाग लिया।

**परामर्शकारी सेवाएं और व्याख्यान**

यू. पी. डी. पी. ई. पी. जिलों के लिए पूर्व–मूल्यांकन मिशन, भारत सरकार का नेतृत्व, मिशन न लखनऊ और तीन डी पी ई पी जिलों का दौरा किया और लखनऊ में राज्य योजनागत भाग और जिला योजनाओं पर चर्चा की। भातर सरकार को रिपार्ट प्रस्तुत की मई। 25 मई–6 जून 1999

आई सी ई एम जयपुर में 2-3 दिसंबर 1999 के दौरान राजस्थान में डी पी ई पी जिलों के लिए एन एस डी ए आर टी, मसुरी द्वारा वार्षिक कार्यशाला के निर्माण पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति के रूप में व्याख्यान दिए।

सीमेट, पटना बिहार में 20-21 दिसंबर 1999 के दौरान बिहार के डी पी ई पी जिलों के लिए एन एस डी ए आर टी, मसूरी द्वारा वार्षिक कार्ययोजन के निर्माण पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति के रूप में व्याख्यान दिए।

सदस्य, अनुसंधान समिति, एस सी ई आर टी, दिल्ली

**विदेश दौरे**

सियोल में 18-22 अक्तूबर 1999 के दौरान शैक्षिक योजना और प्रशासन पर केडी–यूनेस्को संचुक्त संसाधन व्यक्तियों की बैठक में भाग लेने कोरिया शैक्षिक विकास संस्थान का दौरान किया।

**नीलम सूद**

**अनुसंधान**

हरियाणा राज्य के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का अध्ययन

**अंतर्राष्ट्रीय सम्मलनो में प्रस्तुत आलेख**

अरली चाइल्डहुड डवलपमेंट इन डवलपिंग वर्ल्ड : प्लानिंग फार ट्रवेंटी फस्ट सेंन्चूरी' तृतीया वार्विक प्रारंभिक वर्ष सम्मेलन में, वार्विक विश्वविद्यालय, इंग्लैण्ड, 12–16 अप्रैल 1999

**संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भागीदारी**

यूनिसेफ द्वारा आयोजित 'चाइल्ड इन्फो' कार्यशाला में भागीदारी, 25–27 अक्तूबर 1999

शैशवकालीन प्रारंभिक देखभाल और मुक्त व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा शिक्षा पर राष्ट्रीय खुला विद्यालय द्वारा आयोजित समीक्षा बैठकों में भाग लिया

**अन्य अकादमिक तथा व्यावसायिक गतिविधियां**

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिये शैशवकालीन शिक्षा और देखभाल केंद्र का आयोजन और प्रबंधन पर माड्यूल तैयार करने हेतु कार्य का समन्वयन

शैशवकालीन प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र के पांच भागों–अधिगम सामग्री, स्टाफ, सामुदायिक भागीदारी, प्रशासन निरीक्षण तथा वित्त और संयोजन का पुनरीक्षण तथा संपादन

जम्मू विश्वविद्यालय में एम. एस. सी. शिशु विकास पर परीक्षक

एन सी ई आर टी द्वारा डाइट के अध्यापक शिक्षकों के लिए आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति

सदस्य, निरीक्षण समिति, एम.एल.जी.पी.एस. यमुनानगर, हरियाणा

**जयश्री रॉय जलाली**

**पुस्तकें**

रिफलेक्शंस आन एलिमेंटरी एजुकेशन आन द नार्थ ईस्ट इंडिया (प्रेस में)

**अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी**

इक्कीसवीं शताब्दी में शैक्षिक संस्कृति : ज्ञान, अध्यापक तथा तकनीकी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भागीदारी, 29 –31, 1999 गुवाहाटी

शिक्षा एक अंतःस्थित निधि पर डेलर्स रिपोर्ट, (जनवरी) इंडिया हैबिटेंट सेंटर, नई दिल्ली

**अनुसंधान आलेख**

एजुकेशन आफ द ट्राइबल पापुलेशन आन द नार्थ ईस्ट इंडिया–बालिका शिक्षा के विशेष संदर्भ में

**पठन-सामग्री की तैयारी**

क्रियान्वयन रणनीति के विशेष संदर्भ में पूर्वोत्तर में प्रांरभिक शिक्षा पर कार्यशाला – पठन सामग्री की एक पुस्तक

**यजाली जोसेफिन**

**पाठ्यचर्या तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी**

विद्यालय प्राचार्यों के लिये संसाधन योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के शैक्षिक अधिकारियों के लिये संसाधन योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम

**पाठ्यक्रम प्रभारी**

डेपा कार्यक्रम के लिये शैक्षिक व्यवस्था प्रबंधन तथा संगोष्ठी भागीदारों के लिये पाठ्यक्रम प्रभारी

**माध्यमिक स्त्रोतों से पठन तथा प्रशिक्षण सामग्री**

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के शिक्षा अधिकारी तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रचार्यों के लिये पठन सामग्री की पहचान

**पठन तथा प्रशिक्षण सामग्री**

''स्कूल परफारमेंस इन अंडमान एण्ड निकोबार आइलैंड''–अनुसंधान आलेख

विद्यालय संसाधन आकलन के लिये अभ्यास कार्य का विकास

**अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठियो में भागीदारी**

शिक्षा संस्कृति और तकनीक पर गुवाहाटी में दिनांक 29–31 जनवरी के दौरान आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में "इम्पैक्ट आफ सैप्स आन इलिमेंटरी एजुकेशन इन नार्थ ईस्ट रीजन आफ इंडिया" विषय पर अनुसंधान आलेख प्रस्तुत किया

शिक्षा और विकास पर पांचवें आक्सफोर्ड अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिनांक 9–13 सितंबर 1999 के दौरान ''इंसिडेंस आफ पावर्टी आन गर्ल्स प्राइमरी एजुकेशन – ए केस स्टडी फ्रोम इंडिया'' विषय पर अनुसंधान आलेख प्रस्तुत किया

**पूर्ण अनुसंधान अध्ययन**

डी.पी.ई.पी अकादमिक संसाधन संस्थानों की प्रभाविकता – जिला बैतूल, मध्य प्रदेश का एक केस अध्ययन

**भागीदारी**

आकाशवाणी में दिनांक 14.1.2000 को भारत में शिक्षा विषय पर चर्चा में भाग लिया, पोर्टब्लेयर

**सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन**

सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण संयुक्त मंच (यू.के.एफ.आई.ई.टी.)

**बिजोय कुमार पांडा**

प्रकाशित पुस्तकें

नथिंग बट दि स्कूल–ह्वाट ए स्कूल हेड कैन डू! ए प्रॉपोजीशन फार डवलपिंग कांट्रीज, अनामिका प्रकाशन, नई दिल्ली 2000

**जारी अध्ययन**

नगरीक गरीबों की शिक्षा का अध्ययन : दिल्ली के मलीन बस्तियों का केस अध्ययन

**प्रकाशित आलेख**

आदिवाली क्षेत्रों में विद्यालयों के संचालन और कार्यकलाप, परिप्रेक्ष्य, वर्ष 7 अंक 1-2, अप्रैल–अगस्त 2000, नीपा

**प्रकाशित पुस्तक समीक्षाएं**

"डवलपिंग एजुकेशन" : हंटर फिलिप (सं.), जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रशन, वर्ष 13, अंक 4, अक्तूबर 1999

**सम्मेलन में भागीदारी**

इं. गा. रा. मु. विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में 26-28 सितंबर 1999 के दौरान सामग्री उत्पादन के लिए संरचनात्मक शोध प्रक्रिया पर सम्मेलन में सहभागिता

**रश्मि दीवान**

**प्रकाशित पुस्तकें**

डायनामिक स्कूल लीडरशीप, अनामिका प्रकाशक तथा वितरक, नई दिल्ली, 2000

**प्रकाशित आलेख**

लीडरशीप इंटरवेंन्शन्स फार स्कूल बेस्ड रिफोर्मस : टूवडर्स ए न्यू एजेंडा फार न्यू सैंचूरी, *न्यू फ्रंटियर्स इन एजुकेशन,* जिल्द XXX, अंक 1, जनवरी–मार्च 2000

मैनेजिंग स्कूल्स फ्राम विदिन : हाउ प्रैक्टिशनर्स कैन इंप्रूव आपान? *न्यू फ्रंटियर्स इन एजुकेशन,* जिल्द XXIX अंक 2, अप्रैल – जून 1999

संक्रमण से गुजरते विद्यालय, *परिप्रेक्ष्य,* नीपा, जिल्द V अंक 3, दिसंबर 1999

स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट : बिल्डिंग न्यू लीडरशिप रोल्स, *एजुकेशनल हेराल्ड,* शाह गोवर्धन लाल काबरा अध्यापक महाविद्यालय, जोधपुर, जिल्द 29, अंक 3–4, जुलाई – दिसंबर 1998

**सम्मेलनों में आलेखों की प्रस्तुति**

ट्रांसफार्मेशनल लीडरशिप फार अर्बन बेस्ड स्कूल्स : रिफ्लेक्शन आन एक्सपिरियेन्सेस आन इंडिया बी.ई.एम.ए.एस, छठा अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन अनुसंधान सम्मेलन, विद्वत समाज में शैक्षिक प्रबंधन की ओर अनुसंधान, नीति तथा व्यवहार, दिनांक 29–31 मार्च 2000 के दौरान, कैम्ब्रिज, यू.के.

**प्रशिक्षण कार्यक्रम**

प्राथमिक शिक्षा पर सामुदायिक भागीदारी और अधिकारिता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, 8–10 दिसंबर 1999

साक्षरता आकलन रणनीतियां और प्रक्रियाएं पर कार्यशाला, 29 फरवरी 3 मार्च 2000

**के.श्रीनिवास**

**संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओ में भागीदारी**

"इंटरनेट स्ट्रेटीजिस फार द नेक्स्ट मिलेनियम" विषय पर सेंटर फार इंफार्मेशन टैक्नोलाजी, टाटा रिसर्च इंस्टिट्यूट द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया, दिनांक 8–9 अक्तूबर 1999

**कौसर विज़ारत**

**आलेख**

कमला नहेरू कालेज, फगवाड़ा, पंजाब में दिनांक 17–18 दिसंबर 1999 के दौरान नारी अस्मिता का संघर्ष : साहित्य, समाज और राजनीति के संदर्भ में" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला में आलेख प्रस्तुत किया

परफारमेंस अप्रेसल एण्ड टीचर एकाउंटेविलिटी पर एक अध्ययन रिपोर्ट

इंटरनेशनलाइजेशन आफ हायर एजुकेशन : इशूज एण्ड पालिसी सजेशंस

**मंजू नरूला**

**प्रकाशन : पुस्तकें**

"टीचिंग एफिशियंसी इन हायर एजुकेशन", कामनवेल्थ प्रकाशन, जनवरी 2000

"लर्निंग : द ट्रेजर विदिन – इंप्लिकेशन फार एशिया", नीपा, नई दिल्ली 1999 (रिर्पोट तथा संपादन – सह लेखिका)

### अनुसंधान आलेख

'परफारमेन्स आफ यूनिवर्सिटी टीचर्स : ए स्टडी आफ जे.एन.यू. एंड जे.एम.आई. स्टाफ एंड एजुकेशनल डवलपमेंट इंटरनेशनल', अरावली पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय (प्रा) लिमिटेड, दिसंबर 1999

**कमलकान्त बिस्वाल**

### अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भागीदारी

नई दिल्ली, इंडिया हैबिटेट सेंटर में नीपा के विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक द्वारा शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। (सम्मेलन निदेशक – डॉ. आर गोविंद)। सम्मेलन के दो सत्रों की रिर्पोटिंग की।

दिनांक 25–26 मई के दौरान, नई दिल्ली यूनेस्को के साथ भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग के सहयोग से दक्षिण तथा पश्चिम एशिया क्षेत्रीय तकनीक सलाहकारी समूह द्वारा "दक्षिण तथा पश्चिम एशिया के लिए लिये वर्ष 2000 सबके लिये शिक्षा आकलन विषय पर प्रथम उप–क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

काठमाण्डू, नेपाल में अक्तूबर 1999 में नेपाल सरकार के सहयोग से दक्षिण तथा पश्चिम एशिया क्षेत्रीय तकनीक सलाहकारी समूह द्वारा 'दक्षिण तथा पश्चिम एशिया के लिये वर्ष 2000 सबके लिए शिक्षा–आकलन विषय पर' आयोजित द्वितीय उप–क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

बैंकाक, थाईलैंड में दिनांक 17–20 जनवरी 2000 के दौरान थाईलैंड सरकार के सहयोग से दक्षिण तथा पश्चिम एशिया क्षेत्रीय तकनीकी सलाहकारी समूह द्वारा "एशिया–प्रशांत सम्मेलन वर्ष 2000 : सबके लिये शिक्षा के आकलन विषय पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया।

दक्षिण तथा पश्चिम एशिया के लिये वर्ष 2000 सबके लिये शिक्षा–आकलन' विषय पर आयोजित सम्मेलन की रिपोर्ट तैयार करने का उत्तरदायित्व निभाया। डॉ. जे.बी.जी. तिलक, प्रधान रिपोर्टर रहे।

### अनुसंधान अध्ययन/केस अध्ययन

अग्रगामी पर एक केस अध्ययन यह एक गैर–सरकारी संगठन है जो उड़ीसा के रायगढ़ जिला के आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यह केस अध्ययन नीपा के विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक द्वारा तैयार किये गये सात अध्ययनों मे से एक है। यह यूनेस्को द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना 'मूलभूत शिक्षा में गैर–सरकारी संगठनो की भूमिका और योगदान' का भाग है। डा. गोविंदा इस परियोजना के प्रधान निरीक्षक हैं।

### अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की रिपोर्टें

दिनांक 25–26 मई 1999 के दौरान नई दिल्ली में यूनेस्को के सहयोग से आई.एन.सी. और दक्षिण–पश्चिम एशिया आर.टी.ए.जी. द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दक्षिण और पश्चिम एशिया

के लिये सबके लिये शिक्षा–आकलन वर्ष 2000 प्रथम उप–क्षेत्रीय कार्यशाला की रिपोर्ट तैयार की।

अक्तूबर 1999 में काठमाण्डू, नेपाल में नेपाल सरकार के सहयोग से दक्षिण और पश्चिम आर. टी.ए.जी. द्वारा दक्षिण और पश्चिम एशिया के लिये शिक्षा आकलन वर्ष 2000 पर द्वितीय उप–क्षेत्रीय कार्यशाला की रिपोर्ट तैयार की।

दिनांक 17–20 जनवरी 2000 के दौरान बैंकाक में थाइलैंड सरकार के सहयोग से बैंकाक के दक्षिण और पश्चिम एशिया आर.टी.ए.जी. द्वारा दक्षिण और पश्चिम एशिया के लिये सबके लिये शिक्षा आकलन – वर्ष 2000 पर तृतीय उप–क्षेत्रीय कार्यशाला की रिपोर्ट (डा. तिलक के साथ) तैयार की।

**प्रशिक्षण सामग्री/आलेख**

शिक्षा में जिला योजना पर व्यावहारिक अभ्यास का हल तैयार किया और व्यावहारिक अभ्यास को परिशोधित किया (डा. एन. वी. वर्गीज और डा. एन. के. मोहंती के साथ)। शिक्षा में जिला योजना पर एस. एस. ए. कार्यक्रम के लिये प्रशिक्षण सामग्री के इस सेट को प्रमुख प्रशिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा रहा है

नीपा में परिचर्चा के लिये 'डैमेजेस टू स्कूल एजुकेशन सेक्टर इन उड़ीसा ड्यू टू सुपर साइक्लोनिक स्ट्रोम " तैयार किया। इस आलेख को नीपा में आपदा प्रबंधन पर हुई बैठक में प्रस्तुत किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता श्री जे.सी.पंत, अध्यक्ष आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय समिति ने की

**प्रकाशित पुस्तकें/प्रासंगिक आलेख**

डा. (एन.वी.वर्गीज) के साथ स्कूल मैपिंग' विषय पर पुस्तक को अन्तिम रूप। अंतिम पाण्डुलिपि प्रेस में

"एजुकेशन, एक्सपिरियन्स एण्ड अर्निंग इन द सेगमेंटेड अर्बन लेबर मार्केट : एविडेन्स फ्राम दिल्ली, इंडिया" (प्रासंगिक लेख सं. 28) विषय पर प्रासंगिक लेख प्रकाशित, नीपा, नई दिल्ली, 1999

**एन. के. मोहन्ती**

**प्रशिक्षण सामग्री**

शिक्षा में जिला योजना पर हस्तपुस्तिका : एक व्यावहारिक अभ्यास (परिशोधित रूप)

**परामर्शकारी सेवाएं**

भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये अपर प्राथमिक और सर्व शिक्षा अभियान की नई योजनाओं हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को परामर्शकारी सेवाएं

**संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भागीदारी**

अगस्त 11–13, 1999 के दौरान, बेंगलौर में डी.पी.ई.पी. ब्यूरो, मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार, एडसिल तथा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से 'प्राथमिक शिक्षा' में लागत और अपव्यय 'विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'प्राथमिक स्तर पर सांस्थानिक लागत की संरचना और प्रतिरूप : दिल्ली का केस अध्ययन' विषय पर आलेख प्रस्तुत किया। यह कार्यक्रम नागरभाबी, बेंगलौर में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान में आयोजित हुआ।

भुवनेश्वर, उड़ीसा में, एस. सी. ई. आर. टी., उड़ीसा सरकार के सहयोग से शिक्षा में आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की

# परिशिष्ट I

## नीपा परिषद के सदस्य (31 मार्च 2000 के अनुसार)

**अध्यक्ष**

1. श्री मुरली मनोहर जोशी
   मानव संसाधन विकास मंत्री
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली

**उपाध्यक्ष**

2. श्री बी. पी. खण्डेलवाल
   निदेशक
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
   नई दिल्ली 110016

**पदेन सदस्य**

3. प्रो. हरि गौतम
   अध्यक्ष
   विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
   बहादुरशाह जफर मार्ग
   नई दिल्ली

4. श्री एम. के. काव
   शिक्षा सचिव
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शिक्षा विभाग
   शास्त्री भवन
   नई दिल्ली 110001

5. श्री पी. जी. मानकड
   सचिव
   वित्त मंत्रालय
   नार्थ ब्लाक
   नई दिल्ली, (या उनके प्रतिनिधि)

6. श्री बी. बी. टण्डन
   सचिव
   कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग
   नार्थ ब्लाक (या उनके प्रतिनिधि)
   नई दिल्ली

7. श्री एन. सी. सक्सेना
   सचिव
   योजना आयोग
   नई दिल्ली (या उनके प्रतिनिधि)

8. प्रो. जे. एस. राजपूत
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद
नई दिल्ली 110016

9. श्री देंगनुना
शिक्षा सचिव तथा आयुक्त
मिजोरम सरकार
सचिवालय परिसर
आईजोल – 796001

10. श्री निखिलेश दास
सचिव
विद्यालय शिक्षा
पश्चिम बंगाल सरकार
विकास भवन, छठा तल
साल्ट लेक
कोलकाता – 700091

11. श्री प्रेम प्रशान्त
शिक्षा सचिव तथा आयुक्त
हरियाणा सरकार
नया सचिवालय
कक्ष सं. 129/2
चंडीगढ़ – 160001

12. श्री आर. सी. कानाडे
प्रधान सचिव (विद्यालय शिक्षा)
महाराष्ट्र सरकार
मंत्रालय
मुंबई – 400032

13. श्रीमती एम. छाया रतन
शिक्षा सचिव (विद्यालय शिक्षा)
आंध्र प्रदेश सरकार
जे. ब्लाक, ए. पी. सचिवालय
हैदराबाद – 744101

14. सुश्री नूतन गुहा बिस्वास
शिक्षा आयुक्त तथा सचिव
अंडमान तथा निकोबार
प्रशासन
पोर्ट ब्लेयर – 744101

15. डा. जी. एन. तालुकदार
माध्यमिक शिक्षा निदेशक
असम सरकार
काहिलीपाड़ा
गुवाहाटी – 781019

16. श्री अनिल के. श्रीवास्तव
माध्यमिक शिक्षा निदेशक
बिहार सरकार
नया सचिवालय
पटना – 800015

17. श्री एस. सी. राय
माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक
शिक्षा निदेशक
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला – 171001

18. श्री बी. एल. आर्य
माध्यमिक शिक्षा निदेशक
राजस्थान सरकार
बीकानेर – 305001

19. श्री आर थिवामनी
विद्यालय शिक्षा निदेशक
तमिलनाडु सरकार
डी. पी. आई. परिसर
कालेज रोड, चेन्नई – 600006

20. श्री जी. पनेरसेलवम
शिक्षा निदेशक
पांडिचेरी सरकार
सरम, पी. एच. बी. भवन
पांडिचेरी – 605001

**विख्यात शिक्षाविद**

21. डा. एस. वी. गिरी
कुलपति
सत्य, साई विश्वविद्यालय
प्रशांतनिलायम – 515134
जिला अनंतपुर,
आंध्र प्रदेश

22. डा. उमा तुली
"अमरज्योति" सहायता न्यास
एन–192, ग्रेटर कैलाश –I
नई दिल्ली – 110048

23. प्रो. पी. एल. चतुर्वेदी
कुलपति
अजमेर विश्वविद्यालय
अजमेर (राजस्थान)

24. डॉ. एम. आई. खान
कुलपति
आगरा विश्वविद्यालय,
आगरा

25. डॉ. के. जी. रस्तोगी
भूतपूर्व आचार्य
एन. सी. ई. आर. टी.
ई–923, सरस्वती विहार,
दिल्ली – 110034

26. डॉ. एच. पी. दीक्षित
कुलपति
मुक्त विश्वविद्यालय रेड क्रास भवन,
शिवाजी नगर
भोपाल – 462016

**कार्यकारी समिति के सभी सदस्य**

27. श्री अभिमन्यु सिंह
संयुक्त सचिव (योजना)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

28. श्री संजय नारायण
वित्त सलाहकार
मा. सं. वि. मंत्रालय
शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

29. श्री. निखिलेश दास
शिक्षा सचिव
पश्चिम बंगाल सरकार
कोलकाता

30. सुश्री नजमा अख्तर
निदेशक
सीमेट, एलेनगंज,
इलाहाबाद – 211002

31. प्रो. सी. सुब्बाराव
अध्यक्ष
आंध्र प्रदेश उच्च शिक्षा राज्य परिषद
पोस्ट बाक्स न. 34, सैफाबाद
हैदराबाद – 580004

32. संयुक्त निदेशक
नीपा
नई दिल्ली

[redacted]

33. डॉ. जे. बी. जी. तिलक,
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
शैक्षिक वित्त एकक,
नीपा

33. डॉ. (श्रीमती) पी. मेनन,
अध्येता, प्रादेशिक प्रणाली एकक
नीपा

34. सुश्री जोसेफिन, सह–अध्येता
शैक्षिक प्रशासन एकक, नीपा

35. श्री पी. आर. आर. नायर
कुलसचिव
नीपा सचिव

## परिशिष्ट - II

## नीपा कार्यकारी समिति के सदस्य (31 मार्च 2000 के अनुसार)

1. प्रो. बी. पी. खण्डेलवाल, *अध्यक्ष*
   निदेशक
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
   प्रशासन संस्थान
   नई दिल्ली–110016

2. संयुक्त निदेशक
   नीपा
   नई दिल्ली–110016

3. श्री अभिमन्यु सिंह
   संयुक्त सचिव (योजना)
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शिक्षा विभाग, नई दिल्ली–110001

4. श्री संजय नारायण
   वित्त सलाहकार
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शिक्षा विभाग
   शास्त्री भवन
   नई दिल्ली–110001

5. श्री वी. पी. गर्ग
   संयुक्त सलाहकार (शिक्षा)
   योजना आयोग
   नई दिल्ली–110001

6. श्री निखिलेश दास
   शिक्षा सचिव
   पश्चिम बंगाल सरकार
   कोलकाता

7. सुश्री नजमा अख्तर
   निदेशक
   सीमेट, एलेनगंज
   इलाहाबाद--211002

8. प्रो. सी. सुब्बा राव
   अध्यक्ष
   आंध्र प्रदेश उच्च शिक्षा राज्य परिषद
   पोस्ट बाक्स न. 34, सैफाबाद
   हैदराबाद – 500004

9. डॉ. (श्रीमती) उमा तुली,
   प्रबंध निदेशक
   अमर ज्योति
   पुनर्वास तथा अनुसंधान केन्द्र
   कड़कड़डूमा, विकास मार्ग
   नई दिल्ली

10. डॉ. जे. बी. जी. तिलक
    वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
    शैक्षिक वित्त एकक

11. सुश्री वाई. जोसेफिन
    सह–अध्येता
    शैक्षिक प्रशासन एकक, नीपा

11. श्री पी. आर. आर. नायर
    कुलसचिव
    नीपा *सचिव*

परिशिष्ट III

## वित्त समिति के सदस्य (31 मार्च 2000 तक)

1. प्रो. बी. पी. खण्डेलवाल *अध्यक्ष*
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली–110016

2. संयुक्त निदेशक
नीपा
नई दिल्ली

3. श्री अभिमन्यु सिंह
संयुक्त सचिव (योजना)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली–110001

4. श्री संजय नारायण
वित्त सलाहकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली–110001

5. श्री आर. सी. कानाडे
सचिव (विद्यालय शिक्षा)
महाराष्ट्र सरकार
मंत्रालय
मुंबई–400032

6. डॉ. जे. बी. जी. तिलक
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
नीपा
नई दिल्ली

7. श्री पी. आर. आर. नायर
कुलसचिव
नीपा *सचिव*

## परिशिष्ट IV

# योजना और कार्यक्रम समिति के सदस्य (31 मार्च 2000 तक)

1. प्रो. बी. पी. खण्डेलवाल, *अध्यक्ष*
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली - 110016

2. श्री अभिमन्यु सिंह
संयुक्त सचिव(योजना)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली - 110001

3. डॉ. आर.पी. गांगुर्दे
अतिरिक्त सचिव
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली

4. श्री के के. बाक्सी
प्रधान सलाहकार (शिक्षा)
योजना आयोग
नई दिल्ली–110001

5. प्रो. ए. डब्ल्यू खान
इं. गां. रा. मु. विश्वविद्यालय
मैदानगढ़ी
नई दिल्ली

6. श्री सुधीर जी. मानकड
अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा)
गुजरात सरकार
सरदार पटेल भवन
गांधी नगर

7. श्री सी. बालाकृष्णन
शिक्षा सचिव
हि. प्र. सरकार
शिमला

8. श्री उपेन्द्र त्रिपाठी
जनशिक्षा – आयुक्त
कर्नाटक सरकार
नया पब्लिक कार्यालय
न्रूपाथुंगा रोड
बंगलौर - 560001

9. श्री अमृत प्रकाश
शिक्षा निदेशक
कर्नाटक सरकार
18 पार्क रोड,
लखनऊ

10. एच. एम. जोशी
कुलपति
सौराष्ट्र विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय रोड
राजकोट - 360005

11. प्रो. सुरेश्वर शर्मा
कुलपति
जबलपुर विश्वविद्यालय
जबलपुर

12. प्रो. कमल नरायण काबरा
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
आई. पी. इस्टेट
नई दिल्ली – 110002

13. प्रो. राम सिंह
सेवानिवृत्त डीन
विधि संकाय
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

14. प्रो. वी. एस. गौतम
प्रबंध अध्ययन विभाग
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
नई दिल्ली-110016

15. प्रो. रवीन्द्र नाथ पाल
अध्यक्ष, राजनीति विभाग
पंजाबी विश्वविद्यालय
पटियाला – 147001

16. डॉ. जी. डी. शर्मा
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
उच्च शिक्षा एकक
नीपा
नई दिल्ली - 110016

17. डॉ. एम. मुखोपाध्याय
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
शैक्षिक प्रशासन एकक
नीपा
नई दिल्ली - 110016

18. डॉ. आर. गोविंद
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक
नीपा
नई दिल्ली - 110016

19. डॉ. जे.बी.जी. तिलक
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
शैक्षिक वित्त एकक
नीपा
नई दिल्ली - 110016

20. डॉ. वाई. पी. अग्रवाल
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
संक्रियात्मक अनुसंधान और
प्रणाली प्रबंधन एकक
नीपा
नई दिल्ली - 110016

21. डॉ. के सुधा राव
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष,
शैक्षिक नीति एकक
नीपा
नई दिल्ली - 110016

22. (सुश्री) के. सुजाता
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष,
अंतर्राष्ट्रीय एकक
नीपा
नई दिल्ली - 110016

25. श्री पी. आर. आर. नायर *सचिव*
नीपा
नई दिल्ली - 110016

## परिशिष्ट V

# संकाय तथा प्रशासनिक स्टाफ़ (31 मार्च 2000 तक)

**निदेशक**

बी. पी. खण्डेलवाल

**शैक्षिक योजना एकक**

बी. पी. खण्डेलवाल, अध्यक्ष
एन. के. मोहंती, अनुसंधान और प्रशिक्षण सहयोगी

**शैक्षिक प्रशासन एकक**

एम. मुखोपाध्याय, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
वाई. जोसेफिन, सह–अध्येता
मंजू नरूला, अनुसंधान और प्रशिक्षण सहयोगी

**शैक्षिक वित्त एकक**

जे.बी.जी. तिलक, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
ए. एन. रेड्डी, अनुसंधान और प्रशिक्षण सहयोगी
एस. के. मलिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण सहयोगी (अध्ययन अवकाश पर)

**शैक्षिक नीति एकक**

के. सुधा राव, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष

**विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक**

आर. गोविंद, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
एस. मुखोपाध्याय, अध्येता
नलिनी जुनेजा, अध्येता
नीलम सूद, अध्येता
रश्मि दीवान, सह अध्येता
वी.पी.एस. राजू , अनुसंधान और प्रशिक्षण सहयोगी (अध्ययन अवकाश पर)

**उच्च शिक्षा एकक**

जी. डी. शर्मा, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
कौसर विजारत, अनुसंधान और प्रशिक्षण सहयोगी

**प्रादेशिक प्रणाली एकक**

प्रमिला मेनन, अध्येता
अरुण. सी. मेहता, अध्येता
एस. एम. आई. ए. जैदी, अध्येता
जे. जलाली, सह–अध्येता
कमलकान्त बिस्वाल, अनुसंधान और प्रशिक्षण सहयोगी

**अंतर्राष्ट्रीय एकक**

के. सुजाता, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
बी. के. पांडा, सह–अध्येता,

**संक्रियात्मक अनुसंधान और प्रणाली प्रबंधन एकक**

वाई. पी. अग्रवाल, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
सुनीता चुग, अनुसंधान और प्रशिक्षण सहयोगी

*संगणक केन्द्र*

के. श्रीनिवास, सिस्टम एनलिस्ट
एकता नाहर, प्रोग्रामर

**कुलसचिव**

पी. आर. आर. नायर

**पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र**

निर्मल मल्होत्रा, पुस्तकालयाध्यक्षा
एन.डी. कांडपाल, प्रलेखन अधिकारी
दीपक मकोल, व्यावसायिक सहायक
बी. डी. जोशी, व्यावसायिक सहायक

**प्रकाशन एकक**

एम. एम. अजवानी, उप प्रकाशन अधिकारी

**हिंदी कक्ष**

सुभाष शर्मा, हिंदी संपादक

**मानचित्रण कक्ष**

पी. एन. त्यागी, मानचित्रकार (संगणक अनुप्रयोग)

**प्रशासन और वित्त**

जी. एस. भारद्वाज, प्रशासनिक अधिकारी
एम. एल. शर्मा, अनुभाग अधिकारी
एस. आर. चौधरी, अनुभाग अधिकारी
पी. मणि, अनुभाग अधिकारी
आर. सी. शर्मा, अनुभाग अधिकारी

# परिशिष्ट VI
# वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

## राष्ट्रीय शैक्षिक योजना

**1.4.99 से 31.3.2000 तक**

| 1998-99 | [illegible] | 1999-2000 | |
|---|---|---|---|
| | अर्थशेष | | |
| 0.00 | हस्तगत रोकड़ | 0.00 | |
| 5,000.00 | अग्रदाय | 5,000.00 | |
| 19,454,805.10 | बैंक में रोकड़ | 12,208,744.69 | 12,213,744.69 |

## और प्रशासन संस्थान

### की प्राप्तियां और भुगतान लेखा

| 1998-99 | | भुगतान | 1999-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | **योजनेतर (व्यय)** | | |
| | | **अधिकारियों का वेतन** | | |
| 527,598.00 | | प्रशासन | 568,317.00 | |
| 167,466.00 | | वित्त तथा लेखा | 147,489.00 | |
| 3,798,410.00 | | अनुसंधान तथा प्रशिक्षण | 3,397,633.00 | |
| 393,329.00 | | पुस्तकालय तथा प्रलेखन | 322,380.00 | |
| 205,050.00 | 5,091,853.00 | प्रकाशन | 205,828.00 | 4,641,647.00 |
| | | **संस्थागत वेतन** | | |
| 1,679,503.00 | | प्रशासन | 2,884,137.00 | |
| 364,936.00 | | वित्त तथा लेखा | 420,220.00 | |
| 2,201,883.00 | | अनुसंधान तथा प्रशिक्षण | 2,007,998.00 | |
| 418,078.00 | | पुस्तकालय तथा प्रलेखन | 452,605.00 | |
| 159,955.00 | | प्रकाशन | 205,445.00 | |
| 235,145.00 | 5,059,500.00 | छात्रावास | 245,425.00 | 6,215,830.00 |
| | | **भत्ते तथा मानदेय** | | |
| 2,178,964.00 | | प्रशासन | 2,044,498.00 | |
| 427,152.00 | | वित्त तथा लेखा | 378,283.00 | |
| 3,319,239.00 | | अनुसंधान तथा प्रशिक्षण | 2,557,080.00 | |
| 431,848.00 | | पुस्तकालय तथा प्रलेखन | 435,362.00 | |
| 346,100.00 | | प्रकाशन | 296,268.00 | |
| 137,307.00 | 6,840,610.00 | छात्रावास | 155,332.00 | 5,866,823.00 |
| 278,142.00 | 278,142.00 | समयोपरि भत्ता | 273,450.00 | 273,450.00 |
| 392,800.00 | 392,800.00 | चिकित्सा व्यय अग्रिम | 182,000.00 | 182,000.00 |
| 792,213.00 | 792,213.00 | चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 620,324.00 | 620,324.00 |
| 191,933.00 | 191,933.00 | अवकाश यात्रा रियायत | 138,045.00 | 138,045.00 |
| 246,738.00 | 246,738.00 | तदर्थ बोनस | 227,591.00 | 227,591.00 |
| 1,497,843.00 | 1,497,843.00 | पी.एफ. पर ब्याज अंशदाता को भुगतान | 2,005,733.00 | 2,005,733.00 |
| 36,186.00 | 36,186.00 | अवकाश वेतन तथा पेंशन योगदान | 148,680.00 | 148,680.00 |
| 1,895,702.00 | 1,895,702.00 | पेंशन तथा उपदान | 3,290,336.00 | 3,290,336.00 |

[redacted] [redacted] [redacted]

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13,865,000.00 | | योजनेत्तर | 17,800,000.00 | |
| 10,500,000.00 | 24,365,000.00 | योजना | 30,000,000.00 | 47,800,000.00 |
| 1,487,208.00 | 1,487,208.00 | छात्रावास किराया | 2,019,095.00 | 2,019,095.00 |
| 1,428,197.00 | | निवेश पर ब्याज | 102,395.00 | |
| 411,392.00 | | पी. एफ. निवेश पर ब्याज | 103,110.00 | |
| 81,190.00 | | ब्याज वाली पेशगियों पर ब्याज | 57,371.00 | |
| 0.00 | | पी. एफ. खाते पर ब्याज | 6,335.02 | |
| 0.00 | 1,920,779.00 | बचत बैंक खाता पर ब्याज | 211,279.19 | 480,490.21 |

| 1998-99 | | [illegible] | 1999-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | **अकादमिक गतिविधियां** | | |
| 0.00 | | विज्ञापन प्रभार | 276,173.00 | |
| 61,310.00 | | मनोरंजन प्रभार | 9,363.00 | |
| 19,417.00 | | विविध आकस्मिक्ताएं | 14,309.00 | |
| 17,234.00 | | मुद्रण/जिल्द प्रभार | 1,912.00 | |
| 60,860.00 | | डाक व तार प्रभार | 70,283.00 | |
| 90,422.00 | | पैट्रोल, ऑयल तथा ल्यूब्रीकेंट प्रभार | 26,750.00 | |
| 83,813.00 | | स्टेशनरी/स्टोर मद | 50,386.00 | |
| 460,728.00 | | टेलीफोन प्रभार | 208,781.00 | |
| 71,989.00 | 865,773.10 | वृत्तिका/पुस्तक तथा परियोजना अनुदान | 17,000.00 | 674,957.00 |
| | | **यात्रा भत्ता** | | |
| 425,235.00 | 425,235.00 | संकाय/कर्मचारी वर्ग तथा सदस्य | 28,416.00 | 28,416.00 |
| 23,609.00 | 23,609.00 | संसाधन व्यक्तियों को मानदेय | 2,275.00 | 2,275.00 |
| | | **अनुसंधान अध्ययन** | | |
| 22,094.00 | 22,094.00 | मुद्रण प्रभार | 19,729.00 | 19,729.00 |
| | | **अन्य प्रभार (आवर्ती)** | | |
| 40,650.00 | | लेखा शुल्क | 95,680.00 | |
| 910.00 | | कूलियेज/कार्टेज/कस्टम इत्यादि | 1,800.00 | |
| 5,384.00 | | बागवानी प्रभार | 0.00 | |
| 84,922.00 | | बीमा | 84,633.00 | |
| 44,562.00 | | वर्दी | 61,749.00 | |
| 64,000.00 | | कानूनी प्रभार | 193,150.00 | |
| 115,782.00 | | गाड़ियों का रख–रखाव | 14,844.00 | |
| 183,787.00 | | उपकरणों का रख–रखाव | 62,795.00 | |
| 13,694.00 | | फर्नीचर व साज–समान का रख–रखाव | 1,318.00 | |
| 18,751.00 | | संस्था भवन का रख–रखाव (सिविल) | 0.00 | |
| 1,980.00 | | संस्था भवन का रख–रखाव (इलैक्ट्र.) | 0.00 | |
| 431,679.00 | | विविध भुगतान | 161,026.00 | |
| 17,442.00 | | समाचार पत्र प्रभार | 7,112.00 | |
| 2,496.00 | | किराया, दर तथा कर | 0.00 | |
| 155,339.00 | 1,181,378.00 | पानी तथा बिजली प्रभार | 44,128.00 | 728,235.00 |

| 1998-99 | | प्राप्तियां | 1999-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | **प्रकाशनों की बिक्री** | | |
| 15,282.00 | 15,282.00 | रायल्टी | 30,039.50 | 30,039.50 |
| 368,000.00 | 368,000.00 | चिकित्सा व्यय की वापसी | 109,450.00 | 109,450.00 |
| | | **विविध प्राप्तियां** | | |
| 326,000.00 | | अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री | 128,565.00 | |
| 68,325.00 | | लाइसेंस शुल्क | 83,024.00 | |
| 6,129.00 | | जल प्रभार | 6,655.00 | |
| 0.00 | | कार्यक्रम प्राप्तियां | 2,839,997.00 | |
| 6,836,277.04 | 72,36,731.04 | विविध प्राप्तियां | 232,044.00 | 3,290,285.00 |
| 0.00 | 0.00 | यथोनुपात पेशंन लाभ | 2,659.00 | 2,659.00 |
| 112,898.00 | 112,898.00 | अवकाश वेतन पेंशन अंशदान | 162,110.00 | 162,110.00 |
| 93,186.00 | 93,186.00 | पेंशन (वसूली) | 7,937.00 | 7,937.00 |
| | | **अन्य विविध प्राप्तियां** | | |
| 17,500.00 | 17,500.00 | प्रतिभूति प्राप्तियां | 11,000.00 | 11,000.00 |
| | | **वसूली योग्य पेशगियां** | | |
| 90,370.00 | | त्यौहार पेशगी | 111,300.00 | |
| 8,840.00 | | कार पेशगी | 79,600.00 | |
| 44,608.00 | | स्कूटर पेशगी | 60,620.00 | |
| 4,950.00 | | साइकिल पेशगी | 4,020.00 | |
| 0.00 | | पंखा पेशगी | 900.00 | |
| 111,950.00 | | भवन निर्माण पेशगी | 122,300.00 | |
| 31,180.00 | | कंप्यूटर पेशगी | 7,200.00 | |
| 0.00 | 291,898.00 | चक्रवात पेशगी | 0.00 | 385,940.00 |
| 3,959,410.00 | 3,959,410.00 | विविध पेशगियां | 875.00 | 875.00 |
| **15,502,892.04** | | **कुल प्राप्तियां (योजनेत्तर)** | **6,499,880.71** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **अन्य विविध भुगतान** | | |
| 0.00 | 0.00 | प्रतिभूति वापसी | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | **वसूली योग्य पेशगियां** | | |
| 117,000.00 | | पंखा पेशगी | 125,250.00 | |
| 0.00 | | कार पेशगी | 260,420.00 | |
| 191,109.00 | | स्कूटर पेशगी | 90,000.00 | |
| 7,500.00 | | साइकिल पेशगी | 4,920.00 | |
| 0.00 | | पंखा पेशगी | 2,000.00 | |
| 278,650.00 | | भवन निर्माण पेशगी | 306,000.00 | |
| 0.00 | | कंप्यूटर पेशगी | 0.00 | |
| 0.00 | | चक्रवात पेशगी | 7,500.00 | 796,090.00 |
| 4,066,445.00 | 4,066,445.00 | विविध पेशगियां | 0.00 | 0.00 |
| **29,502,313.10** | | **कुल व्यय (योजनेत्तर)** | **24,291,054.00** | |
| | | **योजना (व्यय)** | | |
| | | **अधिकारियों का वेतन** | | |
| 172,400.00 | 172,400.00 | अनुसंधान तथा प्रशिक्षण | 185,790.00 | 185,790.00 |
| | | **संस्थागत वेतन** | | |
| 134,566.00 | | प्रशासन | 121,250.00 | |
| 100,721.00 | | वित्त तथा लेखा | 82,800.00 | |
| 311,554.00 | | अनुसंधान तथा प्रशिक्षण | 681,292.00 | |
| 29,790.00 | 576,631.00 | प्रकाशन | 66,300.00 | 951,642.00 |
| | | **भत्ते तथा मानदेय** | | |
| 1,210,281.00 | | प्रशासन | 62,669.00 | |
| 35,579.00 | | वित्त तथा लेखा | 34,400.00 | |
| 471,306.00 | | अनुसंधान तथा प्रशिक्षण | 446,073.00 | |
| 112,050.00 | 1,829,216.00 | प्रकाशन | 48,022.00 | 591,164.00 |
| 6,525.00 | 6,525.00 | समयोपरि भत्ता | 4,238.00 | 4,238.00 |
| 544.00 | 544.00 | चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 4,418.00 | 4,418.00 |
| 24,190.00 | 24,190.00 | तदर्थ बोनस | 26,609.00 | 26,609.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | आई. डी. ई. पी. ए. कार्यक्रम | | |
| 6,782,875.00 | 6,782,875.00 | अनुदान | 3,452,063.00 | 3,452,063.00 |
| | | डी. आई. एस. ई./ई. एम. आई. एस. की स्थापना और संचालन (डा. अग्रवाल) | | |
| 1,820,045.00 | 1,820,045.00 | अनुदान | 1,129,000.00 | 1,129,000.00 |
| | | डाइट के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम (मेनन) | | |
| 143,664.00 | 143,664.00 | अनुदान | 127,122.00 | 127,122.00 |
| | | डी. पी. ई. पी. योजना और प्रबंधन में क्षमता निर्माण (एन. वी. वर्गीज) | | |
| 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | अनुदान | 3,867,000.00 | 3,867,000.00 |

| 1998-99 | | | 1999-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | **अकादमिक गतिविधियां** | | |
| 0.00 | | विज्ञापन प्रभार | 158,320.00 | |
| 111,859.10 | | मनोरंजन प्रभार | 276,032.00 | |
| 135,326.00 | | विविध आकस्मिकताए | 402,822.00 | |
| 72,151.00 | | मुद्रण/जिल्द प्रभार | 310,845.50 | |
| 140,522.00 | | डाक व तार प्रभार | 330,339.00 | |
| 113,760.00 | | पैट्रोल, आयल तथा ल्यूब्रीकैंट प्रभार | 204,942.00 | |
| 824,868.00 | | स्टेशनरी/स्टोर प्रभार | 1,049,978.00 | |
| 606,723.25 | | टेलीफोन प्रभार | 677,235.00 | |
| 108,603.00 | | वृत्तिका, पुस्तक तथा परियोजना अनुदान | 225,857.00 | |
| 1,062,097.00 | 3,175,909.35 | पत्रिकाएं | 1,377,243.00 | 5,013,613.50 |
| | | **यात्रा भत्ते** | | |
| 245,476.00 | 245,476.00 | संकाय तथा कर्मचारी वर्ग को यात्रा भत्ता | 609,982.00 | 609,982.00 |
| 233,723.00 | 233,723.00 | भागीदारों का यात्रा/दैनिक भत्ता | 609,128.00 | 609,128.00 |
| 46,270.00 | 46,270.00 | संसाधन व्यक्तियों को मानदेय | 390,248.00 | 390,248.00 |
| 247,245.00 | 247,245.00 | प्रकाशन (प्रकाशित) | 259,543.00 | 259,543.00 |
| | | **अन्य प्रभार (अ) आवर्ती** | | |
| 3,480.00 | | कूलियेज/कार्टेज/कस्टम इत्यादि | 10,473.00 | |
| 8,447.00 | | बागवानी प्रभार | 23,750.00 | |
| 108,336.00 | | गाड़ियों का रख–रखाव | 159,161.00 | |
| 280,493.00 | | उपकरणों का रख–रखाव | 299,435.00 | |
| 19,591.00 | | फर्नीचर व साज–सामान का रख=रखाव | 85,707.00 | |
| 1,265,968.00 | | संस्था भवन का रख–रखाव (सिविल) | 2,142,512.00 | |
| 1,729,035.00 | | संस्था भवन का रख–रखाव (इलैक्ट्र.) | 1,029,113.00 | |
| 15,412.00 | | समाचार पत्र प्रभार | 43,665.00 | |
| 213,406.00 | | किराया, दर/कर | 213,405.00 | |
| 295,292.00 | | पानी तथा बिजली प्रभार | 2,004,110.00 | |
| 461,651.00 | 4,401,111.00 | विविध पेशगियां | 852,536.00 | 6,863,867.00 |

| 1998-99 | | प्राप्तियां | 1999-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | ए. डी. बी. श्रीलंका | | |
| 4,556,583.00 | 4,556,583.00 | अनुदान | | |
| | | कालेज प्रचार्यों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम (वि. अ. आयोग कार्यक्रम) | | |
| 685,340.00 | 685,340.00 | अनुदान | 602,894.00 | 602,894.00 |
| 150,000.00 | 150,000.00 | कंप्यूटर अनुप्रयोग कार्यक्रम (वि. अ. आयोग) | | |
| | | डाइट की तकनीकी और आधारभूत क्षमता का मूल्यांकन (डा. आर. गोविन्दा) | | |
| 1,634,000.00 | 1,634,000.00 | अनुदान | 0.00 | 0.00 |

| 1998-99 | | भुगतान | 1999-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | **गैर- आवर्ती** | | |
| 464,404.00 | | फर्नीचर व साज–समान | 1,045,350.00 | |
| 5,294,452.00 | 5,758,856.00 | अन्य कार्यालय उपकरण | 2,826,743.00 | 3,872,093.00 |
| 514,164.00 | 514,164.00 | पुस्तकालय की पुस्तकें | 371,974.00 | 371,974.00 |
| | | **अग्रिम भुगतान** | | |
| 17,000.00 | | भवन का निर्माण (सिविल) | 1,709,100.00 | |
| 261,404.00 | 278,404.00 | भवन का निर्माण (इलैक्ट्र) | 1,493,024.00 | 3,202,124.00 |
| **17,510,664.35** | | **कुल (योजना) व्यय** | **22,956,433.50** | |
| | | **संस्थान के अनुसंधान अध्ययन** | | |
| | | **शिक्षा पर द्वितीय अखिल भारतीय सर्वेक्षण** | | |
| 223,913.00 | | वेतन/मानदेय | 327,422.00 | |
| 64,957.00 | | संसाधन व्यक्तियों की यात्रा/दैनिक भत्ता | 55,067.00 | |
| 69,626.00 | | स्टाफ को यात्रा दैनिक/भत्ता | 1,978.00 | |
| 71,834.00 | 730,330.00 | आकस्मिकताएं | 55,254.00 | 439,721.00 |
| | | **मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी** | | |
| 15,124.00 | | वेतन | 66,962.00 | |
| 1,750.00 | 16,874.00 | आकस्मिकताएं | 3,845.00 | 70,807.00 |
| | | **भारत में महिला अध्ययन केंद्रो की योजना और प्रबंधन** | | |
| 9,326.00 | 9,326.00 | वेतन | 80,599.00 | 80,599.00 |
| | | **भारत में विद्यालयी शिक्षा** | | |
| | | **(डा. गोविंदा तथा रश्मि दीवान)** | | |
| 1,157.00 | 1,157.00 | वेतन | 8,773.00 | 8,773.00 |
| | | **नगरीय गरीबों की शिक्षा के एक केस** | | |
| | | **अध्ययन डा. सुश्री/के. सुजाता** | | |
| | | व्यय | 1,600.00 | 1,600.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | आई. टी. डी. ए. पडेरू के सभी मंडलों में विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार के लिए समवर्ती मूल्यांकन (यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित) डा. सुजाता | | |
| 531,200.00 | 531,200.00 | अनुदान | 0.00 | 0.00 |
| | | आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना का राष्ट्रीय मूल्यांकन (डा. आर. गोविन्दा) | | |
| 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | अनूदान | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 |

| 1998-99 | | | 1999-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रतिरूप तथा उच्च | | |
| Nil | Nil | शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण (डा. जी. डी. शर्मा) | | |
| | | वेतन | 40,866.00 | |
| | | विविध आकस्मिक्ताएं | 57,489.00 | 98,355.00 |
| | | विद्यालयी शिक्षा का प्रबंधन | | |
| 59,048.00 | 59,048.00 | शिक्षा पर गृह अनुभवों का प्रतिरूप तथा विधि | | |
| | | वेतन | 32,923.00 | |
| | | विविध व्यय | 2,549.00 | 35,472.00 |
| | | नवयुग विद्यालय पर सूक्ष्म अध्ययन | | |
| | | वेतन | 19,431.00 | |
| | | विविध व्यय | 2,936.00 | 22,367.00 |
| | | उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आस्वासन | | |
| | | व्यय | 101,457.00 | 101,457.00 |
| 36,147.00 | 36,147.00 | अवस्नातक स्तर पर व्यावसायिक | | |
| | | शिक्षा सहायता योजना | | |
| 45,000.00 | 45,000.00 | व्यय | 12,536.00 | 12,536.00 |
| **607,687.00** | | **कुल अनुसंधान अध्ययन** | **871,687.00** | |
| **18,118,351.35** | | **कुल (योजना) व्यय** | **25,402,227.50** | |

| 1998-99 | | विवरण | 1999-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | भारत में अपर प्राथमिक विद्यालयों का अध्ययन (सबके लिये शिक्षा का सार्वजनीकरण) विश्व बैंक द्वारा प्रयोजित (डा. एन. वी. वर्गीज़) | | |
| 630,000.00 | 630,000.00 | अनुदान | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | भारत में बेसिक शिक्षा में गैर=सरकारी संगठनों का योगदान (क.सं. 860.030.8) | | |
| 211,210.00 | 211,210.00 | अनुदान | 0.00 | 0.00 |
| | | अधिगम पर एशिया क्षेत्र सम्मेलन (क.सं. 860.030.8) | | |
| 126,690.00 | 126,690.00 | अनुदान | 563,646.50 | 563,646.50 |

| 1998-99 | | भुगतान | 1999-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | **प्रायोजित कार्यक्रम/अध्ययन** | | |
| | | **आई. डी. ई. पी. ए. कार्यक्रम** | | |
| 52,067.00 | | वेतन | 327,783.00 | |
| 3,908,106.00 | | कार्यक्रम व्यय | 1,665,768.00 | |
| 346,689.00 | | भागीदारों को सीधा भुगतान | 446,461.00 | |
| 1,103,624.00 | | भोजन तथा आवास | 1,979,461.00 | |
| 59,222.00 | | स्टेशनरी | 79,092.00 | |
| 408,485.00 | | आकस्मिक्ताएं | 309,119.00 | |
| 0.00 | 5,878,193.00 | पूंजीगत मद | 97,250.00 | 4,904,934.00 |
| 88,360.00 | 88,360.00 | पंचायती राज | | |
| 14,284.00 | 14,284.00 | बेस लाइन (केरल) | | |
| 9,839.00 | 9,839.00 | बेस लाइन (केरल) | | |
| | | **डी. आई. एस. ई/ई. एम. आई. एस. की स्थापना तथा संचालन (डा. अग्रवाल)** | | |
| 253,294.00 | | वेतन | 360,281.00 | |
| 60,437.00 | | यात्रा/दैनिक भत्ता | 70,200.00 | |
| 180,080.00 | | कंप्यूटर (पूंजीगंत मद) | 58,885.00 | |
| 677,986.00 | | स्टेशनरी | 63,115.00 | |
| 290,078.00 | 1,461,875.00 | आकस्मिकताएं | 94,514.00 | 646,995.00 |
| | | **डाइट के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (मेनन)** | | |
| 77,122.00 | 77,122.00 | व्यय | 176,195.00 | 176,195.00 |
| | | **डी. पी. ई. पी. योजना और प्रबंधन में क्षमता निर्माण** | | |
| 542,757.00 | | वेतन | 1,271,290.00 | |
| 302,725.00 | | स्टाफ को यात्रा/दैनिक भत्ता | 235,880.00 | |
| 0.00 | | भागीदारों को यात्रा/दैनिक भत्ता | 165,805.00 | |
| 509,436.00 | | कार्यक्रम व्यय | 522,000.00 | |
| 936,800.00 | | प्रशिक्षण सामग्री | 20,000.00 | |
| 0.00 | | स्टेशनरी | 115,300.00 | |
| 328,440.00 | 2,620,158.00 | आकस्मिकताएं | 119,300.00 | 2,449,575.00 |

| 1998-99 | | प्राप्तिया | 1999-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | विकास प्रक्रिया के लिए अवस्नातकों की भूमिका और योगदान को सुदृढ़ बनाने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण प्रश्नावली (क.स. 840.858.8) | | |
| 63,260.00 | 63,260.00 | अनुदान | 0.00 | 0.00 |
| | | सभी के लिए शिक्षा मूल्यांकन (पी) मा. सं. वि. मंत्रालय (डा. गोविन्दा) | | |
| | | अनुदान | 1,726,450.00 | 1,726,450.00 |
| | | सं. रा. सामान आंकड़ा आधार के लिये विकास संकेतक (यूनेस्को) (क.सं. 860.116.9) (डा. ए. सी. मेहता) | | |
| | | अनुदान | 68,991.00 | 68,991.00 |

| 1998-99 | | ब्यौरा | 1999-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| 112,582.00 | 112,582.00 | **सामाजिक सुरक्षा कवच योजना** | | |
| 71,790,83.00 | 71.790.83.00 | **ए. डी. घी. श्रीलंका** | | |
| | | **पुस्तकाध्यक्षों के लिये डाइट कार्यक्रम (सुश्री मल्होत्रा)** | | |
| 33,642.00 | 33,642.00 | व्यय | 9,414.00 | 9,414.00 |
| 57,142.00 | 57,142.00 | | | |
| | | **विद्यालय प्राचार्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (वि. अ. आयोग)** | | |
| 802,528.00 | 802,528.00 | व्यय | 399,986.00 | 399,986.00 |
| 47,057.00 | 47,057.00 | | | |
| | | **अधिगम प्राप्ति अध्ययन (दिल्ली) (यूनीसेफ) (डॉ. वाई. पी. अग्रवाल)** | | |
| 86,777.00 | | वेतन | 24,499.00 | |
| 50,540.00 | 137,317.00 | विविध आकस्मिक्ताएं | 7,274.00 | 31,773.00 |
| 121,649.00 | 121,649.00 | **प्राथमिक शिक्षा आकलन तथा समीक्षा** | | |
| 2,648.00 | 2,648.00 | **आई. आई. ई. पी.** | | |
| | | **डाइट की तकनीकी और आधारभूत क्षमता का मूल्यांकन (डॉ. आर. गोविन्द)** | | |
| 75,626.00 | | वेतन | 255,597.00 | |
| 97,936.00 | | ससाधन व्यक्तियों का मानदेय | 183,632.00 | |
| 75,560.00 | | स्टाफ को यात्रा/दैनिक भत्ता | 77,793.00 | |
| 1,379,230.00 | | कार्यक्रम व्यय | 300,000.00 | |
| 81,029.00 | 1,709,381.00 | आकस्मिक्ताएं | 4,597.00 | 821,619.00 |
| | | **आई. टी. डी. ए. पडेरू के सभी मंडलों में विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार के लिए समवत्ती मूल्यांकन (यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित) डा. सुजाता** | | |
| 127,058.00 | | वेतन | 32,370.00 | |
| 72,357.00 | | यात्रा दैनिक भत्ता | 1,166.00 | |
| 88,288.00 | 287,703.00 | आकस्मिकताएं | 2,500.00 | 36,036.00 |
| | | **विद्यालय स्तरीय शिक्षा में प्रोत्साहनों की प्रभाविकता (डॉ. के सुजाता)** | | |
| | | व्यय | 28,867.00 | 28,867.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | बंगला देश के उच्चशिक्षा अधिकारियो से संबंधित कार्यक्रम तथा यात्रा व्यय (यूनेस्को-ढाका) (क.सं. 865.273.9) | | |
| | | अनुदान | 496,225.00 | 496,225.00 |
| 84,484.00 | 84,484.00 | | | |
| 13,183.00 | 13,183.00 | | | |
| | | उच्च शिक्षा में मानवाधिकार पर अध्ययन (मा. सं. वि. मंत्रालय द्वारा प्रायोजित) | | |
| | | अनुदान | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | | क्रियान्वयन रणनीति पर बल देते हुये सबके लिये शिक्षा के सार्वजनीकरण पर पूर्वोत्तर में कार्यशाला (मिजोरम) (आइजोल) (15-11-99 से 19-11-99) सुश्री जलाली | | |
| | | अनुदान | 146,000.00 | 146,000.00 |

| 1998-99 | | भुगतान | 1999-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | **आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना का राष्ट्रीय मूल्यांकन (डॉ. आर. गोविंद)** | | |
| 71,857.00 | | वेतन | 353,769.00 | |
| 67,915.00 | | भागीदारों का यात्रा/दैनिक भत्ता | 615,604.00 | |
| 183,709.00 | | कार्यक्रम व्यय | 1,500,000.00 | |
| 39,611.00 | | स्टाफ का यात्रा/दैनिक भत्ता | 309,426.00 | |
| 7,125,000.00 | | विभिन्न राज्यों/संस्थानों को अनुदान | 8,168,132.00 | |
| 56,795.00 | 7,544,887.00 | आकस्मिक्ताएं | 81,874.0 | 11,028,805.00 |
| | | **भारत में अपर प्राथमिक विद्यालयों का अध्ययन (सबके लिये शिक्षा का सार्वजनीकरण) विश्व बैंक द्वारा प्रयोजित (डा. एन. वी. वर्गीज़)** | | |
| 132,163.00 | | वेतन | 61,703.00 | |
| 164,760.00 | 296,923.00 | आकस्मिकताए | 4,290.00 | 65,993.00 |
| | | **भारत में बेसिक शिक्षा में गैर-सरकारी संगठनों का योगदान (क.सं. 860.030.8)** | | |
| 27,000.00 | | वेतन | 46,008.00 | |
| 11,000.00 | | यात्रा/दैनिक भत्ता | 3,337.00 | |
| 4,160.00 | 42,160.00 | आकस्मिकताएं | 34,427.00 | 83,772.00 |
| | | **अधिगम पर एशिया क्षेत्र सम्मेलन (क.सं. 860.031.8)** | | |
| 686,452.00 | 686,452.00 | कार्यक्रम व्यय | 3,884.50 | 3,884.50 |
| | | **विकास प्रक्रिया के लिए अवस्नातको की भूमिका और योगदान को सुदृढ़ बनाने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण प्रश्नावली (क.सं. 840.858.8)** | | |
| 21,100.00 | 21,100.00 | व्यय | 42,160.00 | 42,160.00 |
| | | **सभी के लिए शिक्षा मूल्यांकन (पी) मा. सं. वि. मंत्रालय (डा. गोविन्दा)** | | |
| 19,457.00 | | वेतन | 273,193.00 | |
| 19,439.00 | 38,896.00 | आकस्मिकताएं | 550,405.00 | 823,598.00 |

| 1998-99 | प्राप्तियां | 1999-2000 | |
|---|---|---|---|
| | अपर प्राथमिक शिक्षा पर कार्यशाला | | |
| | डा. के. सुधा राव | | |
| | अनुदान | 471,500.00 | 471,500.00 |
| 29,832,534.00 | कुल प्राप्तियां प्रायोजित परियोजना | 30,550,891.50 | |

| 1998-99 | | | 1999-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | सं. रा. समान आंकड़ा आधार के लिये विकास संकेतक (यूनेस्को) (क.सं. 860.116.9) (डा. ए. सी. मेहता) | | |
| | | व्यय | 68,991.00 | 68,991.00 |
| | | बंगला देश के उच्च शिक्षा अधिकारियों से संबंधित कार्यक्रम तथा यात्रा व्यय (यूनेस्को-ढाका) (क.सं. 865.273.9) | | |
| | | कार्यक्रम व्यय | 220,194.00 | |
| | | सांस्कृतिक व्यय | 55,136.00 | |
| | | विविध आकस्मिकताएं | 28,500.00 | 330,830.00 |
| 56,321.00 | 56,321.00 | | | |
| | | प्राथमिक शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी तथा शक्तिकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (8–10/12/99) (यूरोपीय आयोग) | | |
| | | व्यय | 118,630.00 | 118,630.00 |
| | | सर्व शिक्षा अभियान-परियोजना | | |
| | | व्यय | 138,784.00 | 138,784.00 |
| | | उच्च शिक्षा में मानवाधिकार पर अध्ययन (मा. सं. वि. मंत्रालय द्वारा प्रायोजित) | | |
| | | वेतन | 2,576.00 | |
| | | स्टेशनरी प्रभार | 1,200.00 | 3,776.00 |
| | | क्रियान्वयन रणनीति पर बल देते हुये सबके लिये शिक्षा के सार्वजनीकरण पर उत्तर पूर्व में कार्यशाला(मिजोरम) (आइजोल) (15-11-99 से 19-11-99) सुश्री जलाली | | |
| | | व्यय | 146,000.00 | 146,000.00 |
| **29,327,302.00** | | कुल प्राप्तियां प्रायोजित परियोजना | **22,333,617.50** | |

| 1998-99 | [illegible] | 1999-2000 |
|---|---|---|
| | **प्रेषित धन** | |
| 1,076,473.00 | आयकर (वेतन) | 1,294,849.00 |
| 4,680,408.00 | भविष्यनिधि अंशदाता अग्रिम स्टाफ की वसूली | 5,836,854.00 |
| 133,750.00 | पी. एफ. अंशदाता तथा प्रतिनियोक्ता से वसूली | 85,500.00 |
| 48,420.00 | भवन निर्माण पेशगी (प्रतिनियुक्ता) | 48,420.00 |
| 155,400.00 | पे रोल बचत योजना | 155,400.00 |
| 91,760.00 | सामूहिक बचत लिंक बीमा | 90,500.00 |
| 271,552.00 | स्टाफ का जीवन बीमा | 298,696.00 |
| 463,242.00 | सोसायटी वसूली | 559,656.00 |
| 4,822.80 | सी. जी. ई. जी. आई. एस. (प्रतिनियुक्ता) | 5,517.10 |
| 3,600.00 | कंप्यूटर अग्रिम (प्रतिनियुक्ता) | 3,600.00 |
| 20,295.00 | आयकर | 36,839.00 |
| 0.00 | प्रतिनियोक्ता से संबंधित यूनियन फण्ड | 8,800.00 |
| 0.00 | प्रतिनियोक्ता से संबंधित सोसयती वसूली | 3,674.00 |
| **96,109,953.94** | **महायोग** | **105,492,822.00** |

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का अपेक्षित प्रयोजनों पर उपयोग किया गया है और निर्धारित शर्तों का पूरी तरह पालन किया गया हैं।

ह/–
(एस. आर. चौधरी)
अनुभाग अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

| 1998-99 | | भुगतान | 1999-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | **प्रेषित धन** | | |
| 1,076,473.00 | | आयकर (वेतन) | | 1,294,849.00 |
| 4,680,408.00 | | भविष्य निधि अंशदाता तथा स्टाफ की वसूली | | 5,836,854.00 |
| 133,750.00 | | भवन निर्माण पेशगी (प्रतिनियुक्त) | | 85,500.00 |
| 48,420.00 | | विभाग का भवन निर्माण पेशगी (प्रतिनियुक्त) | | 48,420.00 |
| 155,400.00 | | पे रोल बचत योजना | | 155,400.00 |
| 90,280.00 | | सामूहिक बचत लिंक बीमा | | 90,340.00 |
| 271,552.00 | | स्टाफ का जीवन बीमा | | 298,696.00 |
| 463,242.00 | | सोसायटी वसूली | | 559,656.00 |
| 4,822.80 | | सी. जी. ई. जी. आई. एस. (प्रतिनियुक्त) | | 5,517.10 |
| 3,600.00 | | कंप्यूटर अग्रिम (प्रतिनियुक्त) | | 3,600.00 |
| 20,295.00 | | आयकर (पार्टी) | | 36,839.00 |
| 0.00 | | | | 8,800.00 |
| 0.00 | | | | 3,674.00 |
| | | **रोकड़ बाकी** | | |
| 5,000.00 | | अग्रदाय | 5,000.00 | |
| | | **बैंक में रोकड़** | | |
| 1,403,471.80 | | भारतीय स्टेट बैंक | 2,043,596.01 | |
| 3,271,534.89 | | सिंडिकेट बैंक (181) | 7,735,977.89 | |
| 2,088,910.00 | | सिंडिकेट बैंक (179) | 11,396,314.00 | |
| 5,444,828.00 | 12,213,744.69 | सिंडिकेट बैंक (178) | 3,856,890.00 | 25,037,777.90 |
| | **96,109,953.94** | **महायोग** | **105,492,822.00** | |

ह/–
(श्री पी. आर. आर. नायर)
कुलसचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

ह/–
(बी. पी. खण्डेलवाल)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

# राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

रोकड़ बाकी का विवरण (31 मार्च 2000)

| शीर्ष | अर्थशेष | अनुदान | अन्य प्राप्तिया | योग | भुगतान | शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| योजनेतर | 104.70 | 17,800,000.00 | 6,499,880.71 | 24,299,985.41 | 24,291,054.00 | 8,931.41 |
| योजना | 3,296,367.69 | 30,000,000.00 | 0.00 | 33,296,367.69 | 25,402,227.50 | 7,894,140.19 |
| प्रायोजित कार्यक्रम | 8,917,432.30 | 30,550,891.50 | 0.00 | 39,468,323.80 | 22,333,617.50 | 17,134,706.30 |
| जी एस एल आई | (160.00) | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| योग | 12,213,744.69 | 78,350,891.50 | 6,500,040.71 | 97,064,676.90 | 72,026,899.00 | 25,037,777.90 |

ह/–
(एस. आर. चौधरी)
अनुभाग अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

ह/–
(पी. आर. आर. नायर)
कुलसचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

ह/–
(बी. पी. खण्डेलवाल)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

# राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

31 मार्च, 2000 के अनुसार निर्धारित कार्यक्रमों/अध्ययनों का लेखा प्रपत्र

| क्र.सं. | कार्यक्रम/अध्ययन का नाम | अर्थशेष | प्राप्तियां | योग | व्यय | शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अनौपचारिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परियोजना–मूल्यांकन अध्ययन (शिक्षा मंत्रालय) | 14923.36 | 0.00 | 14923.36 | 0.00 | 14923.36 |
| 2. | अनौपचारिक शिक्षा सहित प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के लिए प्रायोगिक और नवाचारी कार्यक्रम और जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली | (–)13087.70 | 0.00 | (–)13087.70 | 0.00 | (–)13087.70 |
| 3. | मौजूदा सुविधाओं का अधिकाधिक प्रभावी उपयोग | 13037.00 | 0.00 | 13037.00 | 0.00 | 13037.00 |
| 4. | शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा | 1809397.14 | 3452063.00 | 5261460.14 | 4904934.00 | 356526.14 |

| क्र.सं. | कार्यक्रम/अध्ययन का नाम | अर्थशेष | प्राप्तियां | योग | व्यय | शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | उच्च शिक्षा में समता, गुणवत्ता और लागत का अध्ययन | 1043.00 | 0.00 | 1043.00 | 0.00 | 1043.00 |
| 6. | शिक्षा में प्रतिदर्श सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग | (–)26031.00 | 0.00 | (–)26031.00 | 0.00 | (–)26031.00 |
| 7. | शैक्षिक प्रौद्योगिक योजना का मूल्यांकन अध्ययन | 182136.00 | 0.00 | 182136.00 | 0.00 | 182136.00 |
| 8. | ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति का मूल्यांकन अध्ययन (मा. सं. वि. मं.) | 60645.00 | 0.00 | 60645.00 | 0.00 | 60645.00 |
| 9. | केरल में डाइट कार्यक्रम | 22417.00 | 0.00 | 22417.00 | 0.00 | 22417.00 |
| 10. | पुस्तकालयों के लिए डाइट कार्यक्रम | 91141.00 | 0.00 | 91141.00 | 9414.00 | 81727.00 |
| 11. | भारत में चुनिंदा विश्वविद्यालयों का कार्य–विवरण | 75348.00 | 0.00 | 75348.00 | 0.00 | 75348.00 |

| क्र.सं. | कार्यक्रम/अध्ययन का नाम | अर्थशेष | प्राप्तियां | योग | व्यय | शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | महिलाओं की स्थिति और निदानात्मक विश्लेषण | 127283.00 | 0.00 | 127283.00 | 0.00 | 127283.00 |
| 13. | शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों के महाविद्यालयों का विकास | 51081.00 | 0.00 | 51081.00 | 0.00 | 51081.00 |
| 14. | आधार रेखा अध्ययन–(केरल)<br>आधार रेखा अध्ययन–(कर्नाटक) | (–)40177.00 | 0.00 | (–)40177.00 | 0.00 | (–)40177.00 |
| 15. | डी आई एस ई की स्थापना और संचालन (यूनिसेफ)(डॉ. अग्रवाल) | 1088019.00 | 1129000.00 | 2217019.00 | 646995.00 | 1570024.00 |
| 16. | डाइट के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (मेनन) | 157878.00 | 127122.00 | 285000.00 | 176195.00 | 108805.00 |
| 17. | भारतीय विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान के स्तर और गुणवत्ता की स्थिति की रिपोर्ट (वि. अ. आ.) | (–)13383.00 | 0.00 | (–)13383.00 | 0.00 | (–)13383.00 |

| क्र.सं. | कार्यक्रम/अध्ययन का नाम | अर्थशेष | प्राप्तियां | योग | व्यय | शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | राष्ट्रीय अध्यापक आयोग–II | 20686.40 | 0.00 | 20686.40 | 0.00 | 20686.40 |
| 19. | डी. पी. ई. पी. की योजना और प्रबंधन में दक्षता विकास (डा. वर्गीस) | 1074300.00 | 3867000.00 | 4941300.00 | 2449575.00 | 2491725.00 |
| 20. | श्रीलंका के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों के लिए शैक्षिक प्रबंधन पर एशियाई विकास बैंक प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम | 8192.00 | 0.00 | 8192.00 | 0.00 | 8192.00 |
| 21. | उच्च शिक्षा पर उप–क्षेत्रीय कार्यशाला (अ. शै. यो. सं.–यूनेस्को–नीपा) डॉ. जी. डी. शर्मा | 30388.00 | 0.00 | 30388.00 | 0.00 | 30388.00 |
| 22. | शैक्षिक योजना, प्रबंधन, प्रशिक्षण, अनुसंधान के राष्ट्रीय संस्थानों का एशियाई नेटवर्क (5–9 दिसंबर 95) डॉ. वर्गीस | 260351.50 | 0.00 | 260351.50 | 0.00 | 260351.50 |

| क्र.सं. | कार्यक्रम/अध्ययन का नाम | अर्थशेष | प्राप्तियां | योग | व्यय | शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | शैक्षिक संकेतकों की गुणवत्ता (मा.सं.वि.मं.) संविदा सं. 840, 972, 4/159 (161) डॉ. ए. सी. मेहता. | 714.00 | 0.00 | 714.00 | 0.00 | 714.00 |
| 24. | वि. अ. आ. की ओर से महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (डॉ. श्रीमति सुधा राव) | (–)102894.00 | 602894.00 | 500000.00 | 399986.00 | 100014.00 |
| 25. | शैक्षिक रुप से पिछड़े वर्ग के लिए सघन क्षेत्र कार्यक्रम का अध्ययन (डॉ. पी. मेनन) | 49713.00 | 0.00 | 49713.00 | 0.00 | 49713.00 |
| 26. | ई–9 सम्मेलन (मा. सं. वि. मं.) | (–)6361.00 | 0.00 | (–)6361.00 | 0.00 | (–)6361.00 |
| 27. | शिक्षार्थी संप्राप्ति (दिल्ली डी.पी.ई.पी) (डॉ. अग्रवाल) | 141464.00 | 0.00 | 141464.00 | 31,773.00 | 109,691.00 |
| 28. | प्राथमिक शिक्षा आकलन और समीक्षा प्रणाली (डॉ. अग्रवाल) | 375976.00 | 0.00 | 375976.00 | 0.00 | 375976.00 |

| क्र.सं. | कार्यक्रम/अध्ययन का नाम | अर्थशेष | प्राप्तियां | योग | व्यय | शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | अं.शै.यो.सं.–पेरिस (संविदा सं. 97.30.91) डॉ. आर. गोविंद | 306907.00 | 0.00 | 306907.00 | 0.00 | 306907.00 |
| 30. | डाइट का आधारभूत और तकनीकी ढ़ाचा का मूल्यांकन | 521667.00 | 0.00 | 521667.00 | 821619.00 | (–)299952.00 |
| 31. | आई. टी. डी. ए. पाडेरू के सभी मंडलों में विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार का समवर्ती आकलन (डॉ. के. सुजाता) | 123497.00 | 0.00 | 123497.00 | 64903.00 | 58594.00 |
| 32. | आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का राष्ट्रीय मूल्यांकन (डॉ. एन. वी. वर्गीस) | 2455113.00 | 17500000.00 | 19955113.00 | 11028805.00 | 8926308.00 |
| 33. | भारत में उच्च प्राथमिक विद्यालयों (प्रा.शि.सा.) का अध्ययन (डॉ. एन. वी. वर्गीस) | 333077.00 | 100000.00 | 433077.00 | 65993.00 | 367084.00 |
| 34. | भारत में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में अ–सरकारी संगठनों की भूमिका और योगदान (क.सं.860.030.8) | 169050.00 | 0.00 | 169050.00 | 83772.00 | 85278.00 |

| क्र.सं. | कार्यक्रम/अध्ययन का नाम | अर्थशेष | प्राप्तियां | योग | व्यय | शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | शिक्षा पर एशिया क्षेत्र का सम्मेलन (क. सं. 860.031) | (–)559762.00 | 563646.50 | 3884.50 | 3884.50 | 0.00 |
| 36. | प्राथमिक विद्यालयों की आधारभूत संरचना और सुविधाओं पर आंकड़ा आधार (क. सं. 840.851.8) | 28163.00 | 0.00 | 28163.00 | 0.00 | 28163.00 |
| 37. | वि.वि.आ. कार्यक्रम के अंतर्गत संगणक अनुप्रयोग पर अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डॉ. सुधा राव) | 102943.00 | 0.00 | 102943.00 | 0.00 | 102943.00 |
| 38. | विकास प्रक्रिया में शिक्षित व्यक्तियों की भूमिका और योगदान के सवर्धन पर प्रश्नावली द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण (क. सं. 840.858.8) | 42160.00 | 0.00 | 42160.00 | 42160.00 | 0.00 |
| 39. | सबके लिए शिक्षा का आकलन (मा. सं. वि. मं.) (डॉ. गोविंद) | (–)38896.00 | 1726450.00 | 1687554.00 | 823598.00 | 863956.00 |

| क्र.सं. | कार्यक्रम/अध्ययन का नाम | अर्थशेष | प्राप्तियां | योग | व्यय | शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | संयुक्त राष्ट्र आंकड़ा कोश के लिए संकेतक विकास (यूनेस्को क. सं. 860.116.9) (डॉ. अरुण सी. मेहता) | 0.00 | 68991.00 | 68991.00 | 68991.00 | 0.00 |
| 41. | बंग्लादेश के उच्च स्तरीय शिक्षाविदों के कार्यक्रमों और यात्रा पर व्यय (यूनेस्को – ढाका) क. सं. 865.273.9 | 0.00 | 496225.00 | 496225.00 | 303830.00 | 192395.00 |
| 42. | प्राथमिक शिक्षा में समुदाय की भागीदारी और सबलीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (यूरोपियन आयोग) (8–10 दिसंबर 1999) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118630.00 | (–)118630.00 |
| 43. | सर्व शिक्षा अभियान पर परियोजना (मा.सं.वि.मं.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138784.00 | (–)138784.00 |
| 44. | उच्च शिक्षा में मानवाधिकार पर अध्ययन (मा. सं. वि. मं.) (डॉ श्रीमती सुधा राव) | 0.00 | 300000.00 | 300000.00 | 3776.00 | 296224.00 |

| क्र.सं. | कार्यक्रम/अध्ययन का नाम | अर्थशेष | प्राप्तियां | योग | व्यय | शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | कार्यान्वयन की कार्यनीति पर विशेष बल के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर कार्यशाला (15–19 नवंबर 1999 जलाली) | 0.00 | 146000.00 | 146000.00 | 146000.00 | 0.00 |
| 46. | उच्च प्रथमिक शिक्षा पर कार्यशाला डॉ (श्रीमती सुधा राव) | 0.00 | 471500.00 | 471500.00 | 0.00 | 471500.00 |
| **योग** | | **8938118.70** | **30550891.50** | **39489010.20** | **22333617.50** | **17155392.70** |

**विशिष्ट परियोजना के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हुए निर्धारित प्रयोजनों पर प्राप्त अनुदान का उपयोग किया गया है।

ह/–
(एस.आर.चौधरी)
अनुभाग अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

ह/–
(पी. आर. आर. नायर)
कुल सचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

ह/–
(बी. पी. खण्डेलवाल)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

# राष्ट्रीय शैक्षिक योजना

1999–2000 का

| 1998-1999 | व्यय | 1999-2000 |
|---|---|---|
| 5,264,253.00 | अधिकारियों का वेतन | 4,827,437.00 |
| 5,636,131.00 | संस्थागत वेतन | 7,167,472.00 |
| 9,975,369.00 | भत्ते तथा मानदेय, समयोपरि भत्ता, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अवकाश वेतन तथा पेंशन सहित | 7,647,142.00 |
| 0.00 | यात्रा भत्ता | 0.00 |
| 18,95,702.00 | पेंशन तथा उपदान | 3,290,336.00 |
| 1,497,843.00 | पी.एफ. नियोक्ता का अंशदान, अंशदान के खाते में शोधित/देय पी. एफ. पर ब्याज | 2,005,733.00 |
| 270,928.00 | बोनस | 254,200.00 |

## और प्रशासन संस्थान

आय–व्यय लेखा (31 मार्च 2000)

| 1998-1999 | आय | 1999-2000 | |
|---|---|---|---|
| 18,091,980.00 | भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान | 47,800,000.00 | |
| 28,349,736.00 | (अ) धनदाता एजेंसियों से प्राप्त अनुदान | 30,550,891.50 | |
| | **पूंजीकृत अनुदान को घटाकर** | | |
| 464,404.00 | फर्नीचर व साज–समान | 1,045,350.00 | |
| 5,294,452.00 | कार्यालय के अन्य उपकरण | 2,826,743.00 | |
| 1,482,798.00 | | 156,135.00 | |
| 0.00 | स्टाफ कार/टाईप राइटर्स | 0.00 | 43,555,933.00 |
| 514,164.00 | पुस्तकाललयों की पुस्तकें | 371,974.00 | 30,394,756.50 |
| | **छात्रावास किराया** | | |
| 1,487,208.00 | वर्ष के दौरान प्राप्तियां | 2,019,095.00 | |
| 31,650.00 | वर्ष के दौरान प्रोदभूत प्राप्तियां | 2,050.00 | |
| (42,000.00) | पिछले साल को घटाकर | 31,650.00 | 1,989,495.00 |
| | **प्राप्त ब्याज** | | |
| 1,428,197.00 | निवेश पर | 102,395.00 | |
| 81,190.00 | ब्याजवाली पेशगियों पर | 268,650.19 | 371,045.19 |

| 1998-1999 | व्यय | 1999-2000 |
|---|---|---|
| 69,879.00 | अध्येता वृत्ति और पुरस्कार | 392,523.00 |
| 247,245.00 | प्रकाशन व्यय | 259,543.00 |
| 4,946,116.45 | अकादमिक गतिविधियां | 6,936,096.50 |
| 629,781.00 | अनुसंधान अध्ययन | 891,416.00 |
| 5,582,489.00 | अन्य प्रभार (आवर्ती) | 7,592,102.00 |
| | (कार्यालय व्यय) | 41,264,000.50 |
| 27,844,504.00 | धन प्रदान करने वाली एजेंसी का व्यय | 22,177,482.50 |
| 0.00 | व्यय से अधिक आय | 8,247,011.21 |
| 505,232.00 | व्यय से अधिक आय (धनदाता एजेंसी) | 8,217,274.00 |
| **64,365,472.45** | **योग** | **79,905,768.21** |

ह./–
(एस. आर. चौधरी)
अनुभाग अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

| 1998-1999 | आय | 1999-2000 | |
|---|---|---|---|
| | **विविध प्राप्तियां** | | |
| 15,282.00 | रायल्टी | 30,039.50 | |
| 68,325.00 | मकान किराया (लाइसेंस शुल्क) | 83,024.00 | |
| 6,129.00 | पानी का शुल्क | 6,655.00 | |
| 6,836,277.00 | विविध प्राप्तियां | 232,044.00 | |
| 326,000.00 | अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री | 128,565.00 | |
| 0.00 | कार्यक्रम प्राप्तियां | 2,839,997.00 | |
| 0.00 | पेंशन हितलाभ | 2,659.00 | |
| 112,898.00 | अवकाश वेतन तथा पेंशन | 162,110.00 | 3,485,093.50 |
| | **भविष्य निधि निवेश पर ब्याज** | | |
| 411,392.00 | वसूली | 109,445.02 | 109,445.02 |
| | वर्ष के लिए प्रोद्भोत | | |
| 7,161,208.41 | आय से अधिक व्यय | | 0.00 |
| **64,365,472.45** | | | **79,905,768.21** |

ह./–
(पी. आर. आर. नायर)
कुलसचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

ह./–
(बी. पी. खण्डेलवाल)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

# राष्ट्रीय शैक्षिक योजना

तुलन पत्र

## दायित्व

| | | |
|---|---|---|
| **पूंजीकृत अनुदान** | | |
| पिछले तुलन=पत्र के अनुसार शेष राशि | 68,144,025.17 | |
| वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि | 4,400,202.00 | |
| परिवर्धन (समायोजन द्वारा) | 5,700,868.00 | |
| बट्टे खाते में डाली गई पूंजीकृत निवेश को घटाकर | 1,592,327.00 | 76,652,768.17 |
| **उपहार और दान** | | |
| पिछले तुलन=पत्र के अनुसार शेष राशि | 165,487.76 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन/प्राप्तियां | 13,924.00 | 179,411.76 |

# और प्रशासन संस्थान

(31 मार्च 2000)

## परिसंपत्तियां

| | | |
|---|---|---|
| **भूमि तथा भवन** | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि | 35,900,979.55 | |
| वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि | 5,700,868.00 | 41,601,847.55 |
| **उपकरण तथा मशीनरी, फर्नीचर व साज-समान टाइपराइटर, कंप्यूटर, स्टाफ कार इत्यादि** | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि | 27,482,360.00 | |
| वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि | 4,028,228.00 | |
| बट्टे खाते को घटाकर | 1,533,558.00 | 29,977,030.00 |
| **पुस्तकालय की पुस्तकें** | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि | 4,926,173.38 | |
| वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि | 371,974.00 | |
| उपहार और दान के द्वारा बढ़ोत्तरी | 13,924.00 | |
| बट्टे खाते की पुस्तकों की कीमत घटाकर | 58,769.00 | 5,253,302.38 |
| **धनदाता एजेंसियों को अव्ययित देय राशि (समनुदेशित कार्यक्रम)** | | |
| वसूली योग्य राशि | 656,405.70 | 656,405.70 |
| मिश्रित पेशगी (एन.सी.टी. II) | 20,686.40 | 20,686.40 |
| **भविष्य निधि निवेश** | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि | 13,100,000.00 | |
| वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि | 4,550,000.00 | 17,650,000.00 |
| **के.लो.नि. विभाग के पास जमा** | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि | 5,860,756.00 | |
| वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि | 3,202,124.00 | |
| संशोधन जोड़कर | 54,803.00 | |
| समायोजन घटाकर | 5,700,868.00 | 3,416,815.00 |
| **डी. डी. ए. के पास जमा राशि** | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि | 375,000.00 | |
| वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि | 0.00 | |
| समायोजन घटाकर | 0.00 | 375,000.00 |

देयताएं

| | | |
|---|---|---|
| **व्यय से अधिक आय** | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि | 11,012,672.39 | |
| वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि | 8,247,011.21 | |
| संशोधन जोड़कर | 54,803.00 | |
| समायोजित घटाकर | 5,700,868.00 | |
| आय से अधिक व्यय | 0.00 | 13,613,618.60 |
| प्रायोजक एजेंसियों को वापिस किए जाने वाला अव्ययित शेष (निर्धारित कार्यक्रम) | | |
| पिछले तुलन=पत्र के अनुसार शेष राशि | 8,938,118.70 | |
| वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि | 30,550,891.50 | |
| संशोधन जोड़कर | 99,039.70 | |
| वर्ष के दौरान व्यय को घटाकर | 22,333,617.50 | |
| अधिक व्यय को जोड़कर | 557,366.00 | 17,811,798.40 |

## परिसंपत्तियां

| | | |
|---|---|---|
| **कर्मचारियों को पेशगी/अन्य पेशगी** | | |
| **वसूली योग्य पेशगियां** | | |
| त्यौहार पेशगी | 89,400.00 | |
| मोटर कार पेशगी | 212,000.00 | |
| स्कूटर पेशगी | 193,071.00 | |
| साईकिल पेशगी | 3,900.00 | |
| पंखा पेशगी | 1,100.00 | |
| भवन निर्माण पेशगी | 810,300.00 | |
| कंप्यूटर पेशगी | 22,685.00 | |
| बाढ़ पेशगी | 7,500.00 | 1,339,956.00 |
| **चिकित्सा अग्रिम** | 163,350.00 | 163,350.00 |
| **विविध पेशगियां (नीपा)** | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि | 318,075.00 | |
| वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि | 0.00 | |
| समायोजन घटाकर | 875.00 | 317,200.00 |
| **अधिक पेशन भुगतान की वूसली** | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि | 38,404.00 | |
| वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि | 0.00 | |
| वर्ष के दौरान प्राप्त राशि को घटाकर | 7,937.00 | 30,467.00 |
| **छात्रावास से प्राप्त आय** | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि | 32,525.00 | |
| वर्ष के दौरान बढाई गई राशि | 2,050.00 | |
| प्राप्तियां घटाकर | 31,650.00 | 2,925.00 |
| **विभिन्न देनदार** | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि | 89,334.00 | |
| वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि | 0.00 | |
| समायोजन घटाकर | 0.00 | 89,334.00 |
| **धन प्राप्ति** | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि | 160.00 | |
| वर्ष के दौरान बढाई गई राशि | 0.00 | |
| वर्ष के दौरान प्राप्त राशि को घटाकर | 160.00 | 0.00 |

## देयताएं

| | | |
|---|---|---|
| **भविष्यनिधि** | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि | 14,756,181.00 | |
| वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि | 7,992,601.00 | |
| वर्ष के दौरान निकाली गई राशि | 3,041,217.00 | 19,707,565.00 |
| **विभिन्न लेनदार** | | |
| पिछले तुलन=पत्र के अनुसार शेष राशि | 18,500.00 | |
| वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि | 11,000.00 | |
| वर्ष के दौरान निकाली गई राशि को घटाकर | 5,000.00 | 24,500.00 |
| **योग** | | **127,989,661.93** |

ह/–
(एस. आर. चौधरी)
अनुभाग अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

परिसंपत्तियां

| | | |
|---|---|---|
| **शेष रोकड़** | | |
| हस्तगत रोकड़ | 0.00 | |
| अग्रदाय | 5,000.00 | |
| बचत खाता (एस. बी. आई.) | 2,043,596.01 | |
| बचत खाता (सिंडिकेट बैंक) | 7,735,977.89 | |
| बचत खाता (सिंडिकेट बैंक) | 11,396,314.00 | |
| बचत खाता (सिंडिकेट बैंक) | 3,856,890.00 | |
| जी. पी. एफ./सी. पी. एफ लेखा | 2,057,565.00 | 27,095,342.90 |
| | | **127,989,661.93** |

ह./–
(पी. आर. आर. नायर)
कुलसचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

ह./–
(बी. पी. खण्डेलवाल)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

# राष्ट्रीय शैक्षिक योजना

| 1998-99 | [illegible] | 1999-2000 |
|---|---|---|
| 1,150,510.00 | अर्थशेष | 1,656,181.00 |
| 4,876,673.00 | जी.पी.एफ. अंशदान और पेशगियों की वापसी | 5,725,558.00 |
| 141,480.00 | सी.पी.एफ. अंशदान और पेशगियो की वापसी | 261,310.00 |
| 1,260,505.00 | जी.पी.एफ. पर अदा किया गया ब्याज | 1,684,574.00 |
| 146,576.00 | सी.पी.एफ. पर अदा किया गया ब्याज | 180,724.00 |
| 23,220.00 | सरकारी अंशदान | 95,955.00 |
| 38,711.00 | सरकारी अंशदान पर ब्याज | 44,480.00 |
| **7,637,675.00** | **योग** | **9,648,782.00** |

ह/–
(एस.आर.चौधरी)
अनुभाग अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

## और प्रशासन संस्थान

| [redacted] | [redacted] | [redacted] |
|---|---|---|
| 2,910,638.00 | जी.पी.एफ. पेशगियों और निकासी | 3,041,217.00 |
| 270,856.00 | सी.पी.एफ. पेशगियों और निकासी | 0.00 |
| 2,800,000.00 | 1999 – 2000 में किया गया निवेश | 4,550,000.00 |
| 1,656,181.00 | अंत शेष | 2,057,565.00 |
| **7,637,675.00** | **योग** | **9,648,782.00** |

ह/–
(पी. आर. आर. नायर)
कुल सचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

ह/–
(बी. पी. खण्डेलवाल)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

# राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान की लेखा परीक्षा रिपोर्ट : 1999-2000

## प्रस्तावना

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) पहले शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालेज के नाम से जाना जाता था। मई 1979 में इसकी स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत इसे पंजीकृत किया गया। संस्थान का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक योजना और प्रशासन के विविध क्षेत्रों में अध्ययन, नए विचारों और तकनीकों के अर्जन, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए सेवाकालीन, सेवापूर्व प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशाला और संगोष्ठियां आदि आयोजित करके, शैक्षिक योजना और प्रशासन के विविध क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए अनुदान देकर, अनुसंधान को बढ़ावा देकर और समन्वय करके तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संबंधित साहित्य, पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करके, और उन्हें प्रकाशित करके शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता का एक शीर्षस्थ संस्थान बने रहना है।

### (ii) लेखा परीक्षा का कार्य

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिनियम 1971 की धारा 20(1) (कार्य, अधिकार और सेवाशर्तें) के तहत पांच वर्षों (1996-97 से 2000-2001) के लिए संस्थान की लेखा परीक्षा सुपुर्द की गई है।

### 2. वित्त

संस्थान को मुख्यतः केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान संस्थान को भारत सरकार से 478.00 लाख रुपए (300.00 लाख योजनागत और 178.00 लाख रुपए योजनेतर मद में) का अनुदान प्राप्त हुआ।

## 3. लेखा पर टिप्पणियां

### 3.1 प्राप्ति और भुगतान का अधिक आकलन

प्राप्ति और भुगतान लेखा 1999-2000 में चिकित्सा अग्रिम (अदायगी) के शीर्ष के अंतर्गत रु. 1.09 लाख की राशि प्राप्ति के रूप में दिखाई गई है। यद्यपि बही खाता से पता चला कि वास्तव में यह अदायगी नहीं थी बल्कि वर्ष के दौरान चिकित्सा अग्रिम के भुगतान के साथ इसे समायोजित किया गया। रु. 1.09 लाख की राशि को प्राप्तियां और भुगतान लेखा के भुगतान स्तंभ में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रु. 6.20 लाख में भी शामिल किया गया। प्राप्तियां और भुगतान लेखा में अग्रिम के साथ राशि का समायोजन दिखाने से लेखा में 1.09 लाख की राशि प्राप्तियां और भुगतान में अधिक दिखायी गयी क्योंकि यह राशि नगद रूप में प्राप्त नहीं की गई थी। इसी प्रकार की त्रुटि पिछली लेखा रिपोर्ट में भी चिन्हित की गई थी।

### 3.2 प्राप्ति और भुगतान का अधिक आकलन

(अ) **त्यौहार पेशगी :** प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार संस्थान ने रु 1.25 लाख का त्यौहार अग्रिम दिया तथा रु. 1.11 लाख की वसूली की जबकि ब्रॉड–शीट में त्यौहार अग्रिम का रु 1.25 लाख और रु. 1.11 लाख की राशि को भुगतान और वसूली के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार प्राप्ति और भुगतान में 0.008 लाख रुपये अधिक दिखाया गया।

(ब) **कार पेशगी :** प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार रु 2.60 लाख रुपये कार पेशगी के रूप में दिये गये तथा रु. 0.80 लाख रुपये वसूले गये जबकि ब्राड–शीट में रु 2.60 लाख रुपये कार पेशगी और रु. 0.79 लाख वसूली के रूप में दर्शाये गये हैं। इस प्रकार प्राप्ति और भुगतान में रु 0.004 लाख अधिक दिखाया गया।

(4) **बकाया अग्रिम :** तुलन पत्र में – विविध पेशगी (एन.सी.टी.–II) शीर्ष के अंतर्गत 0.21 लाख रुपये दर्शाये गये हैं। यह राशि सन् 1983 से वसूल की जानी थी। 1983 में राष्ट्रीय शिक्षक आयोग–II (केन्द्रीय तकनीकी विभाग) परियोजना की समाप्ति के बाद प्रतिदेय शेष के रुप में रु 0.10 लाख बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल और रु 0.10 लाख रुपये कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता से वसूल करना था।

बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ने राशि वि.अ. आयोग को अनजाने में यह राशि भेज दी जिसका पता नहीं चल सका, जबकि कोलकाता विश्वविद्यालय से प्राप्त डिमाण्ड ड्राफ्ट समय–सीमा निकलने के बाद प्राप्त हुआ।

**5. व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण**

बही खाता दर्शाता है कि संस्थान ने ए.सी. लगवाने के लिये रु 0.11 लाख का भुगतान किया। यह भुगतान विविध भुगतान शीर्ष के अंतर्गत किया गया। यह राशि स्थापना प्रभार, पूंजीगत वस्तु की लागत के रूप में, पूंजी में परिणित करके संपत्ति की लागत में जोड़ी जानी चाहिये थी। इस त्रुटिपूर्ण व्यय वर्गीकरण के कारण रु 0.11 लाख की परिसंपत्तियों का उल्लेख नहीं हुआ और राजस्व व्यय में इतनी ही राशि अधिक हो गई।

**6. व्यय का मिश्रण**

प्राप्ति और भुगतान लेखा में "यात्रा भत्ता" शीर्ष के अंतर्गत 12.48 लाख रुपये (गैर–योजना : 0.28 लाख और योजना 6.10 लाख तथा 6.09 लाख) प्रदर्शित है। यह राशि आय और व्यय लेखा में शैक्षिक गतिविधियां शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। आय और व्यय लेखा में यात्रा व्यय के अंतर्गत व्यय शून्य दिखाया गया है। इससे संस्थान के लेखे की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं होती है।

**7. परिसंपत्तियों का अधिक आकलन**

तुलन–पत्र में साजो–सामान, मशीन, फर्नीचर शीर्ष के अंतर्गत 40.28 लाख रुपये की स्थायी परिसंपत्तियों का परिवर्धन दिखाया गया है। जबकि स्टॉक/परिसंपत्ति रजिस्टर और बहीखाता से पता लगा कि 16.20 लाख रुपये की निम्नांकित परिसंपत्तियां इस वित्तीय वर्ष के बाद प्राप्त हुई थी :

| क्र.स. | मद | राशि (रु.) | मदों की प्राप्ति की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. | एयर कंडीशनर्स | 2,24,460.00 | 11.4.2000 |
| 2. | फर्नीचर | 1,00,716.00 | 24.6.2000 |
| 3. | यू. पी. एस. | 1,86,300.00 | 11.5.2000 |
| 4. | एयर कंडीशनर्स | 1,43,640.00 | 20.4.2000 |
| 5. | कंप्यूटर | 3,40,200.00 | 10.5.2000 |
| 6. | कंप्यूटर | 4,25,250.00 | 10.5.2000 |
| 7. | कंप्यूटर | 85,050.00 | 19.4.2000 |
| 8. | कंप्यूटर | 16,536.00 | 4.4.2000 |
| 9. | प्रिंटर | 13,000.00 | 27.5.2000 |
| 10. | प्रिंटर | 85,280.00 | 27.5.2000 |
| | **योग** | **16,20,432.00** | |

अतः परिसंपत्तियों का 16.20 लाख रुपये की राशि अधिक दर्शायी गई है।

**8. विविध देनदार**

विविध देनदारों से संबंधित सहायक रिकार्ड/स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराये गये, इसलिये इन्हें सत्यापित नहीं किया जा सका :

8.1 रजिस्टर में लेखा अधिकारी केन्द्रीय तार कार्यालय, नई दिल्ली के पास 0.19 लाख रुपये की राशि प्रतिभूति जमा के रूप में दर्शायी गई है। यह राशि सन 1980–81 से 1988–89 की अवधि से संबंधित है। तदापि, संस्थान ने न ही कोई रसीद या देनदार की कोई स्वीकृति पत्र प्रस्तुत की जिससे यह स्थापित हो सके कि राशि, लेखा अधिकारी, केंद्रीय तार घर कार्यालय, नई दिल्ली के पास बकाया है।

8.2 'एम.टी.एन.एल' के पास 'तत्काल' सुविधा के अंतर्गत दिनांक 25.10.96 को 0.30 लाख रुपया बकाया राशि के रूप में दर्शाया गया है। संस्थान यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि गत 4 वर्षों से इस राशि को टेलीफोन बिल में क्यों नहीं समायोजित किया गया।

**9. सामान्य**

**9.1 परिसंपत्तियों का अवमूल्यन**

परिसंपत्ति लेखा में अर्जित परिसंपत्ति का खाता मूल्य दर्शाया जाता है। इसमें बेकार, अनुपयोगी और अनुपयोगी घोषित परिसंपत्तियों को निकाला नहीं जाता है और इसके सापेक्ष पूंजीगत लेखा में उसके अवमूल्यन को नहीं दिखाया जाता है। इसके फलस्वरूप पूंजी और परिसंपत्ति लेखा में अपेक्षाकृत अधिक परिसंपत्ति का उल्लेख किया गया है। इससे इसका सही विवरण नहीं मिल रहा है।

**9.2 अव्ययित अनुदान**

संस्थान के पास दिनांक 31.3.99 तक कुल 3296472.39 (योजना : 3296367.69 रुपये तथा गैर योजनाः 104.70 लाख रुपये) अव्ययित अनुदान था जिसे मंत्रालय की अनुमति/अनुमोदन के बगैर अगले वर्ष में अग्रेनी किया गया।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.11.2000

महानिदेशक, लेखा परीक्षा
केंद्रीय राजस्व

# लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रगित और भुगतान लेखा/आय और व्यय लेखा तथा 31 मार्च 2000 के तुलन=पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभियुक्तियों के आधार पर अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में तथा मेरी जानकारी और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण एवं संस्थान की बहियों में दर्शाए गए विवरणों के अनुसार ये लेखे और तुलनपत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं तथा संस्थान के कार्यकलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 27.11.2000

ह/–

महानिदेशक, लेखा परीक्षा